फिर पेपर लीक

नीट परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र के लीक होने की घटना जितनी शर्मनाक है, उससे अधिक यह दर्दनाक है। शर्मनाक इसलिए कि परीक्षा के आयोजन से जुड़ा तंत्र एक बार फिर नाकाम हो गया है और दर्दनाक इस मायने में कि लगभग 23 लाख किशोर मायूसी के शिकार हो गए हैं। उनकी महीनों-बरसों की आस पर फिलहाल पानी फिर गया है। इनमें से कई बेहद तंगहाली में डॉक्टर बनने का सपना संजोए बैठे होंगे। कई अभिभावकों ने होनहार संतान की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया होगा। उनके लिए परीक्षा का रद्द होना किसी वज्रपात से कम नहीं है। हालांकि, नीट परीक्षा की आयोजक संस्था 'एनटीए' ने कहा है कि जल्द ही दोबारा परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा रद्द करने का कदम होनहार नौनिहालों के हक में ही उठाया गया है। निस्संदेह, धांधली की किसी आशंका को खत्म करने के लिए दोबारा परीक्षा ही उचित रास्ता था, मगर सवाल यही है कि टूटे हुए मन से दोबारा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थी इस पर अब कितना यकीन करेंगे? क्या वे उसी उत्साह से फिर से जुट सकेंगे? हमारी नियामक एजेंसी को किशोर परीक्षार्थियों के नजरिये से भी गौर करना चाहिए।

पेपर लीक की जांच का जिम्मा सीबीआई को तब सौंपा गया, जब कम से कम 48 घंटों तक यह मामला मुख्यधारा के अखबारों व सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरता रहा और दिग्गज विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाने नहीं शुरू कर दिए। क्या इस धत्कर्म में शामिल लोग तब तक भूमिगत नहीं हो गए होंगे? शुरू में इस मामले की जड़ चुरू (राजस्थान) में दिख रही थी, मगर बाद में जिस तरह से इस गैंग के हाथ हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य प्रांतों तक फैले बताए जाने लगे, उसे देखते हुए सीबीआई के लिए पूरे मामले का उद्भेदन बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। नासिक पुलिस ने राजस्थान पुलिस से मिली सूचनाओं के आधार पर जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, वह अपनी वेशभूषा और हेयर स्टाइल वगैरह बदल चुका था। बहरहाल, इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करते हुए दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा सिर्फ देश में परीक्षा तंत्र की शुचिता स्थापित करने के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपने बच्चों का इसमें भरोसा बहाल करने के लिए भी जरूरी है।

धांधली को मिटाने के लिए परीक्षा रद्द करना ही उचित रास्ता था। प्रश्न यह है कि टूटे हुए मन से दोबारा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थी अब इस पर कितना यकीन करेंगे?

यह अच्छी बात है, एनटीए ने साफ किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और न ही परीक्षा केंद्र बदले जाएंगे। संस्था अपने संसाधन से ही दोबारा परीक्षा लेगी। इस पेपर लीक कांड ने एक बार फिर इस तथ्य को रेखांकित किया है कि देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं की पवित्रता को लेकर गंभीर प्रयासों की कितनी जरूरत है। तब तो और, जब देश में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और हमें काबिल श्रम-बल की सख्त जरूरत है। जाहिर है, परीक्षा प्रणाली में यह शुचिता तभी आएगी, जब अंदर-बाहर के दोषियों को दंडित करने की सख्त नजीर पेश की जाएगी। हम भूले नहीं हैं कि महज दो साल पहले नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटना घटी थी और अब फिर से इसकी पुनरावृत्ति यही बताती है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग दुस्साहस की सीमा पार कर गए हैं। इसलिए सरकार को सीबीआई को एक तय सीमा के भीतर मामले के खुलासे के लिए कहना चाहिए और पूरी पारदर्शिता बरतते हुए आरोपियों को कठघरे में खड़ा करना चाहिए, ताकि उन लाखों परीक्षार्थियों को इंसाफ मिले, जो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले 13 मई, 1951

करदाताओं तक पहुंचें

नई दिल्ली, 12 मई। आज आयकर कमिश्नरों का त्रिदिवसीय सम्मेलन यहां शुरू हो गया, जिसका उद्देश्य आयकर की बकाया रकम वसूल करने के लिए विशेष आंदोलन शुरू करने के तरीकों पर विचार करना है। वित्त राज्य मंत्री श्री महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे। 30 सितंबर, 1950 तक आयकर की बकाया रकम 117 करोड़ रुपये बताई जाती है। इसमें से 23 करोड़ की रकम ऐसी है, जो फौरन वसूल हो सकती है।

वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि देशमुख ने सम्मेलन में भाषण करते हुए यह आशा प्रकट की कि इस सम्मेलन में ऐसे क्रियात्मक सुझाव पेश किये जायेंगे, जिनसे आगामी 6 महीनों में आयकर की बकाया रकम बहुत कम रह जाये। आयकर विभाग का वह कार्य सचमुच सराहनीय है, जिसके अनुसार 1950-51 में 7.20 के स्थान पर 8.60 लाख मामलों का तस्फिया कर दिया गया। श्री देशमुख ने कहा कि आयकर विभाग की जनशक्ति में सुधार नहीं हुआ। फिर भी यदि कर लगान के तरीकों में कुछ ढील कर दी जाये और हिसाब-किताब के छोटे-छोटे मामलों में जितना समय बर्बाद किया जाता है, यदि उतना समय करदाता के साथ न्यायोचित बातचीत करने में लगाया जाये, तो अपेक्षाकृत कम समय में अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। आपने कहा कि आयकर विभाग की सफलता इस चीज पर निर्भर करती है कि उसके जनता के साथ सम्बन्ध अच्छे हैं या नहीं। यदि छोटा करदाता संतुष्ट है और उससे विभाग को कुछ कम रकम मिलती है तो उसकी यह बहुत बड़ी सफलता है।

श्री देशमुख ने कहा कि हम बहुत सुनते हैं कि काफी लोग ऐसे हैं जो सचाई के साथ यह प्रकट करने को तैयार हैं कि वे अब तक कितना आयकर बचा पाये हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने तो नहीं आया। इतना तो जरूर हुआ है कि आयकर विभाग को किसी व्यक्ति के बारे में कोई सुराग मिल गया हो और शेष बातें उसने स्वयं प्रकट कर दी हो। ऐसे मामलों में रियायती दरों पर कर वसूली का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका अभिप्राय तो बेईमानी को प्रोत्साहन देना होगा। ऐसा व्यक्ति तो पहले ही सरकार से पैसा बचा चुका होगा। हां, इतना जरूर हो सकता है कि यदि ऐसा व्यक्ति पूरी-पूरी जानकारी दे दे, तो उसे किसी किस्म की सजा न दी जाये।

परीक्षा लेने वाले कब तक फेल होंगे

नीट पेपर लीक से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन पर फिर प्रश्नचिह्न लग गया है। क्या हम कभी अपनी परीक्षा प्रणाली को अभेद्य किले की तरह मजबूत बना पाएंगे?

यहां स्कैन करें

हरिवंश चतुर्वेदी | महानिदेशक, आईआईएलएमबीएस

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए इसी 3 मई को नीट (यूजी) परीक्षा हुई थी, जिसमें देश के लगभग 22.79 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। पेपर लीक होने के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और जल्द ही नई परीक्षा कराने का वादा भी किया है। इस प्रकरण ने मेडिकल, इंजीनियरिंग व सीयूईटी की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन पर एक बार फिर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। क्या हम कभी अपनी परीक्षा प्रणाली को एक अभेद्य किले की तरह मजबूत बना पाएंगे कि कभी पेपर लीक न हो और छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े?

यह स्वाभाविक है कि जब मेडिकल (नीट) और इंजीनियरिंग (जेईई) की परीक्षाओं में पेपर लीक होने की कोई घटना घटती है या फिर उनको लेकर कोई अफवाह भी फैलती है, तो युवा वर्ग में तीखी प्रतिक्रिया होती है। ऐसी घटनाएं हमारी प्रवेश परीक्षा प्रणाली में अनास्था और अविश्वास पैदा करती हैं। उन 22.79 लाख परीक्षार्थियों की मनःस्थिति के बारे में सोचिए, जो 3 मई को देश के 551 और विदेश के 14 शहरों के 5,400 केंद्रों पर पहुंचे थे।

जैसे कि ब्योरे हैं, राजस्थान पुलिस को इस बात की शिकायत मिली थी कि नीट परीक्षा से 42 घंटे पहले वाट्सएप पर एक गेस पेपर को वितरित होते देखा गया, जिसमें बहुवैकल्पिक 410 प्रश्न और उत्तर दिए हुए थे। इस गेस पेपर के 100 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए सवालों से हूबहू मिलते पाए गए हैं। पुलिस की जांच से मालूम पड़ा कि इन 100 प्रश्नों को हल करने से कुल 720 में से 600 अंकों का जुगाड़ हो जाता है।

राजस्थान का कोटा शहर जेईई कोचिंग के अत्यधिक व्यवसायीकरण और किशोर छात्रों की आत्महत्याओं के कारण चर्चाओं में आता रहा है, लेकिन नीट के प्रश्नपत्र को लीक करने वाले गेस पेपर की कहानी राजस्थान के चुरु और सीकर जैसे शहरों से

शुरू हुई, जहां गेस पेपर को पांच लाख से तीस हजार रुपये तक में बिकते हुए देखा गया। गौरतलब है, वर्ष 2024 में भी नीट की परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने का प्रकरण सामने आया था, जिसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी असंतोष देखने को मिली। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी।

साल 2017 से पहले तक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं का संचालन सीबीएसई, एआईसीटीई और यूजीसी द्वारा किया जाता था। साल 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रोग्राम और कार्यक्रम 1992 में प्रभाव में आया, उसमें विविध प्रकार की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाने की सिफारिश की गई थी। इसी के अनुरूप साल 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई। 2024 में नीट परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण के बाद एनटीए के नेतृत्व में बदलाव के साथ-साथ हरेक स्तर पर टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा पेपर लीक को रोकने के इंतजाम किए गए थे।

राजस्थान पुलिस द्वारा नीट परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत दर्ज किए जाने के बाद एनटीए ने एक वक्तव्य जारी करके मीडिया को उन तमाम इंतजामों की विस्तार से जानकारी दी थी कि तय प्रोटोकॉल के अनुसार इस बार पेपर लीक न हो पाने के पुख्ता प्रबंध किए गए थे और हरेक स्तर पर जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी सर्विलांस और 5जी जैमर्स के प्रयोग किए गए थे। फिर भी नीट का पेपर लीक हो गया। साल 2024 में नीट पेपर की खुली बिक्री बिहार में पाई गई थी और अब राजस्थान में यही बात पाई गई है।

ऐसे में, सवाल उठना लाजिमी है। आखिर क्या कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित एनटीए जैसी एजेंसी के तमाम प्रयासों के बावजूद फिर नीट का पेपर लीक हो गया? क्या एनटीए के पुख्ता प्रोटोकॉल को भी पेपर लीक करने वाली ताकतों ने नाकामयाब नहीं कर दिया? क्या यह हमारी राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए एक गंभीर सबक नहीं होना चाहिए कि अब नीट, जेईई और सीयूईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के संचालन का कोई ऐसा नया मॉडल ढूंढ़ा जाए, जिसमें बहु-वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ जांच प्रणाली के मौजूदा जोखिम से छुटकारा मिल सके?

दुनिया के कई बड़े देशों में उच्च शिक्षा व पेशेवर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। छोटी-मोटी परेशानियां सभी देशों में देखी जाती हैं, मगर हमारे देश जैसी पेपर लीक की दुस्साहसिक घाटनाएं शायद ही अमेरिका, चीन और यूरोप में देखने को मिलें?

उच्च शिक्षा व आबादी के मामले में भारत और चीन, दोनों लगभग बराबर की स्थिति में हैं। चीन में 'गाओकाओ' नामक राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें 1.3 से 1.5 करोड़ परीक्षार्थी भाग लेते हैं। साल 2025 में 1.34 करोड़ परीक्षार्थियों ने इसमें भाग लिया था। जिन दिनों पूरे चीन में गाओकाओ परीक्षाएं होती हैं, उन दिनों वहां रेल, बसों और हवाई यात्राओं में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल होता है। क्या चीन की इस सबसे विशाल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं? वहां अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि छोटी-मोटी कमियां और गड़बड़ियां देखी गई हैं। इस परीक्षा में कोई व्यक्ति किसी कदाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसे सात वर्षों की न्यूनतम सजा दी जाती है। दूसरे, चीन में भी आधुनिक टेक्नोलॉजी और एआई के उपयोग से पेपर लीक की सभी आशंकाओं को रोका जाता है।

निस्संदेह, रद्द परीक्षा जल्द ही आयोजित कर ली जाएगी, क्योंकि प्रवेश परीक्षाएं हमारी युवा पीढ़ी को अपना भविष्य बनाने का अवसर देती हैं। इन प्रवेश परीक्षाओं में सीट हासिल करना आसान नहीं होता। मुश्किल से पांच से दस प्रतिशत परीक्षार्थी कामयाबी के निकट पहुंच पाते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि बेईमानी और धन द्वारा इनमें सीट हासिल करने का कारोबार कई दशकों से जारी है? ठगों, दलालों और बिचौलियों का एक वर्ग हर साल करोड़ों रुपये की कमाई करके मासूम किशोरों और उनके परिवार को लूटते रहते हैं? क्या एक ऐसी परीक्षा प्रणाली नहीं तलाशी जा सकती, जिसमें कम से कम पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जजों की संख्या बढ़ाकर कार्य-संस्कृति भी सुधारें

यहां स्कैन करें

संजय पारिख | वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं को सुनने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि काश, जजों की नियुक्ति भी चुनाव आयुक्तों वाली तेजी से होती। बेशक, यह तंज में की गई टिप्पणी प्रतीत होती है, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ हैं। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों तक न्यायाधीशों के खाली पद आज की सच्चाई है। इसी पखवाड़े सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 38 जरूर कर दी गई, लेकिन न्यायिक नियुक्ति मौजूदा समय का एक बड़ा मसला है।

राज्यसभा में सरकार ने खुद माना है कि 1 दिसंबर, 2025 तक देश की निचली अदालतों में जजों के 4,855 पद रिक्त थे, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1,055 रिक्तियां थीं, जबकि गुजरात 535 रिक्तियों के साथ दूसरे स्थान पर था। इसी तरह, उच्च न्यायालयों में भी जजों के 297 पद खाली थे। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय की बात है, तो वहां दिसंबर तक महज एक पद खाली था, लेकिन अप्रैल में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की सेवानिवृत्ति के बाद कुल दो पद खाली हो गए। अगले महीने न्यायमूर्ति पंकज मित्तल भी 65 साल के हो रहे हैं।

इन सबका लंबित मुकदमों पर असर पड़ना स्वाभाविक है। आंकड़ों की मानें, तो सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर, 2025 तक 90,694 मामले लंबित थे, जबकि हाईकोर्ट में यह संख्या 63 लाख से अधिक व निचली अदालतों में करीब 4.8 करोड़ थी। हालांकि, एक सच यह भी है कि महज जजों की संख्या बढ़ाने से अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम नहीं होगा। इसके लिए न्यायिक व्यवस्था में ढांचागत बदलाव जरूरी है। हमें यह भी जांचना होगा कि मुकदमे लंबित क्यों हैं? क्या कुछ ऐसे मामले हैं, जिनको समय के हिसाब से समाप्त किया जा सकता है? या, कितने मुकदमे ऐसे हैं, जिनको आपस में इकट्ठा करके सुनवाई की जा सकती है? यानी, हमें लंबित मुकदमों का समाधान जल्द ढूंढ़ना होगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे मुकदमों की प्रकृति जानने में आसानी होगी।

न्यायिक नियुक्ति एक मसला जरूर है, पर हमें लंबित मुकदमों का समाधान जल्द ढूंढ़ना होगा, जिसमें एआई की मदद भी लेनी चाहिए।

न्यायाधीशों के काम में किसी तरह की दखलंदाजी भी बंद होनी चाहिए। इसके कारण सुनाए गए फैसलों में खामी की गुंजाइश बढ़ जाती है। अभी कई ऐसे मामले अदालतों में हैं, जिन पर संविधान पीठ निर्णय ले चुकी है, लेकिन उसकी सुनवाई अब बड़ी संख्या वाली संबंधित संविधान पीठ के समक्ष चल रही है। सबरीमाला केस इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिस पर सात जजों की पीठ ने फैसला ले लिया था, लेकिन अब यह नौ जजों की पीठ के हवाले है। इस तरह के कई मुकदमे हैं, जिनको प्राथमिकता दी जा रही है और जिन पर समय बहुत खर्च हो रहा है। इसमें सुधार जरूरी है। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं और कानूनों में लगातार किए जा रहे बदलाव भी जजों की परीक्षा लेते हैं।

जरूरत राजनीति से प्रेरित मुकदमों को हतोत्साहित करने की भी है। आज जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनमें से करीब 50 प्रतिशत मामलों में एक पक्ष भारत संघ होता है या फिर राज्य सरकार। ऐसे में, सिविल, आपराधिक या अन्य मुकदमों को निपटाने में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर थोड़ी सख्ती दिखानी होगी और एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जो यह तय करे कि इनमें से किस तरह के मुकदमों को अदालतों के सामने लाना आवश्यक है? निस्संदेह, न्यायाधीशों के पास काम का दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन यह देखना आवश्यक है कि आखिर इस 'वर्कलोड' की वजह क्या है?

हम चाहें, तो यूरोप या पश्चिम की अदालतों से कुछ सीख सकते हैं। वहां इस तरह की ढांचागत समस्या बहुत ज्यादा नहीं दिखती। वहां रोस्टर के विवाद नहीं होते और न ऐसे आरोप उछलते हैं कि 'खास' मामले 'खास' जज को दिए गए हैं। जाहिर है, अपने देश में इन सब पर गंभीरता से काम करना होगा। मुकदमों के सूचीकरण वगैरह में पारदर्शिता का पालन हो और तय प्रक्रिया को अमल में लाने की व्यवस्था हो, तो न्यायिक फैसले निर्विवाद रहेंगे और अदालतें भी मुकदमों के बोझ से राहत पा सकेंगी। केवल जजों की संख्या बढ़ा देने से यह संभव नहीं कि आम आदमी को न्याय जल्दी मिलेगा। इसके लिए एक सोच के साथ न्याय व्यवस्था में सुधार जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

संसार से मोह कैसा

एक बार एक शिष्य ने प्रश्न किया, 'बाबा, हम जानते हैं कि यहां कोई सदा के लिए नहीं रहता, फिर भी धन-दौलत, मान-सम्मान, रिश्ते-नाते सबको अपना समझकर उसे पकड़े रखते हैं। आखिर इसका राज क्या है और इससे कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है?'

मनुष्य का जीवन केवल जन्म, भोग और मृत्यु की एक साधारण यात्रा नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार, यह आत्मा की उस अनंत यात्रा का एक पड़ाव है, जिसका अंतिम लक्ष्य है- प्रकृति के बंधनों से पूर्ण मुक्ति। यही मुक्ति 'मोक्ष' है और इसी की प्राप्ति के लिए साधना का मार्ग बताया गया है। साधना केवल पूजा-पाठ या ध्यान का अभ्यास नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रहे उस महायुद्ध का नाम है, जिसमें मनुष्य को अपनी चंचलता, वासनाओं, अहंकार और अज्ञान पर विजय प्राप्त करनी होती है।

दर्शन कहता है कि मनुष्य का मन प्रकृति के प्रभाव से निरंतर चंचल बना रहता है। यही चंचलता उसे बाहरी संसार की वस्तुओं, इच्छाओं और मोह में बांध देती है। मन जितना अधिक स्थूल विषयों में उलझता है, उतना ही वह अशांत और अशुद्ध होता जाता है। साधना का उद्देश्य इस अशांत मन को स्थूलता से हटाकर सूक्ष्मता की ओर ले जाना है। जब मन धीरे-धीरे बाहरी आकर्षणों से हटकर भीतर की चेतना में स्थिर होने लगता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। यह मार्ग सरल नहीं है। जब कोई साधक साधना प्रारंभ करता है, तब उसके जीवन में अनेक बाधाएं आने लगती हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये बाधाएं पतन के नहीं, बल्कि प्रगति के संकेत हैं।

साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है- अहंकार का विसर्जन। आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होने पर अनेक लोग उनको प्रदर्शन का माध्यम बना लेते हैं। किंतु वास्तविक अध्यात्म कहता है कि शक्ति का प्रदर्शन साधक को पुनः अहंकार और अविद्यामाया के अधीन कर देता है।

इस मार्ग में गुरु का महत्व भी अत्यंत गहरा है। जिस प्रकार अंधकार में भटका हुआ व्यक्ति बिना मार्गदर्शक के सही दिशा नहीं पा सकता, उसी प्रकार साधना का सूक्ष्म मार्ग भी सद्गुरु के बिना पूर्ण नहीं होता। किंतु केवल गुरु मिल जाने से मुक्ति नहीं मिलती; साधक को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। जब मन की चंचलता समाप्त होती है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है। वही अवस्था मुक्ति है- जहां न भय है, न मोह, न दुख और न ही जन्म-मृत्यु का बंधन।

साधना केवल धर्म का कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का विज्ञान है। जब मन की चंचलता समाप्त होती है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है।

साधना केवल धर्म का कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का विज्ञान है। यही मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है और यही उसके जीवन की वास्तविक पूर्णता।

श्री श्री आनंदमूर्ति

इमैनुएल मैक्रों | राष्ट्रपति, फ्रांस

हमारे देश (फ्रांस) में लाखों नौजवान पूरी तरह फ्रेंच हैं और लाखों पूरी तरह अफ्रीकी। यह विविधता देश के लिए बड़ी संभावनाएं पैदा करती है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए।

अनुलोम-विलोम

मितव्ययिता की अपील

त्याग की शुरुआत पहले माननीय करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने, गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने, डेस्टिनेशन विवाह से दूरी बरतने, सोने की खरीद कम करने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की है। उनका तर्क है कि भारत आज भी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित ईंधन पर निर्भर है। ऐसे में, यदि देश ईंधन की खपत कम करेगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा और आर्थिक आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। यह बात पूरी तरह सही और व्यावहारिक है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत जैसी अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए बचत और संयम की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह त्याग केवल आम जनता के लिए है? क्या इसकी शुरुआत सत्ता और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से नहीं होनी चाहिए? जब देश का आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते खर्चों से जूझ रहा हो, तब नेताओं और मंत्रियों के लंबे-लंबे काफिले, वीआईपी संस्कृति और सरकारी सुविधाओं का खुला प्रदर्शन लोगों के मन में सहज सवाल खड़े करता है। यदि वास्तव में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, तो सबसे पहले मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें अपने काफिले को सीमित करना चाहिए। सरकारी खर्चों में कटौती करनी चाहिए। विदेश दौरों और आलीशान सरकारी आयोजनों पर अंकुश लगाना चाहिए। वेतन और भत्तों में भी स्वैच्छिक कमी करनी चाहिए। जब माननीय त्याग का संदेश व्यवहार में उतारेंगे, तभी जनता भी उसे ईमानदारी से स्वीकार करेगी।

कोविड-19 महामारी के दौरान देश ने देखा कि कैसे वर्चुअल बैठकें और घर से काम की व्यवस्था ने न केवल समय बचाया, बल्कि ईंधन की खपत भी कम की। यदि सरकार और प्रशासनिक तंत्र इन व्यवस्थाओं को फिर से प्राथमिकता दें, तो यह एक सकारात्मक पहल होगी। किंतु यह भी जरूरी है कि नेताओं के निजी और राजनीतिक कार्यक्रमों में संसाधनों की फिजूलखर्ची बंद हो। हजारों गाड़ियों के काफिले और भव्य राजनीतिक रैलियां ईंधन बचत के संदेश को कमजोर करती हैं। दरअसल, समस्या सुझावों में नहीं, बल्कि दोहरे मापदंड में है। लोकतंत्र में नेतृत्व का अर्थ केवल भाषण देना नहीं, बल्कि उदाहरण प्रस्तुत करना भी होता है। भारत की आर्थिक मजबूती और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए जनता पर नैतिक दबाव बनाने से पहले नेताओं को स्वयं सादगी अपनानी होगी।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

मितव्ययिता करना हम सबकी जिम्मेदारी

वैश्विक अस्थिरता, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और कमजोर होते रुपये के दौर में यदि देश का नेतृत्व नागरिकों से संयम और किफायत की अपील करता है, तो इसे केवल सलाह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के सीमित उपयोग, 'वर्क फ्रॉम होम' संस्कृति अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, सोने की खरीद कम करने और देश में ही विवाह समारोह आयोजित करने की बात वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह प्रासंगिक है। दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष इस गंभीर विषय को भी राजनीतिक चश्मे से देखने में लगा है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। ऐसे में, जब तेल महंगा होता है, तो आयात बिल बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आता है। इसका असर केवल सरकार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम जनता को महंगाई, परिवहन-खर्च और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए, यदि नागरिक थोड़ी किफायत बरतें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएं, ईंधन का अनावश्यक खपत कम करें, विलासिता से बचें और स्थानीय संसाधनों को प्राथमिकता दें, तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती ही मिलेगी। भारत की संस्कृति सदैव 'सादा जीवन, उच्च विचार' की रही है। आज आवश्यकता इस सोच को व्यवहार में उतारने की है। यदि हर नागरिक 'न्यूनतम में काम चलाने' की आदत विकसित कर ले और राष्ट्रहित को व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर रखे, तो भारत न केवल आर्थिक चुनौतियों का मजबूती से सामना करेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता व विकास की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

पेट्रोल-डीजल की खपत कम करना, 'वर्क फ्रॉम होम' को बढ़ावा देना, अनावश्यक सोना खरीदने से बचना, विदेशी यात्राओं में कटौती और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री की अपील को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह दूरगामी आर्थिक संकटों से बचने की व्यापक आर्थिक रणनीति का एक हिस्सा है। आज देश की प्राथमिकता है, विदेशी मुद्रा को बचाए रखना। थोड़े समय पहले ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था, लेकिन अब यह घटकर 690.7 अरब डॉलर रह गया। इसलिए हमें आर्थिक अनुशासन में रहना ही होगा। राष्ट्र के हितों के साथ ही हमारे हित भी जुड़े रहते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखकर हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए।

रामबाबू सोनी, टिप्पणीकार

संसाधन बचाना भी समाधान

क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बहुत वृद्धि होने वाली है? क्या सोना खरीदना मुश्किल हो जाएगा? आज ऐसे अनेक सवाल चर्चा में हैं। आखिर मितव्ययिता से हम अर्थव्यवस्था को कितना बचा पाएंगे? ज्यादातर आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि संयम या किफायत बरतने से समाधान को बल मिल सकता है। पेश है सुभाना शेख की रिपोर्ट...

90 प्रतिशत तक स्वर्ण का भारत आयात करता है। यहां खपत ज्यादा है और आपूर्ति कम। अभी सोना कम खरीदने से देश को फायदा है।

85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चे तेल का हम विदेश से आयात करते हैं। ईरान में युद्ध के चलते भारत ही नहीं, दुनिया भर में तेल आयात घटा है।

1.8 प्रतिशत से ज्यादा हो सकता है भारत का चालू वित्तीय घाटा। तेज विकास के लिए इस घाटे को कम करने के हर संभव उपाय होने चाहिए।

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से कोविड काल के मितव्ययिता उपायों को फिर से अपनाने का आग्रह किया है। इस अपील के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की मुख्य अपीलों को अगर हम देखें, तो घर से काम करना, ईंधन की खपत कम करना, विदेश यात्रा से बचना और एक वर्ष के लिए सोने की खरीद को स्थगित करने जैसी सलाह शामिल है, जिनकी विवेचना हो रही है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक देशभक्ति की अपील से सोने और विदेश यात्रा जैसे विवेकाधीन आयातों पर अंकुश लगाकर बाह्य खाते को अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और देश में कमजोर पूंजी प्रवाह के कारण वित्त वर्ष 2027 में व्यापक चालू खाते की स्थिति में काफी गिरावट आएगी। मतलब, स्थितियां अगर जल्दी नहीं सुधरीं, तो देश का वित्तीय घाटा बढ़ने की प्रबल आशंका है।

किसी देश का सीएडी अर्थात करंट अकाउंट डिफिसिट या चालू वित्तीय घाटा शेष विश्व से अर्जित धन और विदेशों में खर्च किए गए धन के बीच का अंतर होता है। भारत का यह घाटा बना ही रहता है, क्योंकि यह निर्यात की तुलना में कहीं अधिक कच्चा तेल व सोना आयात करता है। भारत को आयात के भुगतान के लिए अधिक डॉलर की आवश्यकता रहती है। बाहर देशों से चीजें खरीदने के लिए डॉलर की अधिक मांग रुपये को कमजोर करती चली जाती है। अभी यही हो रहा है।

एएनजेड के विदेशी मुद्रा रणनीतिकार धीरज निम का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.8-2 प्रतिशत रहेगा, यह मानते हुए कि तेल की औसत कीमत लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल रहेगी।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता अनुमान लगाती हैं, वित्त वर्ष 2027 में भारतीय कच्चे तेल की औसत कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहेगी। फिलहाल, चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.4 प्रतिशत है। अभी भी लगभग 100 अरब डॉलर का चालू खाता घाटा है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 की तुलना में यह काफी अधिक है।

सेनगुप्ता बताती हैं कि कच्चे तेल की आपूर्ति हासिल करने के लिए देशों को हो रही मशक्कत के चलते शुरुआत में तेल की कमी कम गंभीर लग सकती है और वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में आयात की मात्रा घट सकती है। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि आपूर्ति शृंखलाओं के सामान्य होने और देशों द्वारा भंडार फिर से भरने के साथ ही, दूसरी छमाही में आयात में उछाल आएगा।

आयात पर निर्भरता मजबूरी

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85-90 प्रतिशत आयात करता है, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश बन गया है। 10 मई तक जारी आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 134.7 अरब डॉलर है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 137 अरब डॉलर था।

सेनगुप्ता मानती हैं कि पहली छमाही में जो आयात नहीं हो सका, उसकी भरपाई दूसरी छमाही में हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी अगर आयात कम हो रहा है, तो उससे जो बचत हो रही है, वह ज्यादा समय नहीं टिकेगी। अंततः पश्चिम एशिया में जब तेल-गैस के जहाजों का आवागमन सामान्य हो जाएगा, तब मांग और आपूर्ति की मात्रा भी बहुत बढ़ जाएगी।

भारत में अभी बहुत क्षमता

एक सवाल यह भी है कि आखिर स्थितियां कब सामान्य होंगी? युद्ध कब समाप्त होगा, इस बारे में तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन युद्ध-विराम के बाद भी खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के उत्पादन को पूरी तरह से सामान्य होने में तीन से छह महीने का समय लग सकता है।

सेनगुप्ता यह भी चेतावनी देती हैं कि भारत की आयात कवर या क्षमता पूरे साल काफी कमजोर बनी रह सकती है। मतलब, बाहर से तेल या सामान मंगाने के लिए हमें ज्यादा धन खर्च करने की जरूरत पड़ रही है और यह जरूरत बनी रहेगी। मार्च 2026 तक, आयात कवर नौ महीने का है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार और भविष्य का अनुमान भी शामिल है। यदि कच्चे तेल की कीमतें औसतन 90 डॉलर प्रति बैरल रहती हैं, तो मार्च 2027 तक आयात कवर घटकर 7.5 महीने रह जाएगा। युद्ध की वजह से स्थितियां ज्यादा बिगड़ीं, तो यह सात महीने से भी नीचे जा सकता है। वैसे, सात महीने तक आयात करने लायक पैसा भारत के पास हर हाल में रहेगा।

मिंट ने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनविस के हवाले से भविष्य की स्थितियों के बारे में बताया था। यह मानते हुए कि कच्चे तेल की कीमत अगर पूरे साल 100 डॉलर प्रति बैरल पर बनी रहती है, जो असंभव लगता है, तो भारत का तेल बिल या तेल पर किया जाने वाला खर्च सैद्धांतिक रूप से वार्षिक आधार पर बढ़कर लगभग 18 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह एक चरम स्थिति है। उस स्थिति में भारत का चालू वित्तीय घाटा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा।

सोना न खरीदने से लाभ

अर्थशास्त्री यह भी मानते हैं कि सोने की खरीद पर प्रतिबंध या स्वैच्छिक संयम से चालू खाते पर दबाव में कमी आ सकती है। भारत को विदेशी मुद्रा के मद में लाभ हो सकता है, पर सोने की मांग खत्म होने की संभावना नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कोई सोना खरीदने में संयम बरतेगा। सोने का आयात जारी रहेगा और घाटा भी कुछ बना रहेगा। फिर भी सोना न खरीदने की अपील से लाभ की पूरी संभावना है।

करूर वैश्य बैंक के कोषागार प्रमुख वीआरसी रेड्डी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से एक वर्ष के लिए सोने की खरीद स्थगित करने का आग्रह वास्तव में आर्थिक देशभक्ति दिखाने का आह्वान है। यदि इसका सकारात्मक प्रतिसाद मिलता है, तो इससे सोने के आयात में कमी आ सकती है और डॉलर की मांग पर दबाव कम हो सकता है, जिससे भारत की चालू खाता घाटे की स्थिति को कुछ हद तक सहारा मिल सकता है।

वित्त वर्ष 2026 में भारत के कुल आयात बिल में सोने की हिस्सेदारी 9.3 प्रतिशत है। सोना खरीदने में संयम की वजह से इस बिल या खर्च में थोड़ी भी कटौती हुई, तो अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा।

हालांकि, रेड्डी ने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बाहरी क्षेत्र के दबावों के कारण पश्चिम एशिया का संकट एक बड़ा जोखिम बना हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि 2025 की शुरुआत से अब तक विदेशी निवेशक 50 अरब डॉलर से अधिक राशि भारतीय शेयर बाजार से निकाल चुके हैं। यह सोना खरीदने या न खरीदने से ज्यादा बड़ी चिंता है।

यह गौर करने की बात है कि ज्यादातर आर्थिक विशेषज्ञ चालू वित्त वर्ष की अगली छमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद जता रहे हैं।

अनुमान और उम्मीदें

रुपये की लगातार गिरावट को लेकर अर्थशास्त्री सतर्क हैं। हालांकि, विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए कुछ नीतिगत उपायों की उम्मीद थी, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संभावित डॉलर बॉन्ड जारी करना शामिल है।

सेनगुप्ता बताती हैं कि अगर होर्मुज जलमार्ग में व्यवधान उम्मीद से अधिक समय तक चलता है और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के कारण पूंजी का बाहर जाना जारी रहता है, तो निकट भविष्य में रुपया 96 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है।

अर्थशास्त्री धीरज निम ने इस साल के अंत तक रुपये का मूल्य 97.5 रहने का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि यह दृष्टिकोण रुपये पर मौजूदा खाते के दबाव की गंभीरता को दर्शाता है। भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया ने तेल की ऊंची कीमतों के स्वाभाविक आर्थिक समायोजन में देरी की है। यहां यह ध्यान देने की बात है कि पेट्रोल, डीजल के भाव को सरकार ने ज्यादा बढ़ने से रोक रखा है।

उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से बचाकर हमने अपरिहार्य समायोजन को रोका है, जिससे चालू खाते पर दबाव बढ़ा है। निम आगे बताते हैं कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि से विवेकाधीन खर्च और आयात मांग में कुछ समय बाद कमी आ सकती है।

अच्छी बात है, कोई विशेषज्ञ यह नहीं मानता है कि भारत एक बार फिर 'कमजोर पांच' देशों की श्रेणी में आने के कगार पर है। 'कमजोर पांच' उन उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिनकी पहचान 2013 के आर्थिक मंदी के दौर में की गई थी। भारत 2014-2018 के दौरान इस श्रेणी से बाहर निकल आया है। वापस वैसी कमजोर स्थिति नहीं बनेगी। अगर हमने संसाधन बचाने के थोड़े भी उपाय किए, तो समाधान में जरूर मदद मिलेगी।

mint

ध्यान रखना होगा कि बूंद-बूंद से भी घड़ा भरता है। मितव्ययिता से देश का पूरा घाटा तो नहीं भर सकता, लेकिन घाटा कम करने में जरूर कामयाबी मिल सकती है। भारत का वित्तीय घाटा बना ही रहता है, क्योंकि भारत निर्यात की तुलना में अधिक आयात करता है। तेल और सोने के आयात में बहुत धन खर्च करना पड़ता है। भारत सरकार को आयात के भुगतान के लिए अधिक डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। बाहर देशों से चीजें खरीदने के लिए डॉलर की अधिक मांग रुपये को कमजोर करती चली जाती है। अभी यही हो रहा है। ऐसे में, संसाधनों का किफायती इस्तेमाल हमें मजबूती दे सकता है।

गिरता रुपया बढ़ता दबाव

एक डॉलर में कितने रुपये

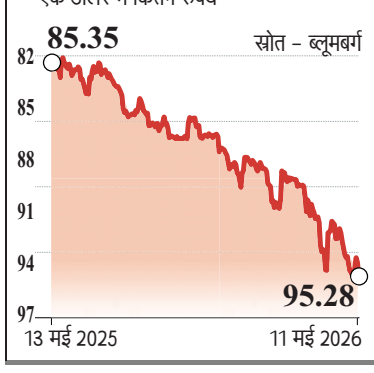

घर से काम को तरजीह

भारत में कुल श्रम शक्ति का करीब 15 प्रतिशत ऐसा है, जो घर से या कहीं दूर बैठकर काम कर सकता है। करीब छह करोड़ से नौ करोड़ लोग भारत में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में 90 प्रतिशत तक काम ऑफिस से दूर बैठकर किया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम की ताजा अपील ईंधन बचाने के मकसद से की गई है। कारपूलिंग या सार्वजनिक वाहन से यात्रा की अपील की गई है, इससे निश्चित ही बचत होगी, आर्थिक लाभ होगा, लेकिन नौकरी की चिंता भी बढ़ेगी। अभी 50 से अधिक देशों में वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति है।

पेट्रोल-डीजल खर्च घटाना

भारत में प्रतिदिन 30 करोड़ लीटर पेट्रोल और करीब 40 करोड़ लीटर डीजल की खपत है। अगर इस खपत में दस प्रतिशत भी कमी हुई, तो अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। एक अनुमान के अनुसार, भारत अभी अनेक देशों से तेल ले रहा है, लेकिन तेल का इंतजाम आसान नहीं है। अपनी जरूरत से 15 से 20 प्रतिशत तेल कम आयात हो रहा है। क्या हम इतने तेल की खपत को रोक सकते हैं? सरकार चाहती है कि हम खपत कम करें, ताकि कच्चे तेल की कमी दूर हो जाए। अनेक देशों में ऐसा किया जा रहा है, कुछ देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है।

सोना खरीदने से परहेज

भारत को अपनी खपत के लिए सोने का आयात बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार, प्रति घंटे भारत को करीब 80 किलोग्राम सोना आयात करना पड़ता है। सोना आयात में बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है। सोना न खरीदने की अपील पर नाराजगी भी देखी जा रही है। हालांकि, यह अपील नई नहीं है। देश पर जब भी मुसीबत आती है, सरकार ऐसी उम्मीद लोगों के सामने रखती है। लोगो के संयम से खपत अगर दस प्रतिशत भी घटती है, तो देश के छह अरब डॉलर मतलब 564 अरब रुपये की बचत हो जाएगी।

विदेश यात्रा में कमी करना

भारत अब गरीब देश नहीं है। साल 2024 में भारतीयों ने विदेशी दौरे पर 31.7 अरब डॉलर खर्च किए थे। भारतीयों के विदेश दौरे बढ़ते ही जा रहे हैं और यही गति रही, तो साल 2027 में भारतीय लोग विदेशी दौरे पर करीब 90 अरब डॉलर खर्च कर देंगे। ऐसे दौरों से देश को नुकसान ही ज्यादा होता है। देश का पैसा विदेश में खर्च होता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आती है। यहां संयम के उपाय जरूरी हैं। देश में तीन करोड़ लोग भी आयकर नहीं देते हैं, लेकिन सवा तीन करोड़ से ज्यादा लोग साल 2025 में विदेशी दौरे पर गए थे।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। खर्चों में वृद्धि होगी।

वृष : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन में उतार-चढ़ाव भी रहेंगे। नौकरी से कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। परिवार से दूर हो सकते हैं।

मिथुन : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यर्थ के क्रोध व विवाद से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में लाभ में वृद्धि होगी।

कर्क : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। माता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी।

सिंह : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है।

कन्या : मन प्रसन्न तो रहेगा, किंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। लाभ भी मिलेगा।

तुला : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के योग हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। खर्च बढ़ेंगे।

धनु : आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे।

मकर : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। भवन सुख में वृद्धि होगी। घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी। पिता की सेहत का ध्यान रखें। यात्रा पर भी जा सकते हैं।

कुंभ : मन परेशान हो सकता है। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के अवसर बन सकते हैं। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। यात्रा खर्च बढ़ सकते हैं।

मीन : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

13 मई, बुधवार, **शक संवत्** : 23 वैशाख (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 30 वैशाख मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 25 जिल्काद, 1447, **विक्रमी संवत्** : प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि दोपहर 01.30 मिनट तक। विष्कुंभ योग रात्रि 08.55 मिनट तक पश्चात प्रीति योग, बालव करण, चंद्रमा मीन राशि में (दिन-रात)

सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। बसंत ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01.30 मिनट तक राहुकालम्। अपरा एकादशी व्रत। गण्डमूल रात्रि 12.18 मिनट से। पंचक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हम एक नया घर बनवा रहे हैं। कृपया नक्शा देखकर बताएं क्या ये सही है। मेरे दो किशोर बेटे हैं। -रीना, लखनऊ

- आपका प्लॉट ईशान मुखी है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। आपने एंट्री उत्तर दिशा से ली है, जो ठीक है। आपने मंदिर भी ईशान कोण में बनवाया है। यह भी ठीक है।
- आपकी रसोई थोड़ी पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में है। इसको ठीक प्रकार से अग्नि कोण में बनाएं। शयन कक्ष पश्चिम दक्षिण पश्चिम में है, जो ठीक है। आपने जो बेटों के कमरे लिए हैं, वे दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम दिशा में हैं। ये दोनों ही छोटे बेटों के लिए उचित नहीं होते। आप उनका कमरा उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा में बनवाएं।

वर्ग पहेली : 8327

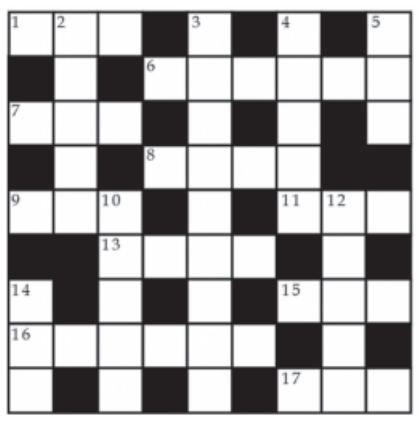

बाएं से दाएं
1. मानदंड; स्तर (3)
6. समाधान कर देना; समाधान निकालना; सुलझा देना (2,2,2)
7. समूह; राशि; ढेर; खट्टे-मीठे फल वाला सदाबहार वृक्ष (3)
8. आकर्षित करने वाला; खींचने वाला; मोहक; रोचक; सुंदर (4)
9. रूप; आकृति; चिह्न; निशान; पता (3)
11. बूंद-बूंद गिरने वाला; टपकी हुई वस्तु (3)
13. गमन; प्रस्थान; प्रेषण; विदाई (4)
15. दूध देने वाला चौपाया; डंगर; ढोर; बोझ ढोने वाले पशु (3)
16. इंद्रिय निग्रह करना; अपने पर नियंत्रण रखना; धैर्य रखना; बुरी बातों से बचाव करना (3,3)
17. पास; समीप (3)

ऊपर से नीचे
2. नवविवाहित जोड़ा; सद्यविवाहित पति-पत्नी (5)
3. खोज-खबर तक न लेना; मुड़ कर न देखना; वापस न आना (3,2,1,3)
4. गांठ काटने वाला; जेबकतरा (5)
5. अख्याति; बिना नाम के; नामहीन (3)
10. कमल जैसे सुंदर हाथ (5)
12. चारों तरफ नजर रखने वाला; निगरानी करने वाला; पर्यवेक्षण करने वाला (5)
14. तराजू के पलड़ों का अंतर (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8326

	1 ब		2 वा		3 सं	4 क	ल	5 न
6 ज	न	मा	न	7 स		ल		ज
	ना		8 र	ह	र	ह	क	र
9 दि		10 वि		ना		क		र
11 ल	ट	का	ना		12 मो	र	पं	ख
द		स		13 आ		ना		ना
14 हे	त्या	क	र	वा	15 ना		1 कि	
ल		र		17 रा	ह	ब	ना	ना
18 ना	ग	ना	थ		क		रा	

सुडोकू : 8309 * आसान

1	5	9		7	6			3
			1					
		7			3			4
3	8			5		2		
		4				5		
		5		2			7	1
8			6			4		
					8			
5			2	3		1	8	9

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8308

6	4	5	1	7	8	3	2	9
3	8	7	9	2	5	1	6	4
1	2	9	4	6	3	7	8	5
5	3	4	8	1	7	6	9	2
9	1	8	6	3	2	5	4	7
2	7	6	5	9	4	8	1	3
8	5	1	7	4	9	2	3	6
7	9	3	2	8	6	4	5	1
4	6	2	3	5	1	9	7	8

बिजनेस

खर्च में कमी से टाटा पावर का लाभ आठ प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली : टाटा पावर ने मंगलवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के दौरान कम खर्च के कारण उसका शुद्ध लाभ आठ प्रतिशत बढ़कर 1,415.52 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वर्ष समान अवधि में कंपनी को 1,306.09 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। बीती तिमाही के दौरान कंपनी का कुल खर्च घटकर 14,876.50 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 16,197.77 करोड़ रुपये रहा था। (प्रेट्र)

कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद कंपनी अगले दशक में धीरे-धीरे अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और हर भारतीय को सेवा देने का लक्ष्य रख रही है।

- संजीव बजाज, चेयरमैन, बजाज फिनसर्व

सेंसेक्स	74,559.24 ▼ 1,456.04	निफ्टी	23,379.55 ▼ 436.30	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,56,800 ▲ ₹ 1,500	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,77,000 ▲ ₹ 12,000	$ डालर	₹ 95.68 ▲ ₹ 0.40	क्रूड प्रति बैरल	$ 107.1

एक नजर में

चालू वित्त वर्ष में 4-5% बढ़ सकती है बिजली की मांग

नई दिल्ली : रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भारत में बिजली की मांग वार्षिक आधार पर 4-5 प्रतिशत बढ़ सकती है। इसमें बीते वित्त वर्ष 2025-26 की 0.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के मुकाबले बड़ा सुधार रहेगा। फिच रेटिंग्स ने कहा कि लगातार हो रही आर्थिक वृद्धि और देश में कूलिंग जरूरतों में आई तेज बढ़ोतरी का बिजली मांग बढ़ाने में प्रमुख योगदान रहेगा। (एएनआइ)

चार रुपये प्रति शेयर का लाभांश देगी बर्जर पेंट्स

नई दिल्ली : पेंट निर्माता कंपनी बर्जर पेंट्स के बोर्ड ने अपने शेयरधारकों को बीते वित्त वर्ष 2025-26 के लिए चार रुपये प्रति शेयर का लाभांश देने की सिफारिश की है। बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 27.52 प्रतिशत बढ़कर 335.25 करोड़ रुपये रहा है। लाभ बढ़ने में उत्पाद मिश्रण और कच्चे माल की कीमतों में नरमी का प्रमुख योगदान रहा है। कंपनी के सीईओ अभिजीत राय ने भविष्य की संभावनाओं पर कहा कि सभी श्रेणी और घरेलू मांग के संकेतकों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। (प्रेट्र)

एक जून से लागू हो सकता है भारत-ओमान एफटीए

नई दिल्ली : वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और ओमान के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के एक जून से लागू होने की उम्मीद जताई है। इस समझौते पर दोनों देशों ने दिसंबर, 2025 में हस्ताक्षर किए थे। इसके अमल में आने से भारत की 98 प्रतिशत निर्यात तक शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इसमें टेक्सटाइल, खेती और लेदर शामिल है। चिली के विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक पर गोयल ने कहा कि दोनों देशों की आर्थिकी का आकार अलग-अलग है और एक-दूसरे को मिलने वाले मौकों के अलग-अलग स्तर को देखते हुए चुनौतियां हैं। (प्रेट्र)

खपत घटाने के लिए स्वर्ण आयात नीति की हो समीक्षा

जीटीआरआइ ने समझौते में यूएई से सोना आयात पर दी गई छूट का दिया उदाहरण

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से एक वर्ष तक सोने की खरीद नहीं करने की अपील की है। इस बीच आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरई ने कहा है कि सोने की खपत को कम करने के लिए सरकार को अपनी इस कीमती धातु संबंधी आयात नीति की समीक्षा करनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) में कीमती धातुओं को टैरिफ छूट का उदाहरण देते हुए जीटीआरआइ ने कहा कि इसके बाद दुबई से सोना आयात काफी बढ़ा है।

भारत-यूएई के बीच सीईपीए मई 2022 में लागू हुआ था। समझौते के तहत भारत ने टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) प्रणाली के माध्यम से यूएई से सोने के आयात पर सामान्य आयात शुल्क से एक प्रतिशत कम टैरिफ की अनुमति दी।

- सीईपीए के चलते संयुक्त अरब अमीरात से सामान्य शुल्क से एक प्रतिशत कम पर आता है सोना
- समझौते से पहले भारत के सोना आयात में यूएई का हिस्सा 7.9% था, जो 2025 में 28% हुआ

2.9 अरब डालर के सोने की छड़ों का आयात हुआ था यूएई से वर्ष 2022 में

16.5 अरब डालर पर पहुंचा वर्ष 2025 में दुबई से सोना छड़ों के आयात का मूल्य

जीटीआरआइ के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि 2024 के बजट में भारत ने सोने के आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया। इससे दुबई से आयातित सोना भारत में केवल पांच प्रतिशत शुल्क पर ही प्रवेश कर पाया। तब से दुबई से आयात में भारी बढ़ोतरी हुई है। यूएई से भारत के सोने के बार (छड़) का आयात 2022 में 2.9 अरब डालर से बढ़कर 2023 में 6.7 अरब डालर और 2025 में 16.5 अरब डालर तक पहुंच गया। सीईपीए लागू होने से पहले भारत के सोना आयात में दुबई की हिस्सेदारी 7.9 प्रतिशत थी, जो 2025 में बढ़कर 28 प्रतिशत पर पहुंच गई।

श्रीवास्तव ने कहा कि यह रुझान चिंता पैदा करता है क्योंकि यूएई न तो सोने का खनन करता है और न ही वहां कोई बड़ी प्रसंस्करण गतिविधि होती है। इससे प्रतीत होता है कि इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा तीसरे देशों से सोने को दुबई के रास्ते भारत भेजना है, ताकि भारत के कम टैरिफ का फायदा उठाया जा सके। जीटीआरआइ ने विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के लिए कीमती धातुओं के मूल-स्थान संबंधी नियमों को और कड़ा करने, एफटीए के तहत कीमती धातुओं पर दी गई रियायतों की समीक्षा करने और भविष्य के व्यापार समझौतों से सोना, चांदी, प्लेटिनम और हीरे को बाहर रखने की सिफारिश की है। बीते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का सोना आयात मात्रा के लिहाज से 4.76 प्रतिशत घटकर 721.03 टन रहा है। लेकिन मूल्य के लिहाज से यह 24 प्रतिशत बढ़कर 71.98 अरब डालर रहा है। भारत के कुल सोना आयात में स्विट्जरलैंड की सबसे अधिक 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके बाद दुबई और दक्षिण अफ्रीका हैं।

रुपये में गिरावट से चांदी 12 हजार रुपये बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र: डालर के मुकाबले रुपये में गिरावट और भू-राजनीतिक तनाव के बीच घरेलू माहौल में मजबूती से मंगलवार को कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। आल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, सोना सोमवार के 1,55,300 रुपये के बंद स्तर से 1,500 रुपये या लगभग 1 प्रतिशत बढ़कर 1,56,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी 12,000 रुपये या 4.53 प्रतिशत बढ़कर 2,77,000 रुपये प्रति किलो हो गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह सफेद धातु 2,65,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

विदेशी बाजारों में हाजिर सोना 42.33 डालर या एक प्रतिशत गिरकर 4,692.64 डालर प्रति औंस पर आ गया। जबकि चांदी 3.04 प्रतिशत गिरकर 83.49 डालर प्रति औंस पर आ गई। ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना तीन सप्ताह के उच्चस्तर से गिरकर 4,700 डालर प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है और मजबूत डालर और बढ़ते ट्रेजरी बांड यील्ड के दबाव में हाजिर चांदी 85 डालर से नीचे फिसल गया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा, ''लगातार भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई की अनिश्चितता सोने और चांदी की कीमतों को बढ़ाने में मददगार बनी हुई है।'' एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, ''मंगलवार को डालर के मुकाबले रुपया 35 पैसे गिरकर 95.63 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ, जिससे घरेलू सोने की कीमतों को मजबूत समर्थन मिला।

- सोना 1,500 रुपये बढ़कर 1,56,800 रुपये 10 ग्राम हुआ
- दिल्ली में चांदी का मूल्य 2.77 लाख रुपये किलो हुआ

रुपया 40 पैसे लुढ़ककर 95.68 प्रति डालर के नए रिकार्ड निचले स्तर पर

मुंबई, प्रेट्र: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ने से मंगलवार को रुपया डालर के मुकाबले 40 पैसे लुढ़ककर 95.68 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ।

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.57 पर खुला और कारोबार के दौरान 95.74 के अब तक के निचले स्तर तक आ गया। कारोबार के अंत में यह 95.68 पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 40 पैसे की बड़ी गिरावट है। सोमवार को भी रुपया 79 पैसे टूटकर 95.28 के रिकार्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। विश्लेषकों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और डालर की मजबूती से रुपये पर दबाव बना हुआ है। हालांकि, आरबीआइ के हस्तक्षेप से सहारा मिल सकता है। मिराए एसेट शेयरखान के विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, 'अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर व्याप्त अनिश्चितता के बीच रुपये में कमजोरी का रुख रह सकता है।

अप्रैल में मामूली बढ़कर 3.48 प्रतिशत पर पहुंची खुदरा महंगाई

नई दिल्ली, प्रेट्र: सोने-चांदी के साथ रसोई में इस्तेमाल होने वाले कुछ उत्पादों की कीमतों में वृद्धि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.48 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) पर आधारित इस महंगाई दर का आधार वर्ष 2024 है। मार्च में खुदरा महंगाई दर 3.40 प्रतिशत, फरवरी में 3.21 प्रतिशत और जनवरी में 2.74 प्रतिशत थी। अप्रैल में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 4.20 प्रतिशत रही जबकि मार्च में यह 3.87 प्रतिशत थी।

राज्यवार महंगाई के आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति तेलंगाना (5.81 प्रतिशत) में और सबसे कम मिजोरम में 0.69 प्रतिशत दर्ज की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए महंगाई दर क्रमशः 3.74 प्रतिशत और 3.16 प्रतिशत थी। अप्रैल में सबसे ज्यादा महंगाई चांदी की ज्वेलरी (144.34 प्रतिशत) में दर्ज की गई। इसके बाद नारियल-खोपरा में 44.55 प्रतिशत, सोना, हीरा, प्लेटिनम ज्वेलरी में 40.72 प्रतिशत, टमाटर में 35.28 प्रतिशत और फूलगोभी में 25.58 प्रतिशत दर्ज की गई। हालांकि, पिछले महीने आलू, प्याज, मोटर कार और जीप, मटर और एयरकंडीशनर की कीमतें घटी हैं। आरबीआइ ने 2026-27 में खुदरा महंगाई 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

- सोने-चांदी के साथ खाने-पीने के उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से बढ़ी महंगाई
- ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए महंगाई दर क्रमशः 3.74 प्रतिशत और 3.16 प्रतिशत रही

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगातार चौथे साल कमाया लाभ

नई दिल्ली, प्रेट्र: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1.98 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, ऋण के स्वस्थ विस्तार और आय में वृद्धि ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी बैंकों की लाभप्रदता में योगदान दिया। इस दौरान कुल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 11.1 प्रतिशत बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड उच्च स्तर पर रहा।

सरकारी बैंकों का कुल कारोबार 31 मार्च, 2026 तक 283.3 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.8 प्रतिशत ज्यादा है। कुल जमा राशि सालाना आधार पर 10.6 प्रतिशत बढ़कर 156.3 लाख करोड़ रुपये रही, जो जमाकर्ताओं के निरंतर भरोसे और बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने का परिणाम है।

कच्चे तेल में तेजी से 1456 अंक गिरा सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अनिश्चितता के चलते लगातार चौथे दिन शेयर बाजार नीचे बंद हुए और सेंसेक्स और निफ्टी लगभग दो प्रतिशत गिर गए। बड़े पैमाने पर बिकवाली के बीच 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,456.04 अंक या 1.92 प्रतिशत गिरकर 74,559.24 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 1,565.78 अंक या दो प्रतिशत गिरकर 74,449.50 पर आ गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 436.30 अंक या 1.83 प्रतिशत गिरकर 23,379.55 पर बंद हुआ। लगातार विदेशी फंड की निकासी और रुपये के अब तक के सबसे निचले स्तर तक गिरने से निवेशकों की भावना पर भी असर पड़ा।

चार कारोबारी सत्रों में बीएसई 3,399.28 अंक या 4.36 प्रतिशत गिरा है जबकि निफ्टी में 951.4 अंक या 3.91 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में से टेक महिंद्रा, अदाणी पोर्ट्स, एचसीएल टेक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन और भारत इलेक्ट्रानिक्स प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। वहीं सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक में तेजी रही। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.75 प्रतिशत बढ़कर 107.1 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क कास्पी, शंघाई का एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग नीचे बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स 1,312.91 अंक टूटकर 76,015.28 अंक पर बंद हुआ था, वहीं निफ्टी 360.30 अंक की गिरावट के साथ 23,815.85 पर रहा था।

विदेशी फंड की लगातार निकासी और रुपये के अब तक के सबसे निचले स्तर तक गिरने से निवेशकों की धारणा पर पड़ा असर

74,559 अंक पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स

436 अंक की गिरावट से 23,379 पर आया निफ्टी

3,399 अंक गिरा है सेंसेक्स चार सत्रों में

951 अंक की गिरावट दर्ज की गई है निफ्टी में इस दौरान

गिरावट बड़े पैमाने पर थी और इसकी अगुआई सूचना-प्रौद्योगिकी और रियल्टी स्टाक ने की। एआइ से होने वाले मूल्य दबाव को लेकर चिंता बढ़ने से आइटी स्टाक का प्रदर्शन खराब रहा।

-विनोद नायर, रिसर्च हेड, जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

चार कारोबारी सत्रों में 16.77 लाख करोड़ घटी संपत्ति

पिछले चार कारोबारी सत्रों में निवेशकों की संपत्ति में 16.77 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का पूंजीकरण घटकर 4,56,02,981 करोड़ रुपये रह गया।

आइटी शेयर लुढ़के	
टेक महिंद्रा	4.44
एचसीएल टेक	4.11
टीसीएस	2.84
विप्रो	3.59
इन्फोसिस	3.09

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अंतरराष्ट्रीय

न्यूज गैलरी

एअर इंडिया ने बढ़ाया इजरायल के लिए उड़ानों का निलंबन

यरुशलम : एअर इंडिया ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम एशिया में अनिश्चितताओं के बीच तेल अवीव-दिल्ली मार्ग पर उड़ानों का निलंबन जून के अंत तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले अप्रैल में एअर इंडिया ने मई के अंत तक अपने परिचालन को रोकने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। (प्रेट्र)

बढ़ सकते हैं हंटावायरस के मामले : डब्ल्यूएचओ

मैड्रिड: डब्ल्यूएचओ ने हंटावायरस संक्रमण को लेकर नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले हफ्तों में और मामले सामने आ सकते हैं। हालांकि फिलहाल वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को कम बताया है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा है कि वायरस की लंबी इन्क्यूबेशन अवधि को देखते हुए नए संक्रमण आना संभव है। अब तक हंटावायरस के सामने आए 11 मामलों में तीन लोगों की मौत हो गई है। (आइएएनएस)

बंकर में होने का दावा खारिज करता पुतिन का वीडियो आया

मास्को : क्रेमलिन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मास्को में कार ड्राइव करते हुए अपनी पुरानी स्कूल टीचर से बड़ा-सा गुलदस्ता लेकर होटल के लाबी में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो तब जारी किया गया, जब पश्चिमी मीडिया ने एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि 'रूसी राष्ट्रपति कई हफ्तों तक बंकरों में छिपे रहे। (रायटर)

इजरायल में फांसी की सजा के लिए विशेष ट्रिब्यूनल को मंजूरी

यरुशलम : इजरायली संसद नेसेट ने सोमवार को एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में शामिल आरोपितों की सुनवाई के लिए विशेष ट्रिब्यूनल गठित किया जाएगा। यह ट्रिब्यूनल दोष सिद्ध होने पर मृत्युदंड सुनाने का अधिकार रखेगा। 120 सदस्यीय नेसेट में विधेयक 93-0 के मत से पारित हुआ। विधेयक को इजरायल के इतिहास के सबसे भीषण हमले के दोषियों को दंडित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। (एपी)

युद्धविराम पर संकट, ईरान ने परमाणु बम बनाने की दी चेतावनी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में पिछले एक महीने से कायम युद्धविराम अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रस्तावों पर सहमति नहीं बनने से तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए संकेत दिया कि युद्धविराम अब गंभीर संकट में है और ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसके बाद खाड़ी क्षेत्र में फिर बड़े संघर्ष की आशंका गहरा गई है।

ट्रंप के बयान पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान ने कहा कि वह अब भी बातचीत के जरिये समाधान चाहता है, लेकिन उसकी अंगुलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान ने चेतावनी दी कि यदि उस पर दोबारा हमला हुआ तो वह परमाणु बम बनाने से पीछे नहीं हटेगा।

खाड़ी संकट के लंबे खिंचने का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखा और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 108 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। वहीं, अमेरिका ने ईरान की मदद करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

ईरान की अमेरिका को कड़ी चेतावनी: रायटर के अनुसार, ईरान की संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने एक्स पर लिखा कि यदि देश पर दोबारा हमला हुआ तो ईरान यूरेनियम संवर्धन को 90 प्रतिशत शुद्धता तक ले जा सकता है। यह स्तर हथियार-ग्रेड संवर्धन माना जाता है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को 'कचरा' बताते हुए कहा था कि दोनों देशों के बीच संघर्षविराम 'वेंटिलेटर' पर है।

ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने एक्स पर लिखा, 'हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं। वे चौंक जाएंगे।' सरकारी एजेंसी फार्स न्यूज के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आइआरजीसी) नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट की अपनी सामरिक परिभाषा का विस्तार करते हुए इसे पहले से कहीं बड़ा 'आपरेशनल क्षेत्र' घोषित किया है। कहा कि अब जलडमरूमध्य को केवल कुछ द्वीपों तक सीमित क्षेत्र के रूप में नहीं देखा जाएगा। पहले होर्मुज और हेंगाम द्वीपों के आसपास सीमित माने जाने वाले इस क्षेत्र को अब पूर्व में जास्क शहर से लेकर पश्चिम में सीरी द्वीप तक फैला रणनीतिक क्षेत्र माना जाएगा। पहले जिस जलडमरूमध्य की चौड़ाई 20 से 30 मील मानी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 200 से 300 मील तक का क्षेत्र माना जा रहा है।

- ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला- दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम संवर्धन 90% की शुद्धता तक ले जाएंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पोस्ट की गईं एआइ तस्वीरें। सौ. ट्रुथसोशल

ट्रंप ने ईरान पर हमलों की एआइ तस्वीरें साझा कर दिए गंभीर संकेत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध केवल खाड़ी में ही नहीं लड़ा गया, बल्कि इसका एक संस्करण इंटरनेट मीडिया पर भी देखा जा सकता है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दर्शाने वाली एआइ-निर्मित तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर साझा की हैं। इनमें लेजर हथियारों से ईरानी विमानों को निशाना बनाते दिखाया गया है। ट्रंप ने अपने 'ट्रुथ सोशल' पर कई काल्पनिक युद्ध दृश्य पोस्ट किए हैं। एक तस्वीर में अमेरिकी युद्धपोत को ईरानी झंडा लगे विमान पर हमला करते दिखाया गया। इसके साथ ट्रंप ने लिखा, 'लेजर्स : बिंग, बिंग, गान!!!' एक अन्य एआइ तस्वीर में अमेरिकी ड्रोन को ईरान की तथाकथित 'फास्ट बोट्स' के ऊपर उड़ते दिखाया गया है।

पाक ने माना, खाड़ी युद्ध में ईरान को एयरबेस इस्तेमाल की दी थी छूट

इस्लामाबाद, एएनआइ: पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि खाड़ी युद्ध के दौरान उसने ईरानी विमानों को अपने रणनीतिक सैन्य एयरबेस इस्तेमाल की अनुमति दी थी। यह बात सामने आने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला तब चर्चा में आया जब सीबीएस न्यूज ने दावा किया कि पाकिस्तान ने चुपके से ईरानी सैन्य विमानों को अपना एयरफील्ड इस्तेमाल करने दिया, ताकि वे अमेरिकी हमलों से सुरक्षित रह सकें। रिपोर्ट में कहा गया कि युद्धविराम के बाद ईरान ने अपने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भेजे थे।

रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर नूर खान एयरबेस पर ईरानी विमानों की मौजूदगी से जुड़ी खबरों को 'सिरे से खारिज' करने की कोशिश की। हालांकि, यह स्वीकार किया कि ईरानी और अमेरिकी विमानों ने वार्ता प्रक्रिया से जुड़े लोगों की आवाजाही के लिए पाकिस्तान के एयरस्पेस और एयरबेस का इस्तेमाल किया था।

अमेरिका में पाकिस्तान के प्रति अविश्वास बढ़ा

इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर संदेह गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका की समीक्षा की मांग की है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के भीतर भी यह चिंता बढ़ रही है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की वास्तविक स्थिति सही तरीके से साझा नहीं कर रहा है।

'भारत की प्राचीन गणितीय विरासत ने रखी आधुनिक विज्ञान की नींव'

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि वैज्ञानिक प्रगति को लंबे समय से 'संकीर्ण दृष्टिकोण' से देखा गया है जबकि जबकि भारत की प्राचीन गणितीय विरासत आधुनिक विज्ञान और तकनीक की नींव है। उन्होंने ऐतिहासिक गलत धारणाओं को 'ठीक' करने और भारत के योगदान को मान्यता देने पर जोर दिया। जयशंकर ने गणित के क्षेत्र में भारत के योगदान को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा आयोजित 'शून्य से अनंत तक - गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान' शीर्षक वाली प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किया है।

जयशंकर ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपनी तरह की पहली गणितीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा, भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण राजनीतिक और आर्थिक अदलाव हो रहा है, और यह अनिवार्य रूप से सांस्कृतिक पुनर्संतुलन का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। यह प्रदर्शनी 'सम्हिता' (दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों का इतिहास और दस्तावेज संग्रह) परियोजना का हिस्सा है।

यह प्रदर्शनी गणित के क्षेत्र भारत के योगदान को दर्शाती है। भारत की प्राचीन गणितीय अवधारणाएं सहस्राब्दियों से दुनियाभर में फैली हैं।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित गणितीय प्रदर्शनी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर। प्रेट्र

अमेरिकी शहर की मेयर निकली चीन की एजेंट, दिया इस्तीफा

न्यूयार्क टाइम्स से

वाशिंगटन: अमेरिका में कैलिफोर्निया प्रांत के अर्कांडिया शहर की मेयर ईलीन वांग चीन की एजेंट पाई गई है। वांग ने चीन के एजेंट के रूप में काम करने का जुर्म स्वीकार कर लिया है और मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में वांग को अधिकतम दस वर्ष जेल की सजा हो सकती है।

ईलीन वांग। फाइल

संघीय अभियोजकों ने सोमवार को बताया कि 58 वर्षीय ईलीन वांग और उसके 65 वर्षीय पूर्व मंगेतर माइक सन पर चीनी सरकार के अधिकारियों के कहने पर अमेरिका में चीन के समर्थन में प्रचार करने का आरोप लगाया गया है।

अपनी ही पार्टी में घिरे ब्रिटिश पीएम स्टार्मर, पद छोड़ने का बढ़ा दबाव

न्यूयार्क टाइम्स से

- पीएम पर दबाव बनाने को तीन जूनियर मंत्रियों का त्यागपत्र
- 80 लेबर सांसदों ने कहा, पद छोड़ने की तिथि बताएं स्टार्मर

लंदन: ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। उनकी लेबर पार्टी के कई सांसदों और मंत्रियों ने इस्तीफे की मांग की है। हालांकि उन्होंने इस्तीफे की मांग को ठुकरा दिया है और पार्टी के अंदर अपने खिलाफ उठती आवाज को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टार्मर सरकार के तीन जूनियर मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और पीएम से भी ऐसा ही करने की अपील की है।

स्टार्मर ने सोमवार को माना कि पिछले सप्ताह इंग्लैंड, स्काटलैंड और वेल्स में हुए चुनावों में लेबर पार्टी के उम्मीदवारों को मतदाताओं ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह दुखद है। मैं इसे महसूस करता हूं और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। रायटर के अनुसार, 80 से अधिक लेबर सांसदों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे एक नई शुरुआत चाहते हैं।

दावेदारों में ये नेता शामिल: अगर स्टार्मर हटते हैं तो लेबर पार्टी के नेता के रूप में कई लोग दावेदार हो सकते हैं। इनमें सबसे आगे ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम बताए गए हैं। वह पार्टी में काफी लोकप्रिय बताए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग और पूर्व उप नेता एंजेला रेनर को भी दावेदारों में गिना जा रहा है। हालांकि किसी भी दावेदार को लेबर पार्टी के 81 सांसदों (कुल का 20 प्रतिशत) की जरूरत पड़ेगी और अंतिम फैसला सदस्य लेंगे।

युद्धविराम खत्म, रूस-यूक्रेन में फिर छिड़ा युद्ध

कीव, रायटर : रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन का युद्धविराम सोमवार मध्यरात्रि औपचारिक रूप से खत्म हो गया यद्यपि दोनों देशों की सेनाओं में उस दौरान भी लड़ाई होती रही। युद्धविराम खत्म होते ही सोमवार-मंगलवार रात रूस ने यूक्रेनी शहरों पर 216 ड्रोन हमले किए। इन हमलों से कीव और कुछ अन्य स्थानों में आग लग गई। एक व्यक्ति की मौत हुई और छह घायल हुए हैं। नागरिक सुविधाओं और बच्चों के स्कूल को भी निशाना बनाया गया।

यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने बताया है कि उनके देश ने युद्धविराम को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन रूस उससे सहमत नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस युद्धविराम को बढ़ाए जाने की इच्छा जताई थी। उनकी मध्यस्थता में ही रूस और यूक्रेन युद्धविराम के लिए सहमत हुए थे। इस बीच रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होने की संभावना व्यक्त की है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 13 मई, 2026

दैनिक जागरण

न सुख स्थायी होता और न दुख

परीक्षार्थियों से खिलवाड़

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की पात्रता परीक्षा नीट के प्रश्नपत्र लीक होने से पूरी परीक्षा रद करने की मजबूरी जितनी शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक। यह परीक्षा इसलिए रद करनी पड़ी, क्योंकि राजस्थान पुलिस को कुछ छात्रों के पास से ऐसे गेस पेपर मिले, जिनके 410 प्रश्नों में से 140 से अधिक परीक्षा के मूल प्रश्नों से हूबहू मिल रहे थे। साफ है कि परीक्षाओं में सेंध लगाने वालों ने परीक्षा के पहले ही कहीं से प्रश्नपत्र हासिल कर लिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई और शीघ्र ही नीट का दोबारा आयोजन किया जाएगा, क्योंकि 22 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। इतनी बड़ी परीक्षा फिर से कराने का मतलब है छात्रों के साथ सरकार के समय और संसाधन की बर्बादी। छात्रों को मानसिक रूप से जो परेशानी उठानी पड़ी, उसकी तो क्षतिपूर्ति करना ही कठिन है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का गठन ही इसलिए हुआ था कि प्रतियोगी परीक्षाएं नीर-क्षीर ढंग से हों, वह अपने उद्देश्य में नाकाम सिद्ध हो रही है। नीट में गड़बड़ी और अव्यवस्था के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं।

गत वर्षों में कई बार इस परीक्षा में सेंध लगने के आरोप लगे और दो वर्ष पहले तो इन आरोपों ने इतना तूल पकड़ा कि एनटीए को कुछ केंद्रों की परीक्षा रद करके दोबारा करानी पड़ी थी। अतीत में एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली कुछ और परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां हो चुकी हैं या फिर धांधली की आशंका के चलते उन्हें टालना पड़ा है। स्पष्ट है कि यह एजेंसी कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को इसकी तह तक जाना होगा कि ऐसा क्यों है? उसे इसका आभास होना चाहिए कि एनटीए के साथ उसकी साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर इंटरनेट और कंप्यूटर के इस युग में किसी परीक्षा के प्रश्नपत्र मुद्रित कर उन्हें देश भर के सैकड़ों केंद्रों में भेजने की पुराने जमाने की प्रक्रिया क्यों जारी है? इस प्रक्रिया में तो कहीं पर भी सेंध लग सकती है? यह समझना भी कठिन है कि जिस परीक्षा में लाखों छात्र बैठते हों, उसके प्रश्नपत्र के कई सेट क्यों नहीं तैयार किए जाते, ताकि यदि कभी कहीं प्रश्नपत्र लीक भी हो जाएं तो पूरी परीक्षा न रद करनी पड़े। एनटीए का काम इसलिए संतोषजनक नहीं, क्योंकि वह पुराने तौर-तरीकों से काम कर रही है और अपने तंत्र को इसके लिए प्रेरित नहीं कर पा रही कि वह विश्व की प्रतिष्ठित और भरोसेमंद परीक्षाओं से कोई सीख ले। दुर्भाग्य से यही स्थिति प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली अन्य संस्थाओं की भी है। इसी कारण प्रश्नपत्र लीक होने का सिलसिला कायम है।

जाम से जूझते शहर

उत्तराखंड में प्रमुख शहरों को जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। प्रयोग-दर-प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। कह सकते हैं कि समस्या और विकराल रूप लेती जा रही है। देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल हो या फिर अन्य शहर, इन सभी में पूरे दिन जाम लगना सामान्य बात हो गई है। सप्ताहांत पर तो हालात और अधिक खराब हो जाते हैं। कई शहरों में तो पांच से आठ किलोमीटर तक लंबा जाम पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की परीक्षा लेने लगता है। परिदृश्य पर नजर डालें तो प्रदेश में यातायात प्रबंधन के लिए न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही उपलब्ध संसाधनों का ठीक से उपयोग करने की कोई प्रभावी योजना नजर आती है। किन शहरों में जाम की समस्या अधिक है, यह सभी को मालूम हैं। लेकिन विडंबना यह कि स्थानीय प्रशासन यातायात प्रबंधन में नाकाम रहता है। यहां जाम स्थलों पर यातायात पुलिस नजर ही नहीं आती है। एकाध जगह होमगार्ड जरूर दिख जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। वीकेंड और अन्य अवसरों के लिए स्थानीय प्रशासन बाकायदा यातायात प्लान जारी करता है, लेकिन उसे लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं दिखती है। कई बार अव्यावहारिक प्लान जारी कर दिया जाता है, इससे दिक्कत और बढ़ जाती हैं। आला अधिकारियों को इस पर गौर जरूर करना चाहिए। यातायात प्रबंधन के लिए जरूरी है कि उपलब्ध संसाधनों का ठीक से उपयोग किया जाए। अगर इसमें विशेषज्ञों की मदद भी लेने पड़े तो परहेज नहीं किया जाना चाहिए।

> शहरों को जाम से निजात दिलाने के लिए मशीनरी को मूकदर्शक बने रहने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा

और सशक्त हो परमाणु आवरण

दिव्य कुमार सोती

पोखरण परीक्षणों के करीब तीन दशक बाद भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह बदले हुए परिदृश्य में नए सिरे से परमाणु परीक्षण पर विचार करे

अवधेश राजपूत

हाल में भारत के परमाणु कार्यक्रम ने एक मील का पत्थर तब पार किया, जब कलपक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त की। 'क्रिटिकलिटी' वह स्थिति है जब परमाणु विखंडन की शृंखला प्रक्रिया आत्मनिर्भर हो जाती है। इस स्वदेशी तकनीक पर आधारित उपलब्धि के साथ ही भारत ने 1950 में होमी भाभा द्वारा तैयार किए गए त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण पूरा कर लिया, जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा संयंत्र जितना परमाणु ईंधन खर्च करता है, उससे अधिक उत्पादन करने की क्षमता रखता है। इस चरण में बनने वाले यूरेनियम-233 को तीसरे चरण में थोरियम-232 के साथ उपयोग करने पर यह और अधिक यूरेनियम-233 बनाता है और अंततः इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए मात्र थोरियम की ही आवश्यकता रह जाती है। इसका महत्व इससे और बढ़ जाता है कि दुनिया भर में थोरियम का एक चौथाई भंडार भारत के पास है। इस परमाणु कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा होने पर भारत अगले अनेक दशकों तक थोरियम से ऊर्जा का उत्पादन करता रह सकता है। अभी व्यावसायिक उपयोग हेतु उर्जा उत्पादन के लिए रूस और भारत ही दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का संचालन कर रहे हैं।

निःसंदेह कलपक्कम में प्राप्त हुई सफलता नागरिक उपयोग हेतु परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अप्रतिम उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े। हमने आज तक दो ही बार परमाणु परीक्षण किए हैं। पहली बार वर्ष मई 1974 में और अंतिम बार परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 में किए थे। 1974 के परीक्षणों में मात्र एक डिवाइस का परीक्षण किया गया था, वहीं 1998 में परीक्षणों में पहले दिन तीन और फिर दो न्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण किया गया। 1998 में पहले दिन परीक्षण की गई शक्ति-1 की क्षमता भारत के दावे के अनुसार 58 किलोटन रही थी। जबकि अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का आकलन इसके लगभग 40 किलोटन रहने का था। अगर सरकार के दावे को भी सही मानें तो यह इसलिए चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि चीन के पास 650 किलोटन से लेकर 3-4 मेगाटन के परमाणु हथियार हैं। चीन के हल्के परमाणु हथियार भी 150 किलोटन क्षमता के हैं।

परीक्षण ही किसी वैज्ञानिक क्षमता को हासिल कर लेने का प्रमाण होता है। यही कारण है कि अमेरिका ने आज तक लगभग 1000 से अधिक, रूस ने 715 और चीन ने 45 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। इसके विपरीत भारत ने बेहद कम क्षमता के बस छह परमाणु परीक्षण ही किए हैं। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से परमाणु परीक्षण करने की बात कही थी। यदि अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो फिर रूस भी पीछे नहीं रहने वाला। ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान गुप्त रूप से भूमिगत परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। चीन पिछले कई वर्षों से गुपचुप तरीके से छोटे परमाणु परीक्षण करने में लगा हुआ है। 2024-25 में उसने परमाणु बम बनाए। मिसाइल प्रतिरोधक प्रणालियों की बढ़ती क्षमताओं और चीन के आबादी बहुल क्षेत्रों का भारतीय सीमा से बहुत दूर स्थित होने, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में हमसे कहीं आगे होने जैसे पहलुओं को देखते हुए भारत के लिए चीन के सापेक्ष भरोसेमंद परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम का विस्तार आवश्यक है।

हमें सामरिक तैयारी और मजबूत करनी होगी। यह न भूला जाए कि 2021 में लक्षद्वीप में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जोन पोल जोंस अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए भारत के एक्सक्लूसिव इकोनोमिक जोन में घुस आया था। बीते दिनों भी भारत से युद्धाभ्यास कर लौट रहे ईरानी नौसेना के जहाज को श्रीलंका के पास अमेरिकी नौसेना ने डुबो दिया था। यह भी ध्यान रहे कि अमेरिका हमारे पड़ोसी देशों में भारत विरोधी शक्तियों को वैसे ही हवा दे रहा है, जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध छिड़ने से पहले उसने रूस के पड़ोसी देशों में रूस के विरुद्ध दी थी। इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि अमेरिकी आक्रामकता से निपटने के लिए रूस ने भी स्मार्ट परमाणु हथियारों के विकास और परीक्षण का ही रास्ता चुना है। उसने परमाणु ऊर्जा से संचालित ब्यूरेवेस्टनिक नाइन एम 730 क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, जो बेहद कम ऊंचाई जैसे मात्र 50 से 100 मीटर पर हफ्तों तक उड़ान भरती रही सकती है, क्योंकि इसके अंदर लगा बेहद छोटा परमाणु संयंत्र इसे बहुत लंबे समय तक ऊर्जा मुहैया कराता रहता है। असीमित ईंधन होने के चलते वह सीधे रास्ते के बजाय चक्कर काटकर या समुद्र के ऊपर से घूमकर किसी भी दिशा से लक्ष्य पर हमला कर सकती है। मौजूदा मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालियां उसे रोक नहीं सकतीं। अक्टूबर 2025 में किए गए परीक्षण में इस मिसाइल ने लगातार 15 घंटों तक उड़ान भरी और 14,000 किमी की दूरी तय की। रूस द्वारा विकसित पोसीडान को भी दुनिया का सबसे अनोखा और खतरनाक परमाणु हथियार माना जाता है। यह एक विशाल परमाणु-संचालित अंतरमहाद्वीपीय टारपीडो है। इसमें लगा छोटा परमाणु रिएक्टर इसे असीमित दूरी तक ले जाने की क्षमता देता है और यह हफ्तों तक एक किमी से अधिक की गहराई पर समुद्र में विचरण करता रह सकता है। इसके प्रहार से ऐसी सुनामी लहरें पैदा हो सकती हैं जो न्यूयार्क या लंदन सरीखे तटीय शहरों को पूरी तरह तबाह कर सकती हैं और उस पूरे इलाके को दशकों के लिए रेडियोधर्मी प्रदूषण से अनुपयोगी बना सकती हैं। पोखरण परीक्षणों के लगभग तीन दशक बाद भारत के लिए भी आवश्यक हो जाता है कि वह बदले हुए परिदृश्य को देखते हुए नए सिरे से परमाणु परीक्षण करे। इसके साथ ही मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालियों को चकमा देने वाले स्मार्ट परमाणु हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों का विकास भी उतना ही आवश्यक है।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

बंगाल में जंगलराज का खात्मा

राजीव सचान

ममता बनर्जी का कुशासन एक किस्म का जंगलराज ही था और कुछ मायनों में तो यह बिहार से भी बदतर था

जब भी जंगलराज का उल्लेख होता है तो उस दौर के बिहार का स्मरण हो आता है, जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके मुख्यमंत्री रहते समय बिहार अराजकता को लेकर इस कदर बदनाम हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल को उसके दुष्परिणाम आज तक भोगने पड़ रहे हैं। चुनावों के समय राजद के विरोधी दल लोगों को लालू के जंगलराज के भयावह दिनों की याद दिलाते हैं और इतने से ही उनका काम आसान हो जाता है। इसका कारण यह है कि बिहार के लोग यह भूल नहीं सके हैं कि लालू यादव के शासनकाल में किस तरह अपहरण और फिरौती ने उद्योग का रूप ले लिया था और राज्य के अनेक शहरों में भी सांझ ढलते ही कैसा सन्नाटा छा जाता था। बिहार के लोग यह भी नहीं भूले हैं कि शहाबुद्दीन सरीखे माफिया का कैसा आतंक था और उनके जैसे बाहुबलियों को किस प्रकार लालू का संरक्षण प्राप्त था। जैसे यह पता नहीं कि बिहार राजद के जंगलराज की यादों से कब मुक्त होगा, वैसे ही यह कहना भी कठिन है कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के कुशासन की पराकाष्ठा को कब तक भूल सकेगा? यह कुशासन एक किस्म का जंगलराज ही था और कुछ मायनों में तो बिहार से भी बदतर था।

लालू यादव का शासन इसलिए जंगलराज के रूप में कुख्यात हुआ, क्योंकि अगस्त 1997 में किसी मामले को लेकर पटना उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी कर दी थी, 'बिहार में कोई सरकार नहीं है, यह जंगलराज से भी खराब है।" ऐसी कोई टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता शासन को लेकर तो नहीं की, पर हिंसा और भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर उसने उसे न जाने कितनी बार फटकार लगाई, वह चाहे 2021 की चुनाव बाद की हिंसा रही हो या आरजी कर अस्पताल कांड या फिर शिक्षक भर्ती घोटाला। अभी हाल में ममता सरकार को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन न देने के लिए फटकार लगी। ममता सरकार को कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार फटकार लगी। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हिंसा के चलते जो लोग अपना घर-बार छोड़ने के लिए

पराजय के बाद वीरान पड़ा तृणमूल कार्यालय। फाइल

असम में शरण लेने को मजबूर हुए थे, उनमें से कुछ तो महीनों तक अपने घरों को लौट नहीं सके थे। यह हिंसा इतनी खुली और भीषण थी कि यदि नेहरू और इंदिरा का जमाना होता तो शायद ममता के शपथग्रहण के पहले ही राष्ट्रपति शासन लग जाता। न्यायपालिका के आदेश पर इस भीषण हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की थी, क्योंकि जब यह हिंसा हो रही थी तो पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। इस आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं, बल्कि शासकों का कानून लागू है। अराजकता के मामले में संदेशखाली की हिंसा को भी नहीं भूला जा सकता।

अराजकता को बयान करने वाली मुर्शिदाबाद की घटना को भी नहीं भूला जा सकता। वक्फ कानून के कथित विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जमकर नंगा नाच किया गया। तब उपद्रवी तत्वों के आतंक से डरे हुए लोगों ने असम और झारखंड जाकर अपनी जान बचाई थी। ममता के शासन के समय टीएमसी के बाहुबली नेताओं-कार्यकर्ताओं और उनके द्वारा संरक्षित गुंडों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ा हुआ था कि वे पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को भी निशाना बनाने में संकोच नहीं करते थे। वे हर किसी से अवैध वसूली, उगाही करते थे। बंगाल में यह कट मनी यानी कमीशनखोरी और तोलाबाजी यानी अवैध वसूली के रूप में कुख्यात थी। बंगाल से गुजरने वाला कोई मालवाहक वाहन अवैध वसूली से बच नहीं पाता था। इसी तरह दो-चार सौ रुपये रोज कमाने वाले फुटपाथ दुकानदार भी हफ्ता वसूली के शिकार थे। लोग टीएमसी नेताओं को पैसे दिए बिना न तो जमीन खरीद सकते थे और न ही घर बनवाने के लिए सामग्री। इस सबसे ममता अनजान नहीं थीं और इसका प्रमाण यह है कि 2019 में उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी पार्टी में चोर नहीं चाहिए और जिन्होंने भी कट मनी वसूली है, उसे वे वापस करें।

ममता के 15 वर्षों के शासन में ऐसी न जाने कितनी घटनाएं घटीं, जिनसे राज्य सरकार की बदनामी हुई, लेकिन इस सबके बाद भी उनके कुशासन को कभी जंगलराज की संज्ञा नहीं मिली। इसका कारण यह रहा कि दिल्ली और कोलकाता के मीडिया का एक हिस्सा उन्हें सदैव फाइटर की संज्ञा देता रहा और बड़ी सेक्युलर नेता के तौर पर रेखांकित करता रहा। चूंकि ममता सेक्युलर नेता मानी जाती थीं, इसलिए लिबरल किस्म के लोगों ने यह देखने की चेष्टा ही नहीं की कि वे किस तरह अल्पसंख्यकों और यहां तक कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के तुष्टीकरण में लिप्त हैं और उन्होंने अपने कैडर को किस प्रकार मनमानी करने की छूट दे रखी है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद उत्साहित, भावुक और ममता के शासनकाल में प्रताड़ित अथवा पलायन करने को मजबूर हुए लोगों की जैसी खबरे आ रहे हैं, वे यही कह रहे हैं कि ममता का शासन निरंकुशता का खौफनाक पर्याय बनकर रह गया था।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

ज्ञान का संचय

जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए लोग नाना प्रकार के भौतिक संसाधनों का संचय करते हैं। यद्यपि इन वस्तुओं से परे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संचय भी उतना ही आवश्यक होता है और वह है ज्ञान का संचय। धन का संचय आपको अभिमानी तो वस्तुओं का संचय आपको लालची बना देता है, किंतु ज्ञान का संचय आपको इन दुर्गुणों से सदा ही दूर रखता है। ज्ञान चक्षु सदा खुले रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्ञान रूपी सागर में हमेशा गोते लगाते रहें।

समय के साथ भौतिक संसाधन तो नष्ट हो सकते हैं, किंतु अर्जित ज्ञान को कोई आपसे नहीं छीन सकता। ज्ञानार्जन के साथ यह भी स्मरण रहे कि हमारे भीतर अभिमान लेशमात्र भी जगह न बना पाए, क्योंकि ज्ञान जब अभिमान का चोला पहन लेता है तो हमारे उस संचय का क्षय होने लगता है। ज्ञान के संचय का क्षय होना इस बात का भी सूचक है कि हम उन अमूल्य बातों को धारण करने की योग्यता अब नहीं रखते। ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र भी नहीं होती और इसका आदान-प्रदान अंत समय तक संभव है। रावण ने भी मरते-मरते लक्ष्मण को ज्ञान से समृद्ध किया। भीष्म पितामह ने भी मृत्यशैया पर अपने प्रियजनों को जीवन के कुछ उपयोगी सूत्र दिए। जब किसी से कुछ ज्ञान ग्रहण करना होता है तो उसमें कृतज्ञता का भाव निश्चित ही होना चाहिए, क्योंकि तब कोई अपने समय और ऊर्जा से आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है।

ज्ञान ही आपकी हर समस्या की कुंजी है, फिर चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियों से आपका सामना हो रहा हो। ज्ञान की अनुभूति का भाव व्यक्ति को सही मार्ग से विचलित नहीं होने देता। समय के साथ बढ़ता अनुभव भी ज्ञान की धारा को और प्रखर बनाता है, जो जीवन की नैया को आगे बढ़ाने में पतवार की भूमिका निभाता है।

पारुल हर्ष बंसल

रैट-होल खनन से पर्यावरण को खतरा

सुधीर कुमार

रैट-होल खनन कोयला निकालने का एक पारंपरिक और अवैज्ञानिक तरीका है

मेघालय में टर्शियरी युग के कोयले का अकूत भंडार है। लेकिन अवैज्ञानिक खनन के तरीकों और विशेषकर प्रतिबंधित रैट-होल खनन के चोरी-छिपे प्रचलन से न केवल श्रमिकों की जान जा रही है, बल्कि बालश्रम को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ पर्यावरण निम्नीकरण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।

रैट-होल खनन कोयला निकालने का एक पारंपरिक और अवैज्ञानिक तरीका है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले सतह की वनस्पतियों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है, तत्पश्चात कोयला के भंडार तक पहुंचने के लिए चार-पांच फीट सुरंग बनाई जाती है। इसी सुरंग के जरिये श्रमिक कोयला प्राप्त करते हैं। यह सुरंग इतना पतला होता है कि इसमें मजदूरों को मुश्किल से रेंगकर अंदर-बाहर आना-जाना पड़ता है। इस दौरान होने वाले हादसों से आए दिन श्रमिकों को जान गंवानी पड़ती है। इसमें खराब निकास व्यवस्था के कारण दम घुटना, संरचनात्मक समर्थन की कमी के कारण खदानों का ढहना और बाढ़ आना आदि खतरे शामिल हैं। इसी वर्ष फरवरी माह में मेघालय के पूर्वी जयंतिया पहाड़ी में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान में डायनामाइट विस्फोट के कारण 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। रैट-होल खनन के इन्हीं खतरों को देखते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने 2014 में ही इसे अवैज्ञानिक और श्रमिकों के लिए असुरक्षित बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि यह आज भी प्रचलन में है, जिससे न सिर्फ श्रमिकों की जान खतरे में होती है, बल्कि इसमें बड़ी संख्या में बाल-श्रमिकों का इस्तेमाल भी चिंतित करती है। बच्चे इन पतली सुरंगों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और कम मजदूरी दर पर उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण उनका इस्तेमाल बहुतायत में किया जाता है। हालांकि अवैज्ञानिक खनन का यह स्वरूप पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। दरअसल राज्य के विभिन्न हिस्सों में चल रहे अवैध रैट-होल खनन से वनों की कटाई और भूमि क्षरण तथा खनन अपशिष्टों के जलस्रोतों में मिलने से जल प्रदूषण और जल में आक्सीजन में कमी का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मेघालय की दो नदियां-लूखा और म्यंटडू इतनी अम्लीय हो गई हैं कि उनमें जलीय जीवन का अस्तित्व संभव नहीं रह गया है।

संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने और अनुच्छेद 244 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त होने के कारण मेघालय में राष्ट्रीय खनन कानूनों को लागू करने में कई जटिलताएं हैं। ऐसे में यहां के भूस्वामी ही नीचे मौजूद खनिजों के भी स्वामी माने जाते हैं, जिससे रैट-होल खनन को बढ़ावा मिला है। इस खनन के दुष्प्रभावों को लेकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर हैं। ऐसे में जरूरी है कि श्रमिकों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और यहां के नागरिक भी संजीदगी दिखाए।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

साझा प्रयासों से मिलेगी सफलता

'उचित अपील पर आपत्ति' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में विदेशी मुद्रा से आयातित वस्तुओं के संयमित इस्तेमाल के लिए प्रधानमंत्री की अपील पर विपक्षी नेताओं की आपत्ति को अनुचित, गैर-जिम्मेदाराना और पूर्वाग्रह से ओतप्रोत बताया गया है। वैश्विक परिस्थितियों में भारत पर भी संकट के बादल मंडरा रहे है। इसके बावजूद अभी तक अर्थव्यवस्था में भूचाल जैसी परिस्थितियां नहीं बनी हैं। भारत ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखते हुए किसी तरह स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा सोना, तेल के आयात में खर्च होता है, लेकिन मौजूदा युद्ध संकट के कारण उनकी आपूर्ति भी बाधित हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप खपत के अनुरूप वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में नागरिकों द्वारा बचत करना और संयमित उपयोग करना राष्ट्रहित में है। विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी, नाकामी और नागरिक विरोधी बताने पर तुला हुआ है, लेकिन यह देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने, स्थिर रखने और वर्तमान चुनौतीपूर्ण स्थितियों में आमजन से अपेक्षित व्यावहारिक कदम ही हैं। हालांकि सरकार से जुड़े लोगों को भी अपने कार्य एवं व्यवहार से किफायत का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा ऐसे सुझाव और निर्देश केवल दिखावटी ही साबित होंगे और जनता को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। नागरिकों का भी नैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दायित्व है कि वे संयमित व्यवहार अपनाए और राष्ट्र के समक्ष चुनौती में सरकार के साथ कदमताल मिलाए।

मोहित सोनी, कुक्षी, मध्यप्रदेश

मेलबाक्स

परीक्षा एजेंसियों का कुप्रबंधन

देश में बार-बार नीट जैसी प्रमुख परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होना और लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना सीधे तौर पर सरकार और उसके अधीन कार्यरत परीक्षा एजेंसियों के कुप्रबंधन की ओर इशारा करता है। आखिर प्रश्नपत्र कैसे और क्यों लीक हो जाते हैं? यदि एक-दो परीक्षाओं में ऐसा होता, तो इसे संयोग माना जा सकता था, लेकिन प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का बार-बार लीक होना उन लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है, जिनकी वर्षों की मेहनत कुछ लोगों की लापरवाही और भ्रष्ट व्यवस्था के कारण पानी की तरह बह जाती है। इससे न केवल लाखों रुपये की फीस व्यर्थ जाती है, बल्कि अभ्यर्थियों की आशाएं, सपने और अभिभावकों का विश्वास भी चकनाचूर हो जाता है। दुखद यह है कि ऐसे मामलों में राज्य और केंद्र के शिक्षामंत्री भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते। जांच समितियां बनती हैं, मामले सुर्खियों में आते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ फाइलें धूल फांकने लगती हैं। यदि प्रश्नपत्र लीक होने के इतिहास के पन्ने पलटे जाएं, तो ऐसी घटनाओं की लंबी फेहरिस्त सामने आ जाएगी। यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। सरकार को चाहिए कि वह परीक्षा एजेंसियों के कुप्रबंधन को सख्ती से सुधारे और इस प्रकार के अपराध में शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। साथ ही ऐसी प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे भविष्य में लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर (मप्र)

जनसहयोग की शक्ति

जब-जब देश कठिन परिस्थितियों से गुजरा, तब-तब सरकारों ने जनता के सहयोग को सबसे बड़ी शक्ति माना। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने और अन्न बचाने की अपील की थी। आज पेट्रोलियम संकट और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील भी उसी परंपरा का विस्तार है। लोकतंत्र केवल अधिकारों का नाम नहीं, बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। जनता और सरकार के बीच विश्वास ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है।

आशुतोष पांडेय, सीतापुर, यूपी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशनलि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

चिंतन

नीट परीक्षा की शुचिता पर फिर उठे सवाल

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 का रद्द होना केवल एक परीक्षा का स्थगन नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की शुचिता पर उठा बड़ा सवाल है। हरियाणा के गुरुग्राम, बिहार के नालंदा और राजस्थान के सीकर से सामने आए तथ्यों ने पूरे देश को चौंका दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से अधिक प्रश्न हाथ से लिखे गए एक कथित 'क्वेश्चन बैंक' में मिले, जिनमें से करीब 150 सवाल हूबहू नीट परीक्षा में पूछे गए। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी कोचिंग सामग्री या संभावित प्रश्न बैंक से कुछ प्रश्न मिल जाना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन 720 में से लगभग 600 अंकों के प्रश्न एक ही स्रोत से आ जाना सीधे-सीधे संगठित फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली परीक्षा में यह सेंध लगी कैसे? एनटीए वर्षों से दावा करता रहा है कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, जीपीएस ट्रैकिंग, एआई-आधारित मॉनिटरिंग और 5जी जैमर जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब परीक्षा से पहले ही कथित प्रश्नपत्र व्हाट्सएप ग्रुपों में घूमने लगें, तो यह तकनीकी दावों की पोल खोल देता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि खतरा परीक्षा केंद्रों पर बैठा छात्र नहीं, बल्कि वह "घर का भेदी" है जो प्रिंटिंग प्रेस, डेटा सिस्टम या एजेंसी के भीतर बैठकर पूरी व्यवस्था को बेच रहा है। नीट परीक्षा का रद्द होना लाखों छात्रों के लिए मानसिक आघात है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दो-दो साल तक कोचिंग में दिन-रात मेहनत की, जिन्होंने परिवार की आर्थिक सीमाओं के बावजूद सपनों को जिंदा रखा, आज वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। परीक्षा रद्द होने का अर्थ केवल दोबारा परीक्षा देना नहीं होता; इसका मतलब है तनाव, अवसाद, आर्थिक बोझ और भविष्य की अनिश्चितता। ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह पीड़ा और भी बड़ी है, क्योंकि उनके लिए हर अतिरिक्त महीना आर्थिक दबाव लेकर आता है। यह भी सच है कि इस पूरे भ्रष्ट तंत्र को केवल परीक्षा एजेंसी की कमजोरी ने जन्म नहीं दिया। निजी मेडिकल कॉलेजों की करोड़ों की फीस, कोचिंग उद्योग का अरबों का कारोबार और सरकारी सीटों की सीमित संख्या ने एक ऐसा बाजार खड़ा कर दिया है, जहां सफलता को मेहनत से ज्यादा "मैनेजमेंट" से जोड़कर देखा जाने लगा है। जब एक मेडिकल सीट की कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है, तब पेपर लीक माफिया के लिए यह सबसे लाभकारी धंधा बन जाता है। पिछले कुछ वर्षों में लगभग हर बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षा पर सवाल उठे हैं। कभी एसएससी, कभी रेलवे भर्ती, कभी शिक्षक पात्रता परीक्षा और अब नीट। हर बार जांच समितियां बनती हैं, कुछ गिरफ्तारी होती हैं, लेकिन सिस्टम जस का तस बना रहता है। यदि सरकार वास्तव में परीक्षा माफिया को खत्म करना चाहती है, तो उसे केवल निचले स्तर के दलालों को पकड़ने से आगे बढ़ना होगा। उन अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों और संस्थागत नेटवर्क तक पहुंचना होगा जो इस पूरे खेल को संरक्षण देते हैं। अब समय केवल बयानबाजी का नहीं, कठोर सुधारों का है। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह विकेंद्रीकृत और पारदर्शी बनाना होगा। प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर प्रिंटिंग और वितरण तक हर चरण की स्वतंत्र ऑडिटिंग होनी चाहिए। संवेदनशील जिम्मेदारियों में शामिल कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो और दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा मिले। साथ ही, परीक्षा प्रणाली को तकनीक पर निर्भर बनाने के साथ-साथ मानव निगरानी और नैतिक जवाबदेही भी मजबूत करनी होगी।

मंथन

मनोज कुमार अग्रवाल

नाजुक वक्त में काबिले गौर है पीएम की सलाह

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के अवरुद्ध होने से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने में भारत सरकार का कुशल प्रबंधन दुनिया के प्रभावित देशों के लिए एक मिसाल बन गया है, लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका और इजराइल-ईरान के बीच जो हालात बने हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट मार्ग निर्बाध खुलने की संभावना नहीं है, जिसके चलते सरकार को उर्जा संकट से निपटने के लिए मौजूदा संसाधनों की समीक्षा और उर्जा जरूरतों के प्रबंधन की दीर्घकालिक नीति बनानी पड़ रही है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आमजन से यह सात सूत्रीय अपील की है। जो देश को ऊर्जा संकट से बचा सकती है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हैदराबाद के संबोधन में देशवासियों को ऊर्जा संकट के इस दौर में ऊर्जा सुरक्षा संयमित उपयोग कर कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक किया है। पीएम की इस 7 सूत्री अपील में न सिर्फ आम जन के बीच संकट की हालत में मनोबल और विश्वास बने रहने की प्रेरणा है साथ ही संकट से निपटने का मूलमंत्र भी है। सरकार वैश्विक संकट के इस दौर में नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनकर डटी रही आयातित तेल पर भारी दाम वृद्धि को सरकार ने 24 से 30 रुपये प्रति लीटर भार वहन किया है पैट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये से घटित कर तीन रुपये लीटर कर दिया, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क खत्म कर दिया है। आपको पता है कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के अवरुद्ध होने से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने में भारत सरकार का कुशल प्रबंधन दुनिया के प्रभावित देशों के लिए एक मिसाल बन गया है लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका और इजराइल-ईरान के बीच जो हालात बने हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट मार्ग निर्बाध खुलने की संभावना नहीं है। जिसके चलते सरकार को उर्जा संकट से निपटने के लिए मौजूदा संसाधनों की समीक्षा और उर्जा जरूरतों के प्रबंधन की दीर्घकालिक नीति बनानी पड़ रही है पूर्व तक यह अनुमान था कि होरमुज मार्ग का विवाद जल्द सुलझ जाएगा और स्थिति पूर्ववत सामान्य हो जाएगी लेकिन अब ऐसा नहीं है।

आपको बता दें कि होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकीर्ण मार्ग है, जिससे भारत अपनी 90 फ़ीसदी से अधिक एलपीजी और लगभग 40 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में, जब दुनिया भर में ईंधन की भारी कमी और कीमतों में आग लगने का अंदेशा था, भारत सरकार ने दूरदर्शिता, कूटनीतिक कुशलता और त्वरित रणनीतिक निर्णयों से देश में ऊर्जा की सुव्यवस्था बनाए रखी बल्कि आम जनता पर बढ़ी कीमतों का भार भी नहीं बढने दिया। संकट का संकेत मिलते ही भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को क्रियान्वित करते हुए न केवल वैकल्पिक स्रोत तलाशे बल्कि घरेलू संसाधनों को भी मजबूत किया। भारत सरकार के कुशल प्रबंधन और कूटनीतिक संबंधों की बदौलत देश ने उस समय भी डीजल पेट्रोल और एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं होने दी जब की देशों में बेहद परेशानी और किल्लत खड़ी हो गई थी स्पेन मिस्त्र श्रीलंका दक्षिण कोरिया फिलीपींस जापान पाकिस्तान बांग्लादेश आदि में वहां की सरकारों ने ईंधन राशनिंग, वर्क फ्रॉम होम, फ्यूल पास, स्कूल बंद जैसे अनेक प्रतिबंध भरे कदम उठाए लेकिन भारत सरकार की सूझ-बूझ और प्लानिंग के चलते ईंधन राशनिंग नहीं हुई, स्कूल बसों, वाहनों व परिवहन यातायात की गाड़ियों को मांग के अनुरूप फ्यूल मिलते रहने से कोई स्कूल बंदी नहीं हुई और न ही कोई दफ्तर बन्द करने पड़े। तमाम दफ्तर सामान्य तौर पर कार्यरत रहे जिससे कोई वर्क-फ्रॉम-होम निर्देश पारित करने की नौबत नहीं आने पाई। देश भर में खुदरा ईंधन की स्थिर आपूर्ति बनाए रखी गई। यह सब त्वरित सरकारी हस्तक्षेप से संभव हो पाया है। एलपीजी और घरेलू आपूर्ति संरक्षण व्यवधान के 8 दिनों के भीतर सरकार ने एलपीजी नियंत्रण आदेश जारी किया रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने का निर्देश दिया गया। घरेलू एलपीजी उत्पादन को 36,000

टन प्रति दिन से बढ़ाकर 54,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया जो लगभग 50 फीसद की वृद्धि है। 9 दिनों के भीतर प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश जारी किया गया। पीएनजी घरेलू उपभोक्ताओं और सीएनजी सार्वजनिक परिवहन को 100 फीसदी आवंटन के साथ संरक्षित किया गया। सरकार द्वारा सार्वजनिक आपूर्ति बनाए रखने के लिए औद्योगिक आवंटन को भी सुचारू और युक्तिसंगत बनाए रखा। भारत सरकार द्वारा रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम बंगाल, अफ्रीका, अटलांटिक बेसिन से त्वरित संपर्क स्थापित कर ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था की गई। भारत में एलपीजी की मांग लगभग 90,000 टन की प्रतिदिन की है जिसे वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल के माध्यम से 70 से 75000 टन प्रतिदिन कर दिया गया है। भारत में घरेलू उत्पादन बढ़कर 54000 टन प्रतिदिन होने से शेष आयात की आवश्यकता घटकर 20,000 टन प्रतिदिन की रह गई है। सरकार द्वारा आठ लाख टन कार्गो पहले ही सुरिक्षत किए जा चुके हैं, जिससे आज हमारे पास चालीस दिनों का अग्रिम भंडार उपलब्ध है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इस कठिन समय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई पहल के तहत, सरकार ने पनामा नहर जैसे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करते हुए अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम अफ्रीका से तेल और गैस आयात के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए। इसके साथ ही, सरकार ने देश के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का बुद्धिमानी से उपयोग किया, जो भारत को अल्पावधि के लिए वैश्विक आपूर्ति झटकों से बचाते हैं। सरकार के इस कदम ने न केवल बाजार को स्थिरता प्रदान की, बल्कि ईंधन की कीमतों में अत्यधिक उछाल को रोकने में भी मदद की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने पश्चिम एशियाई देशों, विशेषकर सऊदी अरब, यूएई और ईरान के साथ निरंतर कूटनीतिक संवाद बनाए रखा इस के चलते होर्मुज संकट के बावजूद भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बनी रहे। भारत की कूटनीतिक सक्रियता का ही परिणाम था कि ईरान ने सशर्त रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने पर सहमति व्यक्त की, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में पूरी तरह से ठहराव की स्थिति टल गई। संकट काल में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर भी बड़ी सफलता हासिल की। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले ही, 2026 में अपनी गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम कर ऊर्जा सुरक्षा को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करता है। सरकार को देश की प्रगति यानी जीडीपी की रफ्तार की गति बनाये रखने के लिए किसी दीर्घकालिक रणनीति के अवलम्बन की आवश्यकता होगी हाल ही मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा विदेशी मुद्रा और आर्थिक संकट से निपटने के लिए देशवासियों से कई महत्वपूर्ण अपीलें कीं। मौजूदा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने मुख्य सुझाव दिया है। पीएम ने नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन मैट्रो सिटी बस या इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करने को कहा।विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए, पीएम ने देशवासियों से कम से कम एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की।उन्होंने कोरोनकाल की तरह ही 'वर्क फ्रॉम होम' की व्यवस्था फिर से अपनाने को कहा, ताकि यात्रा कम हो और ईंधन बचे। यह न सिर्फ जरूरी है वरन देश के हर नागरिक को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संकट से निपटने का संकल्प भी पैदा करने का प्रयास है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

नीट परीक्षा

बाल मुकुन्द ओझा

सपने व हौसले तोड़ रहीं पेपर लीक की घटनाएं

देशभर में परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेपर लीक किसी राज्य विशेष का मामला नहीं है, अपितु यह देश की युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा ज्वलंत विषय है। आज प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखना किसी कठिनतम चुनौती से कम नहीं है। सरकारी नौकरी पाने का सपना हर शिक्षित युवा देखता है। इसके लिए वह सालों तक कड़ी मेहनत और रात दिन पढ़ाई करके परीक्षा में इस उम्मीद और विश्वास से बैठता है कि उसे सफल होना है, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं ऐसे अभ्यर्थियों का सपना और हौसला तोड़ देती हैं। पेपर लीक के कारण आयोग्य उम्मीदवार बाजी मार कर शासनतंत्र का हिस्सा बन जाता है। भर्ती परीक्षाओं में सरकारी लापरवाही का खामियाजा बेरोजगारों को वर्षों से भुगतना पड़ रहा है। ताज़ा प्रकरण नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई 2026 को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 22 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था। राजस्थान के सीकर से नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला सामने आया है। जांच में सामने आया कि इस गेस पेपर के कई सवाल असली परीक्षा से मिल रहे थे। बताया जा रहा है कि 720 नंबर की परीक्षा में करीब 600 नंबर के सवाल पहले से छात्रों तक पहुंच गए थे। यह कथित क्वेश्चन बैंक एक एमबीबीएस छात्र ने अपने दोस्त को भेजा था, जिसके बाद यह अलग-अलग लोगों तक फैल गया। राजस्थान एसओजी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इससे पूर्व साल 2021 की सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली और सिस्टमेटिक पेपर लीक हुआ था। मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के एक सदस्य की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब ये परीक्षा दोबारा करवाई जा रही है। इसी बीच नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में भारी हंगामा मच गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया है। प्रदर्शन और आंदोलन भी शरू हो गया है। नेताओं ने बयान बाज़ी शरू कर दी है। अच्छे भविष्य के लिए लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां किसी सपने से कम नहीं होती। सालों की मेहनत करने के बाद मिलने वाला एक मौका उनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या हो जब उनकी मेहनत पर पेपर लीक का दाग लग जाए? पेपर लीक की इस महामारी में सरकारी कर्मचारी शिक्षक अपराधी माफिया, कोचिंग सेंटर, आदि शामिल हैं। विभिन्न प्रदेशों में दर्जनों संगठित गिरोह सक्रीय है जिन्होंने पेपर लीक का ठेका ले रखा है। इन गैंगों ने मोटी राशि वसूलकर पेपर बेचने का आपराधिक कार्य किया। अनेक सरगना और और परीक्षार्थी पुलिस की पकड़ में है जिनसे गहरी पूछताछ की जा रही है। पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे कई राज्यों में से राजस्थान भी एक है। राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने का सिलसिला कई सालों से चल रहा है। पिछले कांग्रेस शासनकाल में यह कार्य धड़ल्ले से चला। पेपर लीक प्रदेश के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती वर्ष बर्बाद हो रहे हैं बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। प्रदेश में पेपर लीक होने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जिस वजह से एग्जाम को रद्द करना पड़ता है और ऐसे छात्रों के भविष्य पर भी असर पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पूर्व आरएस भर्ती 2013 में प्री-एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद पता चला कि पेपर पहले ही बाहर था, जिसकी वजह से पूरी परीक्षा रद्द हुई। कांस्टेबल भर्ती 2018 और 2022 दोनों ही बार पुलिस की अपनी ही परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। जेईएन सिविल भर्ती 2020 में पेपर लीक का मामला इतना बढ़ा कि बोर्ड के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में नकल गिरोह के तार शेखावाटी तक फैले मिले और परीक्षा को बीच में ही निरस्त करना पड़ा। एलडीसी भर्ती 2013 में पेपर आउट होने की वजह से जो भर्ती चंद महीनों में होनी थी, उसे पूरा होने में 3 साल लग गए। आरपीएमटी 2014 में सवालों में भारी गड़बड़ी और लीक के आरोपों के बाद इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को भी रद्द करना पड़ा था।

(लेखक वरिष्ठ फ़नकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अनासक्त हुए बिना करे दूसरों की भलाई

यह सोचना भूल है कि हमने संसार का भला किया। इस विचार से दुख उत्पन्न होता है। हम किसी की सहायता करने के बाद सोचते हैं कि वह हमें इसके बदले में धन्यवाद दे, पर वह धन्यवाद नहीं देता, तो हमें दुख होता है। हम जो कुछ भी करें, उसके बदले में किसी चीज की आशा क्यों रखें? बल्कि उल्टे हमें उसी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसकी हम सहायता करते हैं, उसे साक्षात नारायण मानना चाहिए। मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है? यदि हम वास्तव में अनासक्त हैं, तो हमें यह प्रत्याशा जनक कष्ट क्यों होना चाहिए? अनासक्त होने पर तो हम प्रसन्नतापूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं। अनासक्त किए हुए कार्य से कभी भी दुख अथवा अशांति नहीं आएगी। यदि हम यह जान लें कि आसक्ति रहित होकर किस तरह कर्म करना चाहिए, तभी हम दुराग्रह और मतांधता से परे हो सकते हैं। जब तुम दुराग्रह और मतांधता से परे हो जाओगे, तभी अच्छी तरह कार्य कर सकोगे। जो ठंडे मस्तिष्क वाला और शांत है, जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है, जिसके स्नायु सहज ही उत्तेजित नहीं होते तथा जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में परोपकार कर सकता है और इस तरह वह अपना भी कल्याण कर सकता है। यह संसार चरित्र गठन की एक विशाल व्यायामशाला है। इसमें हम सभी को अभ्यास रूप में कसरत करनी पड़ती है, जिससे हम आध्यात्मिक बल से अधिकाधिक बलवान बनते रहें।

संकलित

दर्शन

दो अनमोल हीरे

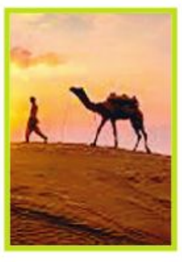

एक व्यापारी को बाज़ार में घूमते हुए एक बहुत अच्छी नस्ल का ऊंट दिखाई पड़ा। व्यापारीव्यापारी ऊंट खरीद कर घर ले आया। घर पहुँचने पर व्यापारी ने अपने नौकर को ऊंट का कजावा (काठी) निकालने के लिए बुलाया। कजावे के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला। नौकर चिल्लाया, मालिक आपने ऊंट खरीदा, लेकिन देखो, इसके साथ क्या मुफ्त में आया है। व्यापारी बोला- मैंने ऊंट ख़रीदा है, न कि हीरे, मुझे उसे तुरंत वापस करना चाहिए। नौकर बोला- मालिक किसी को पता नहीं चलेगा। पर, व्यापारी ने एक न सुनी और वह तुरंत बाज़ार पहुंचा और दुकानदार को मख़मली थैली वापिस दे दी। ऊंट बेचने वाला बहुत ख़ुश था। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। व्यापारी बोला- मैंने ऊंट के लिए सही कीमत चुकाई है इसलिए मुझे किसी शुक्राने और उपहार की जरूरत नहीं है। अंत में व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा- जब मैंने थैली वापस लाने का सोचा तो मैंने पहले से ही दो सबसे कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिए थे। इस कबूलनामें के बाद ऊंट बेचने वाला भड़क गया उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को तुरंत खाली कर लिया। पर वह था बड़ी पशोपेश में बोला- मेरे सारे हीरे तो यहीं है, तो सबसे कीमती दो कौन से थे जो आपने रख़ लिए? व्यापारी बोला- मेरी ईमानदारी और मेरा आत्म सम्मान। जिस-जिस के पास यह 2 हीरे है वह दुनियां के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

संकलित

प्रेरणा

अंतर्मन

आज की पाती

पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों

हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, और इसके बाद यहां हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। चुनाव के बाद यहां हिंसा का सिलसिला पुराना है, वर्ष 2011, 18, 19, 21 और अब 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद भी ऐसा हो रहा है। इस हिंसा का कारण कहीं हारे हुए राजनीतिक दलों का बौखलाना तो नहीं? अगर ऐसा है तो यह सरासर गलत है और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। लेकिन सवाल तो यह है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी यहां हिंसा क्यों हो रही है? यहां से समय-समय पर हिंसा की ऐसी खबरें सुर्खियों में आती हैं जो लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करती हैं, साथ ही वहां की कानून व्यवस्था की भी पोल खोलती हैं। इस हिंसा पर त्वरित रूप से रोक लगनी चाहिए। – *प्रवीण अग्रवाल, राजनांदगांव*

ट्रेंड

हिमंत व मंत्रियों को शुभकामनाएं

मैं असम के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर हिमंत विश्व सरमा को और मंत्रियों के रूप में शपथ ग्रहण करने पर रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार असम के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।
-**जेपी नड्डा,** केंद्रीय मंत्री

युवाओं के सपने कुचले

नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग व सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला-पेपर लीक, सरकारी लापरवाही व शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। -**राहुल गांधी,** कांग्रेस सांसद

विश्वास पर बड़ा आघात

जब परीक्षाओं की शुचिता से समझौता होता है, तो यह केवल एक चूक नहीं, बल्कि उन लाखों अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने अनुशासन के साथ पढ़ाई की, सुख-सुविधाओं का त्याग किया और तैयारी के लिए रातों की नींद गंवाई।
-**नवीन पटनायक,** नेता प्रतिपक्ष, ओडिशा

निजी स्कूल मनमानी न करें

निजी स्कूलों को फीस संरचना का पूरा विवरण सार्वजनिक करना होगा। फीस और अन्य शुल्कों में मनमानी तथा अनुचित वृद्धि पर पूरी तरह रोक रहेगी। अभिभावकों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वर्दी और किताब किसी भी दुकान से खरीद सकेंगे।
-**सम्राट चौधरी,** डीएम बिहार

करंट अफेयर

अब कैमरून करेंगे 'फेमा' का नेतृत्व

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कैमरून हैमिल्टन को संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी (फेमा) का नेतृत्व करने के लिए नामित किया। पूर्व नौसेना सील हैमिल्टन की यह एक आश्चर्यजनक वापसी है। उन्हें पिछले साल फेमा के अस्तित्व का बचाव करने के बाद इसके कार्यवाहक प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्हें नामित करने के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने फेमा को भंग करने के अपने वादों से पीछे हटने के संकेत देना शुरू कर दिया है। फेमा एक ऐसी एजेंसी है जिसकी राष्ट्रपति द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। हैमिल्टन ने तर्क दिया था कि फेमा को समाप्त करना देश के हित में नहीं है और अब उन्हें नामित किया जाना इस बदलाव के नवीनतम संकेत हैं। हैमिल्टन की नियुक्ति हो जाने के बाद वह ट्रंप और आपात प्रबंधन पर गृह सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन के मुख्य सलाहकार होंगे तथा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में फेमा के पहले स्थायी प्रशासक होंगे। ट्रंप ने सोमवार को ही डेविड कमिंस को परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) का प्रमुख नामित किया। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण टीएसए को पिछले कुछ महीनों से उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है और देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा कतारें लंबी होती जा रही हैं।

ऑफ बीट

'डिजिटल डिटॉक्स' क्या है, क्या इससे सेहत बेहतर हो सकती है

क्या आप हर समय स्क्रीन देखते रहते हैं? आज के समय में ईमेल भेजने से लेकर खाना ऑर्डर करने तक, लगभग हर काम के लिए लोग तकनीक पर निर्भर हैं। लेकिन लगातार ऑनलाइन जुड़े रहना शारीरिक और मानसिक थकान का कारण बन सकता है। इसी वजह से कुछ लोग डिजिटल डिटॉक्स अपना रहे हैं। इसका मतलब है एक निश्चित अवधि तक मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाना। यह अवधारणा ऑनलाइन तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसके समर्थक एनालॉग लाइफस्टाइल के स्वास्थ्य लाभों का प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग बेहतर स्वास्थ्य और खुशी पाने के उद्देश्य से महंगे डिजिटल रिट्रीट कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या 'डिजिटल डिटॉक्स' वास्तव में असरदार है या सेहत की बात करने वाला एक और चलन भर है। इसी तरह डिजिटल डिटॉक्स का उद्देश्य तकनीक से कुछ समय के लिए दूरी बनाना, कम व्यवधानों के साथ जीवन का अनुभव करना और ऑफलाइन रिश्तों को मजबूत करना है। ऑस्ट्रेलिया में युवा औसतन रोजाना नौ घंटे स्क्रीन देखते हैं। शोध बताते हैं कि वयस्क भी इससे बहुत पीछे नहीं हैं। 45 से 64 वर्ष आयु वर्ग के ऑस्ट्रेलियाई प्रतिदिन करीब छह घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

संपादकीय

'नीट' फेरपरीक्षेचा वरवंटा

वैद्यक अभ्यासक्रमाची 'नॅशनल इलिजिबिलिटी-कम-एन्ट्रन्स टेस्ट' म्हणजे 'नीट' ही प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की पुन्हा एकदा 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' तसेच सरकारवर ओढवली आहे. राज्य किंवा केंद्रीय बोर्डाच्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा किंवा शिक्षकभरतीचे पेपर आणि 'नीट' या परीक्षांमधील गैरप्रकार इतके नेहमीचे झाले आहेत की, एखाद्या वर्षी 'सुरळीत परीक्षा' हा अपवाद ठरावा! २०२४ मधील 'नीट' पेपरफूट प्रकरण देशात अजून ताजे आहे. बिहारमध्ये ३० ते ५० लाखांना पेपरची विक्री, अनेक विद्यार्थ्यांना पूर्ण ७२० गुण, शेकडो विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क, सर्वोच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल असे या जखमांचे व्रण अजूनही कायम असताना यंदाही तसाच प्रकार घडला. तब्बल ६०० गुणांशी संबंधित १२० अपेक्षित प्रश्न प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांशी जुळल्याचे राजस्थानात उघडकीस आले. 'एनटीए'ने आधी गैरप्रकाराचा इन्कार केला; परंतु, तपास यंत्रणांना चुरू, सिकर, झुनझुनू यांसोबतच डेहराडून, नाशिक, आदी ठिकाणी धागेदोरे सापडले आणि संपूर्ण परीक्षा रद्द करावी लागली. हा निर्णय लाखो विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना प्रचंड मनस्ताप देणारा आणि विद्यार्थ्यांच्या वर्ष-दोन वर्षांच्या अहोरात्र मेहनतीवर पाणी टाकणारा, त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा करणारा आहे; कारण, परीक्षा देऊन १० दिवस उलटले आहेत. अभ्यास-परीक्षेच्या मनोवस्थेतून विद्यार्थी बाहेर पडले आहेत. फेरपरीक्षेसाठी पुन्हा त्या वातावरणाशी जुळवून घेणे सोपे नाही. त्यामुळे त्यांच्या भवितव्यावर वरवंटा फिरविला जाईल. या मनस्तापाची जाणीव सरकारला नाही असे नाही; म्हणूनच कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील भारताचे भविष्य घडवू पाहणाऱ्या 'इंडिया-एआय मिशन'मधील अभिषेक सिंह नावाचे तंत्रस्नेही सनदी अधिकारी केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात 'एनटीए'च्या महासंचालकपदी नियुक्त केले. 'एनटीए' देशातील सर्व प्रकारच्या सामायिक परीक्षा घेते आणि जगातील सर्वांत मोठ्या सामायिक परीक्षांपैकी एक मानली जाणारी, सर्वाधिक चर्चेत राहणारी 'नीट' ही यंत्रणा व सरकारसाठी महाभयंकर डोकेदुखी बनली आहे. राज्याराज्यांमधील स्वतंत्र परीक्षेऐवजी एकच देशव्यापी परीक्षा असावी, या केंद्र सरकारच्या अट्टहासाने आता एका आर्थिक घोटाळ्याचे स्वरूप धारण केले आहे. कारण, देशातील एमबीबीएसच्या जवळपास एक लाख जागा आणि दंतवैद्यक, आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी अभ्यासक्रमांचेही प्रवेश 'नीट' परीक्षेतून होतात. यंदा ३ मे रोजी ही परीक्षा झाली आणि देशातील ५५१ व विदेशांतील १४ शहरांमधील ५ हजार ४०० केंद्रांवर तब्बल २२ लाख ७९ हजार विद्यार्थ्यांनी एकाच वेळी ही परीक्षा दिली. हा इतका अवाढव्य कारभार पाहणारी यंत्रणा कमालीची कार्यक्षम हवीच. त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ती विश्वासार्ह हवी, तिचा कारभार पारदर्शक हवा. त्यासाठीच अभिषेक सिंह यांनी महासंचालकपदाची सूत्रे स्वीकारताच 'झिरो एरर - झिरो टॉलरन्स' घोषणा केली. तथापि, व्यवस्था इतकी सडलेली आहे की, १५ दिवसांत त्या घोषणेचा खेळखंडोबा झाला. 'एनटीए'च्या कारभाराची लक्तरे पुन्हा वेशीवर टांगली गेली. त्याचे कारण, पेपर फुटला की तेवढ्यापुरती चर्चा, आंदोलने, थातूरमातूर चौकशी याशिवाय काही होत नाही. लाखो विद्यार्थी डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न 'एनटीए'च्या भरवशावर पाहतात आणि तिच्यावर मात्र पेपरमाफियांचा कब्जा आहे. काही कोचिंग क्लासेस या माफियांच्या पाठीशी आहेत. राजधानी दिल्ली, राजस्थानातील कोटा, सिकर शहरे तसेच देशाच्या कानाकोपऱ्यात असे कोचिंगवाले अधिक आहेत. कोचिंगची फी काही लाखांमध्ये असते. धनदांडगेच इतका पैसा भरू शकतात. डॉक्टर बनल्यानंतर बक्कळ पैसा मिळतो व सोबत प्रतिष्ठाही मिळते. केवळ गुणवत्तेच्या बळावर वैद्यक अभ्यासक्रमाला प्रवेश तसेच पुढे पैसा व प्रतिष्ठा मिळण्याची शाश्वती ज्यांना नाही, ते गैरमार्गांचा अवलंब करतात. त्यातूनच हे पेपरफुटीचे घोटाळे आकार घेतात. परीक्षा घेणारी एनटीए, काही कोचिंग क्लासेस, धनदांडगे पालक आणि गलथान सरकारी कारभार हा या घोटाळ्यांचा संतापजनक चौकोन आहे. जोपर्यंत ही सडलेली व्यवस्था दुरुस्त होत नाही, तोवर 'झिरो एरर - झिरो टॉलरन्स' वगैरे घोषणा वांझोट्याच ठरणार. आधीच्या पेपरफुटीसाठी जबाबदार सुबोध कुमार सिंह यांना हटविणे, त्याजागी नवे महासंचालक आणणे वगैरे सारे उपाय वरवरचे आहेत. रोगावर जालीम उपचार होत नाही तोवर दरवर्षी देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपऱ्यात पेपरला पाय फुटणार आणि त्या पायांखाली लाखो विद्यार्थ्यांची स्वप्ने चिरडली जाणार. देशाच्या भविष्याच्या वाट्याला आलेले हेच दुर्दैवी प्राक्तन आहे.

स्वतंत्र, सतर्क, सक्रिय वकील हा लोकशाहीचा कणा!

न्यायसंस्था राज्यघटनेची पालक आहे, तर वकील जबाबदार दक्षमित्र आहेत. हे दोन्ही घटक एकत्र येऊन घटनात्मक लोकशाहीचे अभिवचन पूर्ण करतात.

भूषण गवई
भारताचे माजी सरन्यायाधीश

वकील आणि न्यायपालिका या घटनात्मक लोकशाहीत एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या वेगवेगळ्या संस्था नाहीत. त्या एकमेकांना पूरक आहेत. सुवर्णरथाच्या या दोन चाकांवरच सरकारचे उत्तरदायित्व अवलंबून असते. एकाने चूक केली तरी सगळ्या रचनेचा तोल जातो. लोकशाही नीट राबवायची असेल तर न्यायपालिका स्वतंत्र असली पाहिजे. न्यायालयेच घटनेचा अंतिम अर्थ लावत असतात; परंतु स्वतंत्र न्यायव्यवस्था एकट्याने काम करू शकत नाही. वकिली व्यवसाय स्वतंत्रपणे कसा चालतो यावर न्यायालयाचे स्वातंत्र्य जोखले जाते. आणीबाणीच्या प्रसंगी वकील मंडळीच न्यायव्यवस्था आणि तिची स्वायत्तता कमी करणाऱ्यांच्या मध्ये उभी राहतात. वकील नागरिकांचेही प्रतिनिधित्व करतात. वकिलांचे स्वातंत्र्य ही घटनात्मक गरज आहे. न्यायसंस्था राज्यघटनेची पालक आहे, तर वकील दक्षमित्र आहेत. दोघे एकत्र येऊन घटनात्मक लोकशाहीचे अभिवचन पूर्ण करतात.

समाजाच्या नैतिक आणि राजकीय आकलनशक्तीवर वकील प्रभाव टाकतात. हक्काच्या दाव्याला ते शब्द देतात; अन्यायाची परिभाषा ठरवतात. घटनात्मक साधक-बाधक विचार उभे करतात. त्यातून अंतिमतः कायदेविषयक नियम, तत्त्वांना अभिव्यक्ती मिळते. भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर या व्यवस्थेला आकार देण्यात वकिलांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादातून नानी पालखीवाला यांनी हे दाखवून दिले की, घटनादुरुस्तीचा संसदेला असलेला अधिकार अमर्याद नाही. घटनादुरुस्ती करतानाही घटनेच्या काही पायाभूत वैशिष्ट्यांना धक्का लावता येणार नाही. शिवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य १९७३ या खटल्याच्या निकालात या युक्तिवादाचे प्रतिबिंब दिसते. संसदेला घटनादुरुस्तीचे व्यापक अधिकार आहेत, तरी तिच्या मूळ रचनेला धक्का लावता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले.

१९७५ साली आणीबाणी जारी केली गेली तेव्हा दुसरा महत्त्वाचा क्षण आला. एडीएम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला या खटल्यात आणीबाणीच्या काळात व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी न्यायालयात धाव घेण्याचा अधिकार स्थगित करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनीच काय ते विरोधी मत नोंदवले. आणीबाणीतही व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही असे मत त्यांनी नोंदवले. आपल्याला याची काय किंमत मोजावी लागेल याची कल्पना न्यायमूर्ती खन्ना यांना होती. ते सरन्यायाधीश होऊ शकले नाहीत; परंतु त्यानंतर जे घडले ते तितकेच महत्त्वाचे आहे. वकील मंडळींनी यावर मौन पाळले नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांची संघटना तसेच देशभरातल्या वकील संघटनांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवत न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन केले. नंतर न्यायव्यवस्थेतील नेमणुकांच्या संदर्भात तिच्या स्वातंत्र्याचे काही प्रश्न वकिलांच्या संघटनांनी उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी १९९३ आणि २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा विषय आणला असता सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील नेमणुका करताना न्यायपालिकेलाच प्राधान्य द्यायला हवे; तरच तिचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील असा निवाडा न्यायालयाने दिला.

वकिली व्यवसायात स्वातंत्र्य असेल तर न्यायपालिकेची विश्वासार्हता वाढते. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य म्हणजे तिला प्रतिप्रश्न करायचाच नाही असे नव्हे. संस्थात्मक प्रमाणकांपासून दूर जाणे होत असेल किंवा काही गैरप्रकार होत असतील तर वकील मंडळी दैनंदिन कामकाजाच्या माध्यमातूनही त्याकडे लक्ष वेधतात. न्यायाधीशांच्या अशा वर्तनाबद्दल गरज असेल तेव्हा बोलून वकील घटनात्मक संस्था बळकटच करत असतात.

जनहित याचिकांच्या माध्यमातूनही भारतातील वकिलांनी हक्कांचे संरक्षण केले आहे. १९८०च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने काही पारंपरिक नियम शिथिल केले. वंचित घटकांच्या वतीने संबंधित व्यक्ती किंवा वकिलांना न्यायालयाकडे जाता येऊ लागले. न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत त्यामुळे कायापालट झाला. वकिलांनी केवळ हक्कांचे उल्लंघन झाले म्हणून प्रतिसाद दिला असे नव्हे, तर त्यांनी घटनात्मक हक्कांना आकार देण्यात सक्रिय भूमिका बजावली.

गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्ता बेकायदेशीरपणे बुलडोझर लावून पाडण्याविषयीच्या प्रकरणात अनेक नामांकित वकिलांनी न्यायासनापुढे येऊन बाजू मांडली. त्या न्यायपीठाचा अध्यक्ष मी होतो. बाजू मांडणे, न्यायदान आणि शिक्षेची अंमलबजावणी अशा तिन्ही भूमिकांमध्ये कार्यपालिका एकाचवेळी जाऊ शकत नाही असे 'बांधकाम पाडण्याविषयीचे निर्देश २०२४' या निकालात म्हटले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया, सुनावणीशिवाय आणि सूचना न देता दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला.

वकिलांचे स्वातंत्र्य, सतर्कता आणि सक्रियता सर्वत्र सारखीच महत्त्वाची असते. जगभरातील न्याय यंत्रणेला सध्या आंतरदेशीय गुन्हे, स्थलांतर, डिजिटल कारभार, पर्यावरणाचा ऱ्हास अशा आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना वकिलांचे स्वातंत्र्य अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. जगात काय चालले आहे, न्यायप्रणालीत त्याअनुषंगाने काय बदल करावे लागतील, याकडे वकिलांनी न्यायपालिकेचे लक्ष वेधले पाहिजे.

(बार असोसिएशन ऑफ श्रीलंका यांच्या बावन्नाव्या पदवीदान समारंभात कोलंबो येथे केलेल्या भाषणाचा संक्षिप्त, संपादित अनुवाद)

नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांचे पुढचे लक्ष्य?-अर्थातच पंजाब!

भाजपने इतर पक्षांतून आयात केलेल्या वजनदार नेत्यांचे भक्कम जाळे पंजाबमध्ये उभे केले आहे. या राज्यात मोठी झेप घेण्याची मोर्चेबांधणी तयार झालेली आहे !

हरीष गुप्ता
नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

भाजपला स्वत:च्या बळावर कधीही जिंकता आलेला नाही असा एक महत्त्वाचा राजकीय किल्ला - पंजाब. मात्र आता २०२७च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून नरेंद्र मोदी-अमित शाह जोडी या राज्यात राजकीय, सामाजिक आणि मानसिक पातळीवर आक्रमक रणनीती आखताना दिसत आहे.

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी आम आदमी पार्टीचे सरकार अधिकाधिक असुरक्षित होत चालल्याचा भाजपचा विश्वास आहे. अमृतसरमधील खासा येथे लष्करी छावणीजवळ आणि जालंधरमधील बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर मुख्यालयाबाहेर झालेले अलीकडचे दोन कमी तीव्रतेचे स्फोट भाजपला राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रभावी मुद्दा मिळवून देणारे ठरले. खलिस्तानी घटक पुन्हा संघटित होण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या या संवेदनशील सीमावर्ती राज्यात मान सरकार सुरक्षेच्या बाबतीत कमकुवत असल्याचे चित्र रंगवायला भाजपने सुरुवात केली आहे. मात्र भाजपचे सर्वात प्रभावी शस्त्र कोणते? - त्यांचे पोलिटिकल इंजिनिअरिंग !

भाजपने इतर पक्षांमधून आयात केलेल्या वजनदार नेत्यांचे भक्कम जाळे पंजाबमध्ये उभे केले आहे. पंजाब भाजपचे अध्यक्ष सुनील जाखर काँग्रेसमधून आले. केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांनीही काँग्रेस सोडली. माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आधीपासूनच भगव्या छावणीत आहेत. आता राघव चड्ढा आणि 'आप'च्या सहा राज्यसभा खासदारांनी भाजपमध्ये केलेल्या नाट्यमय प्रवेशामुळे पक्षाच्या विस्तार योजनांना नवी गती मिळाली आहे. या सगळ्याचा निष्कर्ष? - एकच ! - आता देशाच्या अस्थिर सीमावर्ती पट्ट्यात पुढची मोठी राजकीय झेप घेण्याची तयारी भाजपने चालवली आहे.

सुवेंदू आणि सर्मा यांच्यातील समान धागा

दशकानुदशके भारतातील विरोधी पक्षांनी एक राजकीय कला उत्तमरीत्या आत्मसात केली- रणांगणातील सेनानींपेक्षा घराण्यांना प्राधान्य देणे. दुसरीकडे भाजपने नेमके उलटे तंत्र विकसित केले- घराणेशाहीच्या दरबारात दुर्लक्षित झालेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रादेशिक नेत्यांना ओळखणे आणि त्यांना मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचवणे. सुवेंदू अधिकारी आणि हिमंता बिसवा सर्मा यांना जोडणारा समान धागा हाच आहे. अधिकारी हे नंदीग्राम आंदोलनाचे शिल्पकार होते. रस्त्यावर लढणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना बंगालच्या निर्विवाद शासकापर्यंत पोहोचवणारे जनसंघटक होते. अनेक वर्षे त्यांना पक्षाचा नैसर्गिक राजकीय वारस मानले जात होते. मात्र पक्षाने अचानक पुढील नेतृत्वासाठी ममतांचा पुतण्या अभिषेक बॅनर्जी यांच्याकडे कल दाखवला आणि उत्तराधिकाराची पटकथा बदलली. अधिकारी यांनी २०२० मध्ये तृणमूलची साथ सोडली. भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि ते बंगालमधील भगव्या छावणीचे 'राजा' बनले.

आसामची कहाणीही तशीच आहे. सर्मा यांनी ईशान्य भारतात काँग्रेसची वीट-वीट रचून तब्बल २५ वर्षे उभारणी केली; पण उत्तराधिकाराचे राजकारण समोर येताच पक्षश्रेष्ठींना माजी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचे पुत्र गौरव गोगोई अधिक पसंत असल्याचे दिसले. सर्मा यांनी २०१५ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. आज ते केवळ केवळ आसामचे नाहीत, तर संपूर्ण ईशान्य भारतातील भाजपचे प्रमुख रणनीतिकार आहेत.

घराणेशाहीमुळे कमकुवत झालेल्या पक्षांकडून अनेकदा त्यांचे सर्वात प्रभावी सेनानी निसटून जातात. भाजपचा उदय केवळ निवडणूक यंत्रणा किंवा आक्रमक प्रचारावर अवलंबून नाही. कुटुंबकेंद्रित पक्षांनी बाजूला सारलेल्या नेत्यांना ओळखणे, वारशापेक्षा महत्त्वाकांक्षेला प्राधान्य देणे आणि राजकीय असंतोषाचे रूपांतर निवडणूक शक्तीत करणे हाच भाजपचा खरा दीर्घकालीन खेळ आहे.

नितीश यांचीही घराणेशाही

वर्षानुवर्षे नितीश कुमार यांनी आपली राजकीय प्रतिमा दोन दाव्यांभोवती उभी केली होती- स्वच्छ प्रशासन आणि घराणेशाहीविरोधातील भूमिका. मात्र त्यांचा पुत्र निशांत कुमार याची सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील बिहार सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी जपलेली नैतिक उंची कोसळल्याचे दिसते. अवघ्या महिनाभरापूर्वी जनता दल (युनायटेड)मध्ये प्रवेश केलेला आणि एकदाही निवडणूक न लढलेला निशांत मंचावर वडिलांच्या पायाला स्पर्श करून थेट मंत्रिपदावर पोहोचला. संघटनात्मक पातळीवरील वर्षानुवर्षांची धडपड नाही, निवडणुकीची कसोटी नाही, विधिमंडळाचा अनुभव नाही- गुणवत्ता काय?- तर फक्त घराणे! दशकानुदशके नितीश यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्यावर घराणेशाहीचा ठपका ठेवला, अखेरीस त्यांनीही तीच संस्कृतीला कवटाळली! 'परिवारवाद' हा लोकशाहीसाठी धोका असल्याचे सांगणारी भाजपची भगवी छावणीही गप्प राहिली!

harish.gupta@lokmat.com

जगभर

चीनच्या दोन माजी संरक्षणमंत्र्यांना मृत्युदंड!

चीनमध्ये काय चालतं हे जगात कोणालाही कळत नाही. कारण आपल्याकडची एकही बातमी, एकही माहिती कुठे लीक होणार नाही याची ते प्राणपणानं काळजी घेतात; मात्र घटना घडून गेल्यानंतर बऱ्याच काळानं किंवा तिथलं कोणी देशाबाहेर गेल्यानंतरच बऱ्याचदा तिथली माहिती जगासमोर येते.

आता नव्या माहितीनुसार चीननं भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आपले दोन माजी संरक्षण मंत्री ली शांगफू आणि वेई फेंघे यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. सरकारी वृत्तसंस्था Xinhua News Agencyच्या माहितीनुसार, दोघांना आधी दोन वर्षं तुरुंगात ठेवण्यात येईल. जर त्यांनी दोन वर्षांत कुठलाही नवा गुन्हा केला नाही, तर शिक्षेचं रूपांतर जन्मठेपेत केलं जाऊ शकतं.

ली शांगफू यांना गेल्यावर्षी अचानक पदावरून हटवण्यात आलं होतं, तर वेई फेंघे यांच्यावरही लष्करी भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी सुरू होती. त्यानंतर २०२४ मध्ये दोघांना चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षातून बडतर्फ करण्यात आलं होतं. तज्ज्ञांच्या मते, ही कारवाई राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा भाग आहे. ली शांगफू जवळपास दोन महिने गायब होते. त्यामुळे अनेक प्रकारच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. आता प्रथमच चिनी अधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे मान्य केलं आहे की त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचारासंबंधी चौकशी सुरू होती.

ली शांगफू आणि वेई फेंघे यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात लाच घेणं, इतरांना लाच देणं आणि पदाचा गैरवापर केल्याचे आरोप आहेत. चीनच्या लष्करी न्यायालयानं त्यांना भ्रष्टाचारासाठी दोषी ठरवलं आहे. चौकशीत समोर आलं की वेई फेंघे यांनी संरक्षण मंत्रालय आणि सैन्याशी संबंधित निर्णयांमध्ये फायदा करून देण्याच्या बदल्यात कथितरीत्या लाच घेतली होती. वेई फेंघे हे चीनमधील वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांपैकी एक मानले जात होते. ते चीनचे माजी संरक्षणमंत्री असण्यासोबतच चिनी सैन्यात रॉकेट फोर्सचे ते कमांडरही होते. रॉकेट फोर्स चीनच्या क्षेपणास्त्र आणि अण्वस्त्र प्रणालीचं नियंत्रण सांभाळतं.

अहवालांनुसार, चीनमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचार चौकशीचं सर्वात मोठं केंद्र रॉकेट फोर्स आणि सैन्याच्या शस्त्र खरेदी विभागाला मानलं जात आहे. चीनच्या सैन्याचं हे विशेष युनिट असून देशाच्या अण्वस्त्र क्षेपणास्त्र आणि लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक मिसाइल्सचं ते नियंत्रण करतं. हे युनिट चीनच्या लष्करी ताकदीचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, कारण गरज पडल्यास अणुहल्ला करण्याची क्षमता याच युनिटकडे आहे. चौकशी संस्थांना संशय आहे की सैन्यासाठी शस्त्रखरेदी, संरक्षण करार आणि लष्करी उपकरणांच्या पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. अनेक अधिकाऱ्यांनी कंत्राटं देताना आणि लष्करी करारांमध्ये मोठी लाच घेतली!

ली शांगफू आणि वेई फेंघे प्रकरणात सेंट्रल मिलिटरी कमिशनच्या (सीएमसी) चौकशी संस्थांनी भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या आरोपांची चौकशी केली होती. सीएमसी ही चीनची सर्वोच्च लष्करी संस्था आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि चीन सरकारतर्फे ती सैन्यावर नियंत्रण ठेवते. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स आर्म्ड पोलिस आणि मिलिशिया याच संस्थेच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहेत.

गेल्या एका वर्षात चीनच्या लष्करी आणि एरोस्पेस क्षेत्राशी संबंधित डझनभर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदांवरून हटवण्यात आलं आहे.

जनमन

अंतिम कसोटी शेवटी आकड्यांचीच!

राजकारणात सत्तेचे समीकरण जुळवणे जितके महत्त्वाचे असते, तितकेच महत्त्वाचे असते ते संविधानिक बहुमत सिद्ध करणे. केवळ राजभवनाच्या फेऱ्या मारून, पत्रकार परिषद घेऊन किंवा भावनिक वातावरण निर्माण करून सत्ता मिळत नसते. लोकशाहीत अंतिम कसोटी आकड्यांचीच असते आणि ती सभागृहात सिद्ध करावीच लागते. भारतीय लोकशाहीचा इतिहास पाहिला, तर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार केवळ एका मताने पडले होते. हा प्रसंग आजही लोकशाहीतील बहुमताचे महत्त्व अधोरेखित करतो. त्यावेळी नियम वेगळे नव्हते आणि आजही वेगळे नाहीत. सत्ता कोणाचीही असो, संविधान सर्वांना समान निकष लावते. आज अनेक राज्यांमध्ये सत्ता स्थापनेबाबत दावे-प्रतिदावे सुरू असतात. मात्र, केवळ 'आमच्याकडे समर्थन आहे' असे सांगून चालत नाही. ते सिद्ध करावे लागते. हीच संसदीय लोकशाहीची परंपरा आणि शिस्त आहे.

लोकशाहीत भावना, घोषणाबाजी किंवा राजकीय दबावापेक्षा घटनात्मक प्रक्रिया मोठी असते. त्यामुळे कोणत्याही पक्ष किंवा आघाडीने सत्ता स्थापनेचा दावा करताना प्रथम बहुमत सिद्ध करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे; अन्यथा 'सत्ता आमचीच' हा दावा केवळ राजकीय वक्तव्य ठरतो. आज देशातील मतदार अधिक जागरूक झाला आहे. त्याला केवळ सत्तासंघर्ष नको आहे, तर स्थिर आणि जबाबदार सरकार हवे आहे. त्यामुळे बहुमत सिद्ध करण्याची प्रक्रिया केवळ औपचारिकता नसून लोकशाहीवरील विश्वास टिकवण्याची हमी आहे. सत्तेचा मार्ग राजभवनातून जाऊ शकतो; पण अंतिम मंजुरी बहुमताच्या आकड्यांतूनच मिळते.

- वीरेंद्र सोनवणे, पुणे

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

सज्जनशक्ती

चांगल्यातले वाईट आणि वाईटातले चांगले शोधण्याचे कौशल्य आहे?

'टोकाचे चांगले' किंवा 'टोकाचे वाईट' अशा भूमिका घेऊन नागरिक भांडत राहिले तर राज्यकर्त्यांना आपला स्वार्थ सहज साधता येऊ शकतो..

डॉ. हमीद दाभोलकर
मानसोपचारतज्ज्ञ, कार्यकर्ता, महाराष्ट्र अंनिस

मानवी वर्तन किंवा आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना फारच कमी वेळा पूर्णपणे चांगले किंवा पूर्णपणे वाईट यामध्ये विभागता येतात. बहुतांश वेळा आपले वास्तव चांगले आणि वाईट यांच्या विविध टक्केवारीच्या मिश्रणातून बनत असते. अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला 'चांगल्यामधले वाईट काय आहे?' आणि 'वाईटामध्ये त्यातल्या त्यात चांगले काय आहे?' हे वेगळे करण्याचे कौशल्य अत्यंत आवश्यक आहे.

वर्तमान कालखंडात बहुतांश गोष्टींविषयी दोन ध्रुवांसारख्या वेगवेगळ्या टोकाच्या भूमिका घेण्याकडे लोकांचा कल वाढलेला आहे. 'पोलरायजेशन' हे प्रमुख राजकीय हत्यार म्हणून वापरले जाते आहे. नागरिकांनी 'टोकाचे चांगले' किंवा 'टोकाचे वाईट' अशा भूमिका घेऊन एकमेकांशी हिरीरीने भांडावे त्यामुळे मग राज्यकर्त्यांना आपला स्वार्थ सहज साधता येऊ शकेल अशा स्वरूपाचे हे राजकारण आहे.

या राजकारणाला जर आपल्याला बळी पडायचे नसेल तर आपल्याला चांगल्यामधले वाईट आणि वाईटातले चांगले शोधता आले पाहिजे. कधी कधी वाईट गोष्ट चांगुलपणाच्या आड लपलेली असते. आपल्याला आवडणारे बोलणे, मदत करण्याची आश्वासने यांच्या मागे अनेक वेळा समोरच्या व्यक्तीचा वेगळाच स्वार्थ दडलेला असतो. फक्त बाह्य चमक पाहून निर्णय न घेता, सत्य आणि परिणाम समजून घेतले तर चांगल्या गोष्टींमधील वाईट ओळखता येते. तसेच ज्या गोष्टीमध्ये खूप चांगले असते, त्यामधले थोडेसे वाईट लगेच दिसत नाही. ते शोधण्यासाठी शांतपणे आणि विचारपूर्वक निरीक्षण करणे गरजेचे असते. छोट्या चुका किंवा गैरफायदे दुर्लक्षित न करता त्याकडे लक्ष दिले, तर चांगल्या गोष्टीमधील वाईट सहज ओळखता येते. चांगल्या गोष्टींमधले वाईट समजून घेण्याची आपली क्षमता विकसित झाली तर मग कोणाही व्यक्तीचे दैवतीकरण आपल्याकडून होण्याची शक्यता कमी होते. वाईट गोष्टीमध्येही काही शिकण्यासारखे किंवा चांगले दडलेले असू शकते. कठीण प्रसंग माणसाला अधिक मजबूत, सावध आणि समजूतदार बनवतात. अपयशातून अनुभव मिळतो, चुका सुधारण्याची संधी मिळते आणि योग्य मार्ग निवडण्याची जाणीव होते.

एक उदाहरण पाहूया. अलीकडे भारतात विविध राजकीय पक्षांनी निवडणुकांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर मोफत योजना, सवलती आणि आर्थिक मदतीची आश्वासने दिली. या गोष्टीतील चांगला भाग असा की गरीब, शेतकरी, महिला आणि बेरोजगार लोकांना काही प्रमाणात आधार मिळतो. अनेक लोकांना शिक्षण, आरोग्य आणि प्रवासाच्या सुविधा मिळतात. पण त्यामधले वाईट असे की काही वेळा लोकांच्या खऱ्या समस्या सोडविण्यापेक्षा फक्त मते मिळविण्यासाठी अशा घोषणा केल्या जातात. त्यामुळे लोक दीर्घकालीन विकास, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे कमी लक्ष देतात. सरकारवर आर्थिक ताणही वाढू शकतो.

कोणतीही राजकीय गोष्ट पूर्णपणे चांगली किंवा पूर्णपणे वाईट नसते. आपण फक्त आकर्षक घोषणा न पाहता, त्याचे परिणाम, उद्देश आणि समाजावर होणारा प्रभाव समजून घेतला पाहिजे. विवेकबुद्धीने विचार केला तर चांगल्यामधले वाईट आणि वाईटामधले चांगले ओळखता येते. आपण स्वत:, आपले कुटुंब आणि आपला समाज अधिक चांगला होण्यासाठी हे अतिशय आवश्यक कौशल्य आहे.

hamid.dabholkar@gmail.com

तिरकस आणि चौकस — गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

नीट-यूजी का रद्द होना

विगत तीन मई को देशभर में आयोजित की गयी नीट-यूजी की परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द किये जाने का फैसला निश्चित रूप से छात्रों के हित और परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, लेकिन इस परीक्षा में बैठे छात्रों के लिए यह घटनाक्रम बेहद परेशान करने वाला है. मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाली इस सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा में इस बार 22 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था. दरअसल, नीट-यूजी गेस पेपर से 120 से 150 सवाल इस परीक्षा में हूबहू आये थे, जिनमें केमिस्ट्री के 30 और बायोलॉजी के 90 तक सवाल थे. पंद्रह दिन पहले ही पेपर लीक होने तथा सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स पर गेस पेपर के शेयर होने की बात भी सामने आयी है. उसके बाद से ही इस परीक्षा के रद्द होने की आशंका उत्पन्न होने लगी थी. शुरुआती स्तर पर राजस्थान के सीकर, केरल और देहरादून से पेपर लीक के तार जुड़े होने की बात सामने आयी है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं. गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पेपर लीक होने से मेरिट सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है और छात्रों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे उनका भरोसा डगमगा जाता है. एक ही परीक्षा सिस्टम में बार-बार खामियां सामने आना व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है. वर्ष 2024 में भी नीट-पीजी की परीक्षा रद्द हो गयी थी. इस बार नीट परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लिया था. प्रश्नपत्रों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए जीपीएस युक्त वाहनों का प्रयोग किया गया था. परीक्षा भवन के भीतर नकल और बाहरी संचार को रोकने के लिए 5जी जैमर्स और एआइ आधारित कैमरों का पहरा था. अभ्यर्थियों का बायोमीट्रिक वेरीफिकेशन भी किया गया था. पर इतने इंतजाम करने के बावजूद पेपर लीक हो गया, तो यह तकनीकी खामी नहीं, बल्कि सिस्टम के भीतर मौजूद मानवीय खामी के बारे में बताता है. सवाल है कि क्या प्रश्नपत्र की प्रिंटिंग और प्रेस में छपाई के दौरान पेपर लीक हुआ या पेपर सेट करने से जुड़े किसी व्यक्ति की ओर से पेपर लीक किया गया होगा. सीबीआइ से न सिर्फ इस मामले की तह तक जाने की उम्मीद है, बल्कि दोषियों की शिनाख्त और सख्त दंड के जरिये पेपर लीक के नेटवर्क को ध्वस्त किये जाने की भी उम्मीद है.

पेपर लीक होने के कारण नीट-यूजी की परीक्षा रद्द किये जाने का फैसला बेशक छात्रों के हित और परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, पर इस परीक्षा में बैठे छात्रों के लिए यह घटनाक्रम बेहद परेशान करने वाला है.

घर लौट आयी है बंगाल की मूल आत्मा

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.com

पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार गेरुआ वस्त्रधारी एक नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राजा राममोहन राय की तर्कशीलता, बंकिम का राष्ट्रप्रेम, सुभाषचंद्र बोस का साहस, अरविंद की दृष्टि और विवेकानंद का उत्साह अंततः फलित हुआ. पर विजय के साथ सबसे कठिन परीक्षा भी आती है. शुभेंदु अधिकारी की सरकार को भाषणों से आगे बढ़कर परिणाम देने होंगे. बंगाल के लोग अब विकास चाहते हैं, जो समाज को जोड़े, तोड़े नहीं. उन्होंने हिंदू एकजुटता के लिए मतदान किया, अब वे व्यवहार में रामराज्य चाहते हैं.

नौ मई की तपती दोपहर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इतिहास ने केवल एक पन्ना नहीं पलटा. वह एक गेरुआ उभार के रूप में फूट पड़ा, जिसने सात दशकों से अधिक की वैचारिक जड़ता को झुलसा दिया. पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार गेरुआ वस्त्रधारी एक नेता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पचपन वर्षीय शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस से उभरकर अपनी पहचान बनायी. उनका परिधान केवल वस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसे राज्य में, जो लंबे समय तक कांग्रेस की निष्क्रियता, मार्क्सवादी कुप्रबंधन और ममता बनर्जी की राजनीति से बंधा रहा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चुनौतीपूर्ण घोषणा के रूप में था. राज्यपाल आरएन रवि भी, जिन्होंने तमिलनाडु में अपने कार्यकाल के दौरान शायद ही कभी पारंपरिक वस्त्र पहने थे, गेरुआ कुर्ता और पारंपरिक बंगाली धोती में सुसज्जित दिखाई पड़े. उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, जो समान रंग की साड़ी पहने थीं, उस दिन रवींद्रनाथ ठाकुर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस क्षण को संभव बनाने वाला जनादेश एक ऐतिहासिक विभाजन था. भाजपा की 207 सीटों और 45 प्रतिशत मतों के साथ मिली विजय फुसफुसाहट नहीं, बल्कि प्रबल जनाक्रोश की गर्जना थी. मतदाता छोटे-मोटे बदलाव नहीं, बल्कि पूर्ण परिवर्तन चाहते थे. मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के लिए यह केवल चुनावी गणित नहीं था. यह एक सांस्कृतिक विजय थी, जिसने 175 वर्षों की ब्रिटिश औपनिवेशिक स्मृति को एक झटके में समाप्त कर दिया.

कोलकाता औपनिवेशिक शासन का पालना था. यहीं से 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस साम्राज्य का संचालन किया था, जिसकी पकड़ पूरे उपमहाद्वीप तक फैली थी. वह शहर जिसने ब्रिटिश राज की प्रशासनिक रीढ़ को जन्म दिया, अब उसके प्रतीकात्मक पतन का साक्षी बना. भाजपा की रणनीति अत्यंत सूक्ष्म, सुविचारित और दूरदर्शी थी. पश्चिम बंगाल को जानबूझकर अंतिम राज्य के रूप में मतदान समाप्त करने के लिए रखा गया. अंतिम चरण और चार मई की मतगणना के बीच पांच दिनों का अंतर रखा गया. यह तिथि विशेष महत्व रखती थी, क्योंकि यह जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी, जिनकी अखंड भारत की परिकल्पना लंबे समय तक वामपंथी इतिहास लेखन की परतों में दबा दी गयी थी. शपथ ग्रहण समारोह नौ मई को निर्धारित किया गया, जिसे रवींद्रनाथ ठाकुर की विरासत को स्मरण करते हुए गेरुआ प्रतीकवाद से जोड़ा गया. ममता बनर्जी के नबान्न से सरकार चलाने के केंद्र को वापस ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग में ले जाने का निर्णय भी पुनर्स्थापन का संकेत था.

इस दृश्य के पीछे भाजपा की 15 वर्षों की धैर्यपूर्ण मेहनत थी. पश्चिम बंगाल की भूमि ऐतिहासिक महत्व रखती है, जहां राजा राम मोहन राय ने नवजागरण का दीप प्रज्वलित किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 'वंदे मातरम' की रचना की. सुभाष चंद्र बोस ने वहीं ब्रिटिश राज को चुनौती देने वाला आक्रामक स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा किया. श्री अरविंद ने हिंदू अध्यात्म को क्रांतिकारी विचारधारा का रूप दिया, तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व मंच पर हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और घोषणा की कि भारत की आत्मा शाश्वत है. इन महान विभूतियों ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऐसे बीज बोये कि न तो कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति और न ही मार्क्सवाद की भौतिकवादी विचारधारा उन्हें उखाड़ सकी. फिर भी सात दशकों तक इन प्रतीकों को उपेक्षित रखा गया. कांग्रेस, वाम मोर्चा और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को एक बिखरे और आत्महीन राज्य में बदल दिया. वोट बैंक की राजनीति ने समाज को धार्मिक और क्षेत्रीय आधार पर विभाजित किया. बांग्लादेश से घुसपैठ ने सीमावर्ती जिलों को अस्थिर बना दिया. हिंसा ने निवेशकों को दूर भगा दिया. जो बंगाल कभी औद्योगिक शक्ति था, वह पूंजी पलायन, उद्योगहीनता और उगाही का पर्याय बन गया. वर्ष 1960-61 में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की 127.5 प्रतिशत थी, जो गिरकर 83.7 फीसदी रह गयी. राष्ट्रीय जीडीपी में राज्य की हिस्सेदारी 10.5 फीसदी से घटकर 5.8 प्रतिशत रह गयी. भाजपा ने इस अवसर को पहचाना. पंद्रह वर्षों तक उसने चुपचाप काम किया. अपमानित समूहों की पहचान की, हिंदुओं को उनके खतरे में पड़े धार्मिक प्रतीकों की याद दिलायी और चेताया कि जनसांख्यिकीय बदलाव उन्हें अपनी ही भूमि में अजनबी बना सकते हैं. संदेशखाली की घटनाओं, चुनाव के बाद की हिंसा और रोजमर्रा के अपमान से उपजा क्रोध अंततः विस्फोटित हुआ. हिंदुओं ने जाति और वर्ग से ऊपर उठकर अभूतपूर्व एकजुटता के साथ मतदान किया. लेकिन विजय के साथ सबसे कठिन परीक्षा भी आती है. शुभेंदु अधिकारी की सरकार को भाषणों से आगे बढ़कर परिणाम देने होंगे. बंगाल के लोग अब विकास चाहते हैं, जो समाज को जोड़े, तोड़े नहीं. उन्होंने हिंदू एकजुटता के लिए मतदान किया, अब वे व्यवहार में रामराज्य चाहते हैं. ऐसा शासन जो वंचितों की गरिमा लौटाये, निवेश को गुंडागर्दी के भय से मुक्त करे, सीमाओं को सुरक्षित बनाये और बंगाल की बौद्धिक व आर्थिक शक्ति पुनर्जीवित करे.

राइटर्स बिल्डिंग में वापसी इसी गहरे उद्देश्य का प्रतीक है. अब सचिवालय इतिहास से कटे आधुनिक भवन में नहीं बैठेगा. वह उन्हीं कक्षों में लौटेगा, जहां कभी औपनिवेशिक आदेश लिखे जाते थे और बाद में क्रांतिकारियों ने उनका विरोध किया था. इस स्थानांतरण के माध्यम से नयी सरकार ने यह घोषणा की कि बंगाल की पहचान न तो औपनिवेशिक अवशेष है और न ही वामपंथी प्रयोगशाला, बल्कि बंगाल भारत की निरंतर जीवंत धारा का हिस्सा है. आलोचक इस पर आपत्ति करेंगे. कुछ अन्य लोग धर्मनिरपेक्ष गढ़ों के अंत पर शोक जतायेंगे. जनादेश स्पष्ट है. मतदाताओं ने अतीत के टूटे वादों को अस्वीकार कर दिया. भूमि सुधारों ने कृषि को ठहराव दिया, औद्योगिक नीतियों ने विकास के स्थान पर हड़तालों को बढ़ावा दिया और अल्पसंख्यक राजनीति ने बहुसंख्यकों की बढ़ती चिंताओं की उपेक्षा की. नौ मई को हुए शपथ ग्रहण समारोह के बीज बंगाल के अपने राष्ट्रवादियों ने बोये थे. राजा राममोहन राय की तर्कशीलता, बंकिम का राष्ट्रप्रेम, सुभाषचंद्र बोस का साहस, अरविंद की दृष्टि और विवेकानंद का उत्साह अंततः फलित हुआ. इतिहास गेरुआ स्याही से पुनर्लिखित हो चुका है. आने वाले वर्ष तय करेंगे कि यह बंगाल की स्थायी लिपि बनेगा या केवल एक साहसी प्रथम अध्याय. फिलहाल एक सत्य निर्विवाद है. बंगाल की मूल आत्मा घर लौट आयी है. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

बढ़ते विकास की कीमत है बढ़ता कार्बन फुटप्रिंट

पद्मश्री डॉ अनिल प्रकाश जोशी
पर्यावरण कार्यकर्ता
dranilpjoshi@gmail.com

दुनिया में हर व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट लगातार बढ़ता जा रहा है. जितना बड़ा देश, उतना बड़ा फुटप्रिंट. जिस तरह खाद्य उत्पादों पर कैलोरी लिखी जाती है, वैसे ही हर उत्पाद पर यदि यह लिखा जाये कि उसके उपयोग से कितना कार्बन उत्सर्जन होता है, तो शायद हमारी सोच बदले.

अब हम चाहे जितनी भी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय बैठकें कर लें, शायद उस बड़े नुकसान से नहीं बच सकते, जो हम कर चुके हैं या भविष्य में करने वाले हैं. हमारी दिनभर की गतिविधियां पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद करने में जुटी हैं. इसके पीछे एक ही कारण है- ऊर्जा का अत्यधिक दुरुपयोग. सुबह से लेकर शाम तक हम किस तरह ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे समझने का समय अब आ चुका है. आज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,395 किलोवॉट बिजली का खर्च है. इस खर्च को कार्बन में परिवर्तित करने पर पता चलता है कि यदि प्रति किलोवॉट के कारण 0.9 किलोग्राम कार्बन फुटप्रिंट होता है, तो प्रति व्यक्ति हर वर्ष 1295.55 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन होगा. हम जिस तरह बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं, वह हमारे सामने है. शहरों में सुबह सात बजे तक स्ट्रीट लाइट या घरों में दिन में भी बल्ब जलते रहते हैं. बिजली की खपत के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहर भी हवा में छोड़ रहे हैं.

आज घरेलू काम के लिए उपयोग में आने वाले अनेक ऐसे उपकरण बाजार में मौजूद हैं, जिनसे न केवल हमारी शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं, बल्कि बिजली की खपत भी बढ़ती है. अकेले कूक टॉप 1,000 वॉट बिजली खा लेता है. कोयले का चूल्हा और लकड़ी की जगह अब एलपीजी गैस और इलेक्ट्रिक इंडक्शन ने ले ली है. फ्रिज के बिना तो आज हमारा काम ही नहीं चल पाता है. पर एक फ्रिज सालाना लगभग 200 से 300 किलोग्राम कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न करता है. यह भी ध्यान देने योग्य है कि अब हम डिजिटल वर्ल्ड के लोग बन चुके हैं. ईमेल, एसएमएस, कॉल- बात यहीं तक सीमित नहीं है. जो डाटा स्टोर किया जाता है, उसके लिए करोड़ों लीटर पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि डाटा सेंटर बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए. यह डिजिटल वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड का भी बड़ा स्रोत बन चुका है. आंकड़े बताते हैं कि यदि हम एक ईमेल भेजते हैं, तो प्रति ईमेल लगभग चार ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाता है. यदि उस ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट भेजा जाये, तो यह उत्सर्जन बढ़कर लगभग 20 से 50 ग्राम तक हो सकता है. इसके अतिरिक्त, हमारे मोबाइल में पड़े जंक मेल- प्रति मेल लगभग 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सालाना प्रकृति में जोड़ते हैं. टेलीविजन अपने पूरे जीवन चक्र में लगभग 100 से 300 किलोग्राम कार्बन फुटप्रिंट प्रकृति में जमा करता है. वाइ-फाइ राउटर भी अपने पूरे जीवन में लगभग 50 से 100 किलोग्राम कार्बन फुटप्रिंट पर्यावरण में छोड़ता है. डेस्कटॉप कंप्यूटर के उपयोग से करीब 300 से 600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है.

यदि यातायात व्यवस्था बेहतर न हो और गाड़ियों की लंबी कतारें जाम में फंसी रहें, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने का कारण बनती हैं. जब गाड़ियां खड़ी रहती हैं और इंजन बंद नहीं होते, तब भी वे कार्बन डाइऑक्साइड उगलती रहती हैं. यह पृथ्वी के तापमान बढ़ने का एक बड़ा कारण है. यदि हम अपनी जीवनशैली से जुड़ी अन्य सुविधाओं पर नजर डालें, विशेष रूप से उद्योगों और उनके उत्पादों पर, तो उन सभी का अपना-अपना कार्बन फुटप्रिंट होता है. हमारी आवश्यकताओं से जुड़े विभिन्न उद्योगों की कार्बन फुटप्रिंट में कुल भागीदारी लगभग 29.4 प्रतिशत है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग का योगदान लगभग 21.6 प्रतिशत, ट्रांसपोर्ट का 15.9 प्रतिशत और खेती-बाड़ी का 11.7 प्रतिशत होता है. एक और गंभीर समस्या ब्लैक कार्बन की है. जब गाड़ियों की लंबी कतारें पहाड़ी क्षेत्रों में लगती हैं, तो यह ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों पर जम जाता है और उनकी क्षमता समाप्त कर देता है. इससे बर्फ सूरज की किरणों को परावर्तित करने के बजाय उन्हें सोखने लगती है, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ जाता है. इसी कारण आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे क्षेत्रों में, जहां पहले जीवन संभव नहीं था, वहां अब जीवन के संकेत दिखाई देने लगे हैं. यह हमारे लिए खतरे की घंटी है.

दुनिया में हर व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट लगातार बढ़ता जा रहा है. जितना बड़ा देश, उतना बड़ा फुटप्रिंट. यदि बिजली की खपत के आधार पर अमेरिका, चीन और भारत की तुलना करें, तो अमेरिका सबसे आगे है, चीन दूसरे स्थान पर और भारत भी कहीं पीछे नहीं है. भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, पर यह भी समझना जरूरी है कि इस विकास की कीमत क्या है. हमारी जीवनशैली जिस दिशा में जा रही है, उससे पूरी तरह मुक्त होना आसान नहीं है. पर यदि हम बिजली के उपयोग में कटौती करें, उसका सीमित उपयोग सीखें और संरक्षण की कोशिश करें, तो शायद समय रहते स्वयं को बचा सकेंगे. अब दुनिया को बचाने से पहले जरूरी है कि हम स्वयं को बचायें. हमारी जीवनशैली पूरी तरह मशीनों पर निर्भर हो चुकी है. हर मशीन में जंग लगता है, तो हमारे शरीर में भी लगेगा. ऐसे में जिस तरह खाद्य उत्पादों पर कैलोरी लिखी जाती है, वैसे ही हर उत्पाद पर यदि यह लिखा जाये कि उसके उपयोग से कितना कार्बन उत्सर्जन होता है, तो शायद हमारी सोच बदले. प्रकृति का धैर्य अब जवाब दे चुका है और उसने अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया है. यदि हम अब भी नहीं समझे, तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

जापान के पुनर्सैन्यीकरण का उद्देश्य ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव उत्पन्न करना

हाल ही में ताइवान के क्षेत्रीय नेता लाई चिंग-ते, योइची हट्टा की स्मृति में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए ताइनान (ताइवान का एक शहर) गये थे. समारोह के दौरान लाई का रवैया चापलूसी भरा था. सही और गलत को तोड़-मरोड़कर पेश करना और एक पूर्व आक्रमणकारी को गले लगाना, न केवल ताइवान के क्षेत्रीय नेता द्वारा जापान की चापलूसी दर्शाता है, बल्कि ताइवान इंडिपेंडेंस फोर्सेज और जापान के नव-सैन्यवाद के बीच मिलीभगत की खतरनाक प्रवृत्ति को भी उजागर करता है. इस तरह का भाव ताइवान जलडमरूमध्य और व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है. यहां यह जानना जरूरी है कि योइची हट्टा कौन थे. योइची जापान की औपनिवेशिक नीति- कृषि प्रधान ताइवान, औद्योगिक जापान- के अग्रिम पंक्ति के एक मोहरे थे. ताइवान पर जापानी औपनिवेशिक शासन क्रूर दमन, संसाधनों के दोहन और ताइवानी लोगों को उनकी अपनी संस्कृति से दूर करने के लिए जाना जाता है. पर लाई ने उस इतिहास से मुंह मोड़ लिया है और औपनिवेशिक हिंसा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. यह ताइवान में जापानी औपनिवेशिक शासन का विरोध करने वालों की स्मृति और ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों ओर रहने वाले लोगों की साझा राष्ट्रीय भावनाओं का भी घोर अपमान है. लाई के लंबे समय से चले आ रहे जापान समर्थक और औपनिवेशिक समर्थक झुकावों पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक बात ताइवान इंडिपेंडेंस फोर्सेज और जापान के नव-सैन्यवाद के बीच बढ़ता तालमेल है. हाल के वर्षों में जापान ने पुनर्सैन्यीकरण की दिशा में कई कदम उठाये हैं, जिनमें दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों में सैन्य तैनाती को मजबूत करना भी है. ऐसा करने का उद्देश्य ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव पैदा करना है. पर ताइवान जलडमरूमध्य के मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करने वाली किसी भी बाहरी शक्ति को चीन की ओर से कठोर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

बोधि वृक्ष

शिष्यत्व का अर्थ है समर्पण

अर्जुन एवं कृष्ण गाढ़े मित्र थे. भगवान ने तब गीतोपदेश नहीं दिया था. परंतु कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन पूर्णतः उद्विग्न हो गये और उनके भीतर का शिष्य जाग उठा, तब अर्जुन ने अपने सारथी-सखा कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया. अर्जुन के भीतर शिष्यत्व के जागने पर ही कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया. इसमें हम सबके लिए शिक्षा छिपी है. हमें अपने भीतर शिष्य का भाव जागृत करना है. शिष्य भाव से अभिप्राय है- पूर्ण समर्पण. यदि हम यह कर सकें, तो पायेंगे कि विश्व की प्रत्येक वस्तु हमारी गुरु हो गयी है. प्रत्येक अनुभव हमें शिक्षा देने के लिए आता है. इस भाव के अभाव में हम कुछ नहीं सीख पायेंगे. आप सबको ढेर सारी चिंताएं हैं. परंतु कटे हुए हाथ देखकर रोने से कुछ नहीं होगा. घाव को मरहम-पट्टी की आवश्यकता है, ताकि संक्रमण न हो. परंतु, चिंता करते रहना हमारा स्वभाव हो गया है. तनाव हमारे मन पर ही नहीं, शरीर पर भी प्रभाव डालता है, बहुत से रोग लगा देता है. समर्पण तनाव मुक्ति का एकमात्र साधन है. सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देने से हमारा बोझ कम हो जाता है. सच तो यही है कि होनी हमारे वश में नहीं, अगली सांस तक हमारे वश के बाहर की बात है. इस ज्ञान के साथ हम सभी कर्म कर उन्हें ईश्वर को अर्पित कर दें, परंतु कर्तृत्व न लें. भाव यह रहे कि हम सब कर्म उनकी कृपा से कर रहे हैं. कर्म को पूजा मानकर करें. यही समर्पण का भाव हमें विकसित करना होगा. परमात्मा हम सबके भीतर आत्मा के रूप में वास करते हैं. प्रतिक्षण वह हमें सरल, मधुर शब्दों द्वारा राह दिखाते हैं. परंतु दुर्भाग्य, कि हम में सुनने का धैर्य ही नहीं, हम उनकी कही बात को सुनते ही नहीं. बारंबार गलतियों को दोहराते रहते हैं और फिर दुख पाते हैं. हमें शिष्यत्व के एक आवश्यक गुण- आज्ञा पालन को विकसित करना चाहिए. जब यह भाव जागृत हो जाता है, जब हम ध्यान से सुनते हैं, श्रद्धा तथा विनम्रतापूर्वक उनके शरणागत होते हैं, तब ही वह गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन करने का दायित्व लेते हैं. जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ.

-श्री माता अमृतानंदमयी देवी

कुछ अलग

आम हुए तो अचार बना दिये जायेंगे

सूर्यदीप कुशवाहा
व्यंग्यकार
sdkji85@gmail.com

आम केवल फल नहीं, बल्कि उस आम आदमी की श्रेणी में आना है, जिसकी पीठ पर लटक लोग खास बनते हैं. लोकतंत्र से लेकर कार्यालयों तक, आम होना किसी गाली से कम नहीं होता. जैसे ही गर्मी आती है, बाजार में आम की बाढ़ आ जाती है. जब संख्या बढ़ती है, तो कीमत गिरती है. यही नियम जनता पर भी लागू होता है. जब आप भीड़ का हिस्सा होते हैं, जब आपकी अपनी कोई अलग सोच या पहचान नहीं होती, तो समाज आपको दो कौड़ी का माल समझता है. चालाक बंदे को हमेशा ऐसे ही आमों की तलाश रहती है, जिन्हें काटकर, छीलकर मर्तबान में ठूंसा जा सके.

अचार बनाना, दरअसल एक व्यवस्थित वध है. पहले आपको आम आदमी के नाम पर चुना जाता है, फिर आप पर टैक्स का नमक छिड़का जाता है, महंगाई की मिर्च डाली जाती है और नियमों की हल्दी में लपेटकर सालों-साल के लिए ठंडे बस्ते में बंद कर दिया जाता है. अचार की खूबी यही है कि वह जितना पुराना होता है, उतना ही गल जाता है. खास लोग भी यही चाहते हैं कि आप इतने गल जायें कि कभी अपना सिर न उठा सकें. मर्तबान के भीतर की उस घुटन को ही हम मिडिल क्लास स्टेबिलिटी कहते हैं. यहां स्पेशल बनने की नसीहत कोई मोटिवेशनल स्पीकर का जुमला नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा का आखिरी हथियार है. जो फल दुर्लभ होता है, वह चांदी की प्लेट में सजाकर किसी वातानुकूलित कमरे की मेज पर रखा जाता है. उसे काटने से पहले सौ बार सोचा जाता है. लेकिन आम के साथ कोई सहानुभूति नहीं होती. उसे तो डंडे मार-मारकर पेड़ से गिराया जाता है और बोरे में भरकर मंडी भेज दिया जाता है. राजनीति के बाजार में तो आम होने का स्वाद ही निराला है. नेता चुनाव के समय इसी आम आदमी के गुण गाते हैं, पर जब वे सत्ता की मेज पर बैठते हैं, तो उसी आम का अचार निकालकर पराठे के साथ मजे ले-लेकर खाते हैं.

आम आदमी की नियति ही यह है कि वह दूसरों का जायका बढ़ाये, स्वयं चाहे सिर से पैर तक तेल और मसाले में क्यों न डूबा रहे. इसलिए, यदि आप अपनी मौलिकता को बचाकर नहीं रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को बचाये रखने की बजाय हां में हां मिलाने वाले आम बनेंगे, तो यकीन मानिए, समाज की कैंची तैयार खड़ी है. आपको काटकर आपकी पहचान का ऐसा अचार डाला जायेगा कि आने वाली नस्लें भी उसी स्वाद में खुद को भुला देंगी. आज के दौर में खास होना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है. याद रखिए, मर्तबान का ढक्कन खुला है और समाज नमक हाथ में लिये आपकी बारी का इंतजार कर रहा है. आम हुए तो अचार बना दिये जायेंगे!

आपके पत्र

देश की प्रथम डिजिटल जनगणना

इस बार की जनगणना देश की प्रथम डिजिटल जनगणना है. इसमें नागरिकों को 'स्व गणना' के माध्यम से अपने भवन, मकान की जानकारी स्वयं दर्ज करने की सुविधा भी दी गयी है. ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पोर्टल के माध्यम से जनगणना में अपनी भागीदारी निभायें. आम जन से मेरा निवेदन है कि वे समाचार पत्रों में आ रहे सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से मकान सूचीकरण में अपना योगदान दें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत करें.

माणिक मुखर्जी, सरायकेला-खरसावां

एंबुलेंस को रास्ता देना आवश्यक

अक्सर देखा जाता है कि यदि कोई एंबुलेंस ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, तो उसका तेजी से निकलना मुश्किल हो जाता है, जबकि मरीज का अस्पताल पहुंचना अति आवश्यक होता है. यदि मरीज कम गंभीर हैं, तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बड़े वाहनों की जगह छोटे वाहन जैसे, ऑटो रिक्शा या दुपहिया को एंबुलेंस की तरह काम में लिया जाये, तो इस समस्या से कुछ हद तक निपटा जा सकता है. आम जन को भी जाम के दौरान एंबुलेंस के निकलने के लिए रास्ता बनाना चाहिए.

विनय मोघे, पुणे

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

प्रेरणा

अच्छाई निवेश है, जो अच्छा रिटर्न देती है। दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार ही महान बनाता है। - सिसरो

संपादकीय

कृषि व उद्योगों को निर्यात पर फोकस करना होगा

खर्चों में कटौती सम्बंधी प्रधानमंत्री के कथन को वास्तव में गलत समझा गया है। उन्होंने सिर्फ आडम्बरनिष्ठ उपभोग घटाने को कहा है, जैसे निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग, गहने खरीदने, विदेशी सामान की ललक या विदेश-यात्रा से बचना और इंटरनेट के युग में वर्क-फ्रॉम-होम करना। लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार को इसे और स्पष्ट तरीके से बताना होगा। यह तो सर्वविदित है कि उपभोग पर अंकुश की सलाह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होती है। खपत नहीं होगी तो उत्पादन और रोजगार भी घटेंगे। दूसरे, सरकारी अर्थशास्त्रियों को दूसरे तरीकों जैसे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आपूर्ति की कमजोरी से ज्यादा विदेशी मुद्रा जा रही हो तो निर्यातपरक उत्पादन पर ध्यान दें और ऊर्जा का देशज व अन्य विकल्प भी तलाशें। देश के निजी अंतिम उपभोग खर्च (पीएफसीई) का हिस्सा जीडीपी में 60% है और एक बड़ा वर्ग जीवन भर जीवित रहने योग्य ही कमाई करता है। प्रधानमंत्री की अपील बड़ी गाड़ियों से चलने वालों, विदेशी लग्जरी आइटमों पर देश का डॉलर खर्च करने वालों के लिए है। पांच-सितारा होटल में 500 रुपये कप वाली चाय पीने से यह धन रोजगार-सृजन वाले उत्पादन-चक्र में नहीं जाता, जबकि बाहर के ढाबे में दस रुपये की चाय पीने पर यह छोटी रकम भी रोजगार सृजन करती है। हमें संकट के समय सही नीतियां लानी होंगी। समय आ गया है कि हम कृषि और औद्योगिक उत्पादन को सस्ता और निर्यातपरक बनाएं।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

ज्ञान, कर्म और उपासना को समझकर छद्म से बचें

आज के लग्जरी मार्केट में ब्रांडेड वस्तुओं में भी लगभग 8% माल नकली बताया जाता है तो सामान्य वस्तुओं की तो बात छोड़ ही दें। खान-पान की वस्तुएं नकली, किसी के नाम से कोई और परीक्षा दे दे, नौकरी किसी के नाम और कर कोई और रहा है और अब तो एआई के कारण नकली-असली का पता लगाना भी मुश्किल है। शास्त्रों में भी कई प्रसंग ऐसे आते हैं। रावण नकली साधु बनकर सीता जी का अपहरण कर गया। विष्णु जी ने भी कुछ प्रसंगों में असली-नकली का खेल खेला। देवताओं के गुरु ब्रह्मा जी तो नकली शुक्राचार्य बन गए, जो दैत्यों के गुरु थे। शूर्पनखा के प्रसंग से भी हम समझ सकते हैं कि जीवन में जब असली-नकली का मुकाबला आए तो ज्ञान, कर्म और उपासना के मार्ग को समझकर इससे निपटा जाए। शूर्पनखा जो थी, वैसी न बनकर नकली होकर आई। सामने थे राम, लखन, सीता। शूर्पनखा की नाक कट गई। राम ज्ञान हैं, लखन कर्म हैं और सीता उपासना हैं। अगर ये तीनों मार्ग सही हैं तो नकली से हम ठगाएंगे नहीं और असली का सदुपयोग कर जाएंगे।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

शब्दों का जादू

कबीर की चादर

कबीर ने बुनी सूत के ताने-बाने से एक चादर
और उढ़ा दी प्रेम से लोई को

कबीर ने दूसरी चादर बुनी
और बेच आए काशी के हाट में
आखिर पालना था कमाल और कमाली को

कबीर ने तीसरी चादर बुनी
और दे दी किसी साधो को समझाते हुए-
'सुनो भई साधो!' यह जानकर भी
कि 'कहा न मानत कोई रे'

कबीर ने उढ़ाई नहीं चादर
किसी सुलतान को और न किसी मठाधीश को

कबीर ने फैलाई नहीं चादर
भिक्षा के लिए!

बस कबीर ने एक चादर और बुनी
इंगला पिंगला सुखमन तार से
और ओढ़ लिया उसे बड़े ही जतन से...

–नरेश जैन, जबलपुर
(मूल कविता के सम्पादित अंश)

पूरी कविता को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

चुनावों में रेवड़ी कल्चर पर रोक लगे

तमिलनाडु में थलापति विजय की जीत में स्टारडम के साथ उनके मुफ्त सौगातों के वादों की भी अहम भूमिका है। रेवड़ी बांटना अब चुनाव जीतने का मंत्र बन गया है। इससे राज्यों पर कर्ज बढ़ रहा है। चुनाव आयोग को ऐसी राजनीति पर रोक लगानी होगी।
–आदित्य शेखर, इंदौर, मध्यप्रदेश

समुद्री जीवन पर खतरा

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट बंद है। ईरान के सभी तेल स्टोरेज फुल होने से वह रोजाना 2800 करोड़ रुपए का तेल समुद्र में बहा रहा है। सोचिए, इससे समुद्री जीवन को कितना नुकसान पहुंचेगा? विकसित देशों की महत्वाकांक्षाओं के कारण ये नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। –सुनील खासगीवाला, सूरत, गुजरात

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

सबसे बड़ी जैविक इकाई एक फंगस है

दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात जैविक इकाई अमेरिका के ओरेगन में मिला एक हनी मशरूम नेटवर्क है। यह फंगस नेटवर्क 'आर्मिलारिया ओस्टोये' कहलाता है। 1992 के एक शोध में 47 हजार अलग तनों से बने इस फंगस के एक ही इकाई होने की पुष्टि हुई थी। इसकी उम्र करीब 2400 वर्ष आंकी गई है।
965 हेक्टेयर में फैला है यह विशालकाय फंगस नेटवर्क।

बामुलाहिजा • भाजपा को आज वही चुनौती दे पाएगा, जो हिंदुओं के साथ भरोसे का रिश्ता बना सके

क्या अब राजनीति में मुसलमान हाशिये पर हैं?

सियासत

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
@ShekharGupta

करीब सात साल पहले मैंने एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था : 'क्या मुसलमान भाजपा के लिए कोई अहमियत रखते हैं?' हाल के राज्यों के चुनाव नतीजे- खासकर बंगाल और असम के- जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 30% से ज्यादा है- दिखाते हैं कि यह मुद्दा अब और बड़ा हो गया है। राजनीतिक तौर पर तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मुसलमान आज भाजपा के लिए 2019 के मुकाबले काफी कम मायने रखते हैं।

बंगाल और असम में भाजपा ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे बिना दो-तिहाई सीटें जीत लीं। दूसरी तरफ, असम में विपक्ष के जीते 24 उम्मीदवारों में से 22 मुस्लिम हैं। इनमें भी कांग्रेस के 19 जीते उम्मीदवारों में से 18 मुस्लिम हैं। बंगाल में 293 नए विधायकों में 40 मुस्लिम हैं, जिनमें से 34 टीएमसी के हैं। यानी टीएमसी के कुल 80 जीते उम्मीदवारों में से 45 फीसदी मुस्लिम हैं। इसका मतलब यह है कि जिन दो राज्यों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है (जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं है), वहां मुसलमान सत्ता से बाहर हो चुके हैं। भाजपा और सेकुलर पार्टियों के बीच हिंदू-मुस्लिम आधार पर बंटवारा साफ हो गया है।

केरल में यूडीएफ के 102 नए विधायकों में 30 मुस्लिम और 29 ईसाई हैं। सेकुलर खेमे को इस बात से राहत हो सकती है कि कम से कम केरल में मुसलमान सत्ता में शामिल हैं, लेकिन यह राहत इस डर से कम हो जाती है कि भाजपा अब इसे अल्पसंख्यकों की सरकार बताकर हिंदू वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश करेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 18वीं लोकसभा में कुल 24 मुस्लिम सांसद हैं, यानी सिर्फ 4.42 फीसदी, जबकि देश में मुस्लिम वोटरों की आबादी 15 फीसदी से ज्यादा है। 16वीं लोकसभा में 22 और 17वीं लोकसभा में 27 मुस्लिम सांसद थे। जबकि 1980 में 49 और 1984 में 45 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। तब उनका प्रतिशत क्रमशः 9 और 8.3 था। लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या अकसर 5 फीसदी के आसपास रही है, लेकिन केंद्र में उन्हें हमेशा अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता रहा। यहां तक कि वाजपेयी सरकार में सिकंदर बख्त मंत्री थे।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपसभापति जैसे पदों से लेकर सेना और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख पदों तक मुसलमान पहुंच चुके हैं, लेकिन आज वे किसी भी ऐसे पद पर नहीं हैं। आज कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। सिर्फ एक मुस्लिम राज्यपाल हैं- बिहार में सैयद अता हसनैन। केंद्र सरकार के करीब 100 सचिवों में सिर्फ एक मुस्लिम हैं- कामरान रिजवी- जो हैवी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सचिव हैं। सुप्रीम कोर्ट के 32 जजों में भी सिर्फ एक मुस्लिम जज हैं- जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह। भारत के आखिरी मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एएम अहमदी थे, जो 24 मार्च 1997 को रिटायर हुए थे।

यह सब देखकर ऐसा लग सकता है कि भारतीय मुसलमानों को किनारे कर दिया गया है, लेकिन इस सोच पर फिर से विचार करने की जरूरत है। डॉक्टरी, कानून, शिक्षा, विज्ञान, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, मनोरंजन और मीडिया जैसे क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। सिविल सेवा और सेना में भी उनका चयन बढ़ा है। इसलिए समस्या यह नहीं है कि मुसलमान हर क्षेत्र से बाहर हो रहे हैं। असली समस्या यह है कि राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है। 1996 में वाजपेयी सरकार 13 दिन चली थी और 1999 में एक वोट से गिर गई थी। तब भाजपा नेता बलबीर पुंज इस बात से नाराज थे कि मुस्लिम वोटों पर निर्भर पार्टियां भाजपा को स्वीकार नहीं कर रही थीं। उनका मानना था कि मुसलमान तय कर रहे थे भारत पर कौन राज करेगा और कौन नहीं, लेकिन अब यह स्थिति बदल गई है।

ये तथ्य तीन बड़े निष्कर्षों की ओर इशारा करते हैं। एक, भाजपा की विरोधी या सेकुलर पार्टियों को भाजपा अब

पार्टियों में हिंदू-मुस्लिम बंटवारा अब और स्पष्ट है...

भाजपा के लिए मुस्लिम वोटर्स अब जरूरी नहीं रह गए हैं। ऐसे में क्या कोई हिंदू-नेतृत्व वाला राजनीतिक गठबंधन ही उसे चुनावों में चुनौती दे सकता है? क्योंकि यह तो साफ है कि भाजपा और सेकुलर पार्टियों के बीच हिंदू-मुस्लिम बंटवारा अब और मजबूत हो गया है।

मुस्लिम पार्टियों की तरह पेश करना चाहती है, जबकि उनके नेता हिंदू हैं। इससे हिंदू बनाम बाकी सब वाला माहौल बनता है, जो 80 फीसदी बनाम 20 फीसदी की राजनीति में बदल जाता है। यह भाजपा के लिए सबसे फायदेमंद स्थिति है। भाजपा चुनिंदा इलाकों में ईसाइयों के बीच भी काम करती है। गोवा और केरल में उसे इसका मौका मिला है। भाजपा के पास धैर्य भी है और समय भी। उत्तर-पूर्व में उसने ईसाई जनजातियों के साथ सुविधाजनक रिश्ता बना लिया है। वहां उसने कभी गोमांस पर प्रतिबंध की मांग नहीं की।

अब भी कुछ सेकुलर पार्टियां मुस्लिम वोटों पर निर्भर हैं, लेकिन वे इतनी सतर्क हो गई हैं कि मुसलमानों के समर्थन में खुलकर बोलने से भी बचती हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने शाहीन बाग आंदोलन और उसके बाद हुए दंगों के दौरान चुप्पी बनाए रखी। इससे धर्मनिरपेक्षता बचाने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर आ गई है। यह न सिर्फ मुश्किल और अव्यावहारिक है, बल्कि गलत भी है। आज मुसलमानों से कहा जाता है कि वे उसी उम्मीदवार को वोट दें, जो भाजपा को हरा सके। इसके पीछे यह उम्मीद होती है कि इससे उन्हें सुरक्षा मिलेगी। एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए यह बहुत कमजोर सोच है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी बताती है कि इससे मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ।

अब सेकुलर दलों को हिंदुओं के साथ इतना बड़ा गठबंधन बनाना होगा, जो जीत दिलाने वाला वोट प्रतिशत जुटा सके। पहले हिंदी पट्टी की पार्टियां जाति के आधार पर हिंदुओं को बांटकर जीत हासिल करती थीं, लेकिन भाजपा ने उस राजनीति को तोड़ दिया है। अगर मुसलमान अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, तो उससे भाजपा को ही फायदा होगा और उसकी ताकत बढ़ेगी। जिन्ना के बाद भारत के मुसलमानों ने कभी किसी मुस्लिम नेता को अपना सबसे भरोसेमंद नेता नहीं माना। वे नेहरू-गांधी परिवार, यूपी-बिहार के यादव नेताओं, ममता बनर्जी और कई जगहों पर वाम दलों के हिंदू नेताओं पर भरोसा करते रहे हैं। लेकिन वे पहले कभी इस तरह सत्ता से बाहर नहीं हुए थे, जैसे आज हैं। इसे ठीक करने का एक ही तरीका है- ऐसा नेतृत्व उभरे, जो बड़ी संख्या में हिंदुओं को साथ लेकर नया गठबंधन बनाए। भारत के हिंदुओं ने ही संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को चुना था, इसलिए उसे बचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। भाजपा को वही चुनौती दे पाएगा, जो हिंदुओं के साथ भरोसे का रिश्ता बना सके। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

विश्लेषण • ऊर्जा संकट से बचने का उपाय नहीं है

सस्ती एनर्जी का दौर फिलहाल के लिए तो खत्म हो चुका है

युद्धकाल

पलकी शर्मा
इंडिया ग्लोबल रिव्यू की संस्थापक
@palkisu

वैश्विक तेल संकट अब भारत के घरेलू बजटों को प्रभावित करने वाला है। दुनिया भर में सरकारें पहले ही किसी न किसी रूप में ऊर्जा-अनुशासन लागू करने लगी हैं। श्रीलंका ने चार-दिवसीय वर्क-वीक और ईंधन पास की नीति लागू की है। बांग्लादेश ने ईंधन की राशनिंग शुरू कर दी है। फिलीपींस ने ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। दक्षिण कोरिया ने तीन दशकों में पहली बार ईंधन मूल्य सीमा लागू की है। जापान ने रिकॉर्ड रणनीतिक भंडार जारी किए। यूरोपीय देश नागरिकों को ऊर्जा बचाने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि कई बाजारों में पेट्रोल की कीमतें 200 रु. प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुकी हैं। सस्ती एनर्जी का युग समाप्त हो चुका है, कम-से-कम फिलहाल के लिए।

इसका कारण हजारों किलोमीटर दूर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में निहित है। यह संकीर्ण जलमार्ग दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। ईरान युद्ध इस महत्वपूर्ण मार्ग को अनिश्चितता के क्षेत्र में बदल चुका है। तेल टैंकरों के मार्ग बदले जा रहे हैं, शिपिंग बीमा लागतों में विस्फोटक वृद्धि हुई है, माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है और आपूर्ति शृंखलाएं बाधित हैं। भारत तो दुनिया की सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में है। हमारे लगभग 50% कच्चे तेल और 90% रसोई गैस का आयात होर्मुज से होता है। सरल शब्दों में कहें तो जब पश्चिम एशिया में आग लगती है तो खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है।

अभी तक भारतीय उपभोक्ताओं को इस संकट के सबसे बुरे प्रभाव से बचाकर रखा गया है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें अधिकांशतः स्थिर बनी हुई हैं। न तो राशनिंग हुई है, न पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन इसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ी है। सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने भारी अंडर-रिकवरी का बोझ उठाया। रिफाइनरियों को असामान्य रूप से ऊंची क्षमता पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। एक तरह से राज्य ने उस झटके का एक हिस्सा स्वयं वहन किया, जिसे अन्यथा बाजार सीधे उपभोक्ताओं पर डाल देता।

आलोचकों का कहना है कि यह कदम राजनीतिक कारणों के चलते उठाया गया, कि चुनाव समाप्त होने तक ईंधन की कीमतों को कृत्रिम रूप से दबाकर रखा गया, और अब उपभोक्ताओं को मूल्य-वृद्धि के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन यह तर्क उस व्यापक हकीकत की अनदेखी करता है, जिसका सामना हर तेल-आयातक अर्थव्यवस्था कर रही है।

दुनिया भर की सरकारों के सामने यही दुविधा थी कि झटके को तुरंत उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाए और महंगाई को भड़का दिया जाए, या उसे अस्थायी रूप से स्वयं वहन किया जाए। अधिकांश सरकारों ने किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप का रास्ता चुना। भारत ने भी यही किया। क्योंकि ईंधन की कीमतें पेट्रोल पम्प पर लिखे अलग-थलग आंकड़े नहीं होतीं, उनका प्रभाव

युद्ध की लागत किसी-न-किसी को वहन करनी ही पड़ती है, और वह अमूमन उपभोक्ता ही होता है। भारतीयों ने युद्ध शुरू नहीं किया था। लेकिन दुनिया के अन्य उपभोक्ताओं की तरह इसकी कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ेगी।

पूरी अर्थव्यवस्था में फैलता है- डीजल की ऊंची कीमतें परिवहन लागत बढ़ाती हैं, इससे खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती है, हवाई यात्रा की लागत बढ़ जाती है और महंगाई व्यापक रूप से फैलकर असर डालती है।

यदि युद्ध कल समाप्त हो जाए, तब भी कीमतें अचानक सामान्य नहीं होंगी। टैंकरों को पहुंचने में हफ्तों लगते हैं, युद्धविराम की घोषणा के बाद भी बीमा दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, देशों को अपने घट चुके भंडार फिर से भरने में समय लगता है, व्यापारी सतर्क बने रहते हैं, और आपूर्ति शृंखलाएं धीरे-धीरे ही सामान्य हो पाती हैं। आप इसकी कीमत या तो सीधे ऊंचे ईंधन दामों के रूप में चुकाते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से करों, महंगाई, राजकोषीय दबाव और सरकार के अन्य क्षेत्रों में घटे हुए खर्च के माध्यम से। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। **(ये लेखिका के अपने विचार हैं)**

दूरदृष्टि • अमेरिका और चीन की बीजिंग समिट

ट्रम्प को चीन से कोई 'बिग ब्यूटीफुल डील' नहीं मिलेगी

भू-राजनीति

मनोज जोशी
विदेशी मामलों के जानकार
manoj1951@gmail.com

ट्रम्प और शी जिनपिंग की मुलाकात जल्द ही बीजिंग समिट में होगी। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रम्प की यह पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले, अक्टूबर 2025 में दोनों नेता दक्षिण कोरिया के बुसान में मिले थे। पहले कार्यकाल में ट्रम्प ने चीन के साथ अमेरिका के दशकों पुराने जुड़ाव को खत्म कर दिया था। एक साल तक दोनों देशों के बीच चले टैरिफ युद्ध के बाद अब ट्रम्प की इस यात्रा का उद्देश्य शायद दोनों देशों के बीच रिश्तों को फिर से बहाल करना है। चीन से अमेरिका के पुराने रिश्ते इस भ्रम पर आधारित थे कि पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव चीन को अधिक खुला और लोकतांत्रिक बनाएगा। लेकिन नया रिश्ता ऐसे चीन से निपटने की व्यावहारिक जरूरत है, जो पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में है और एक आर्थिक तथा तकनीकी महाशक्ति बन चुका है।

निःसंदेह, शानो-शौकत और दिखावे के शौकीन ट्रम्प का चीन में बेहद भव्य स्वागत होगा। कुछ प्रतीकात्मक कदम और कारोबारी समझौते हो सकते हैं। लेकिन जोर प्रतिस्पर्धा खत्म करने पर नहीं, उसे मैनेज करने पर ही रहेगा। बुसान में शी-ट्रम्प के बीच हुए टैरिफ समझौते को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तकनीकी, सुरक्षा और भू-राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्रों में दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता में कोई बदलाव नहीं आएगा।

चीन के लिए ताइवान अहम प्राथमिकता है। पिछले साल ट्रम्प ताइवान के लिए 11 अरब डॉलर के हथियार पैकेज की मंजूरी दे चुके हैं। लगभग 14 अरब डॉलर के अन्य पैकेज भी प्रक्रियाधीन हैं, जिनमें अत्याधुनिक मिसाइलें शामिल हैं। चीन ने अमेरिका को कहा था कि वह ताइवान को हथियार बेचने के मुद्दे पर सावधानी बरते। इसी बीच, ताइवान की विपक्षी पार्टी केएमटी की चेयरपर्सन चेंग ली-वुन की चीन में शी से हालिया मुलाकात यह संकेत देती है कि ताइवान को लेकर चीन के पास सैन्य विकल्पों के अलावा और भी रास्ते हैं। शी-ट्रम्प बैठक का सबसे संभावित नतीजा यही होने वाला है कि दोनों पक्ष अपने-अपने रुख दोहराएंगे और मतभेदों पर परदा डालने की कोशिश करेंगे।

फिर ये बातचीत ऐसे समय हो रही है, जब ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया पर है और दोनों नेताओं की मुलाकात तक इसके समाप्त होने की संभावना भी नहीं दिख रही। निश्चित ही बातचीत में ईरान बड़ा विषय रहेगा, क्योंकि वह चीन का करीबी साझेदार है और उसके तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा चीन में ही जाता है। ट्रम्प शायद चीन पर दबाव बनाएंगे कि वह होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को राजी करे। वैसे भी चीन इसका समर्थन करता है। चीन भी इसे इस नजरिए से देखेगा कि ईरान मसले ने अमेरिका का ध्यान पूर्वी एशिया से हटा दिया है। कई विश्लेषक पहले ही क्वाड की घटती प्रासंगिकता की ओर इशारा कर चुके हैं। 2025 में क्वाड का कोई समिट नहीं हुआ और कब होगा, यह भी तय नहीं। हालांकि, इसी माह के अंत में क्वाड देशों की बैठक नई दिल्ली में होने वाली है।

चीन के प्रति ट्रम्प की शत्रुता कम नहीं हुई है, लेकिन उनका अंदाज बदल गया है। धमकियां नाकाम होने पर अब वे दोस्ताना और सौदेबाजी वाला रवैया आजमा रहे हैं। ट्रम्प शी जिनपिंग के साथ समिट को एक शानदार जीत के रूप में पेश करना चाहेंगे।

हाल ही एक पोस्ट में ट्रम्प ने इस यात्रा को लेकर उम्मीदों को अपने अंदाज में जाहिर किया। उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट खुलने से चीन बहुत खुश है। ट्रम्प ने लिखा, 'मैं यह पूरी दुनिया के लिए और उनके लिए भी कर रहा हूं।' उन्होंने यह भी कहा कि चीन ने ईरान को हथियार नहीं भेजने पर सहमति जताई है। वैसे चीन के प्रति ट्रम्प की शत्रुता कम नहीं हुई है, लेकिन उनका अंदाज बदल गया है। धमकियां नाकाम होने पर अब वे दोस्ताना और सौदेबाजी वाला रवैया आजमा रहे हैं। ट्रम्प अपनी शैली के मुताबिक इस समिट को एक शानदार जीत के रूप में पेश करना चाहेंगे, जिसमें कोई 'बिग ब्यूटीफुल डील' हो जाए। लेकिन चीन समझदार है और शायद ही उन्हें उनकी उम्मीदों के मुताबिक कोई बड़ी डील देगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मुद्दा • भारत के मौजूदा 50 डेटा सेंटर पहले ही ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां पानी की भारी किल्लत है, यह बड़ी समस्या...

एआई में आगे बढ़ने के लिए विदेशी डेटा सेंटरों को छूट कितनी उचित?

टेक्नोलॉजी

अरूंधती काटजू
ऋचा राय
कानूनी मामलों की जानकार

भारत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका एक जरिया विदेशी कंपनियों के लिए भारत में डेटा सेंटर की स्थापना को आसान करना भी है। डेटा सेंटर ऐसी कंप्यूटर सिस्टम्स फेसेलिटी हैं, जो डेटा स्टोर करने में इस्तेमाल होती हैं और क्लाउड स्टोरेज से लेकर एआई तक हर चीज को सपोर्ट करती हैं। इस साल के बजट में विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 21 साल की टैक्स छूट दी गई है। केंद्र की इस टैक्स छूट के अलावा, राज्य सरकारों ने भी विदेशी डेटा सेंटरों को कई तरह के प्रोत्साहन दिए हैं।

लेकिन अमेरिका में देखें तो इन्हीं कंपनियों के डेटा सेंटरों में बड़े निवेश के प्रस्ताव स्थानीय विरोध के कारण वापस ले लिए गए हैं। तब सवाल उठता है कि एआई इकोनॉमी में प्रवेश करने के लिए विदेशी डेटा सेंटरों की मेजबानी करना क्या भारत के लिए सही रणनीति है?

पहले तो हम देखें कि इस टैक्स छूट को लेने वाली विदेशी कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई शर्त नहीं रखी गई है और न ही भारत में एआई मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के कोई प्रावधान हैं। मौजूदा भारत-अमेरिका ट्रेड फ्रेमवर्क के तहत भारत ने वादा किया है कि वह तकनीकी समेत 500 अरब डॉलर तक की अमेरिकी वस्तुएं और सेवाएं खरीदेगा। अमेरिकी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों पर आयात प्रतिबंध भी हटाएगा। ऐसे में बहुत संभावना है कि भारत में डेटा सेंटर चलाने वाली कंपनियां घरेलू क्षमता विकसित करने के बजाय अमेरिका से उपकरणों का आयात करेंगी।

गौरतलब यह भी है कि डेटा सेंटर चलाने वाली भारतीय कंपनियों को इस टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि यह केवल विदेशी कंपनियों के लिए है। इन हालात में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बगैर डेटा सेंटर इनोवेशन के इंजन नहीं, महज गोदाम बनकर रह जाते हैं। इस टैक्स छूट के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डेटा सेंटरों के लिए एक योजना लाए। इसमें नॉलेज ट्रांसफर और भारतीय कंपनियों के लिए सीधे प्रोत्साहन का प्रावधान शामिल हो। इनके बिना भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने तक ही सीमित रहेगा, एआई क्षमता विकसित नहीं कर पाएगा।

दूसरी बात, डेटा सेंटरों में अत्यधिक बिजली खपत होती है और उन्हें कूलिंग के लिए पानी की बहुत अधिक जरूरत होती है। भारत जैसे देश में इनके लिए नियामक प्रावधान की जरूरत है, जहां हीटवेव और जल संकट पहले ही जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आम तौर पर तर्क दिया जाता है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है और पर्यावरण संबंधी ये चिंताएं तो पश्चिमी देशों की लग्जरी हैं। लेकिन यह तर्क भारत में जल संकट के खतरे को नजरअंदाज करता है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन जल संसाधन केवल 4% हैं। भारत के मौजूदा 50 डेटा सेंटर पहले ही ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां पानी की भारी किल्लत है।

विदेशी डेटा को भारत में रखने के भू-राजनीतिक जोखिम भी हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध में ईरान ने यूएई और बहरीन में एडब्ल्यूएस डेटा सेंटरों पर हमला किया। ईरान ने जिन लक्ष्यों की सूची जारी की, उनमें भी प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों के डेटा सेंटर शामिल थे और उन्हें 'एनिमी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर' के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। डेटा सम्प्रभुता का सिद्धांत भी कहता है कि डिजिटल डेटा उसी देश के कानूनों या न्यायिक क्षेत्र के अधीन होता है, जहां वह भौतिक रूप से उत्पन्न और स्टोर होता है। बजट में भी प्रावधान है कि विदेशी कंपनी ऐसे 'स्पेसिफाइड डेटा सेंटर' के माध्यम से काम करे, जो भारतीय स्वामित्व में हो।

(ये लेखिकाओं के अपने विचार हैं)

बिज़नेस भास्कर
Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ
नई दिल्ली, बुधवार 13 मई , 2026

नया दौर • जनवरी-मार्च में मिडकैप की कमाई औसतन 29% बढ़ी, पर लार्जकैप कंपनियों की 14% ही

2026: सेंसेक्स 12% टूटा, पर स्मॉलकैप में 4% तेजी

मजबूतीः मिडकैप इंडेक्स इस साल अब तक स्थिर

देवांशु सिंगला | नई दिल्ली

अमेरिका-ईरान तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच शेयर बाजार दबाव में है। लेकिन मिड और स्मॉलकैप कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर है। विश्लेषकों का मानना है कि इस साल सिर्फ वही कंपनियां टिकेंगी, जिनकी कमाई मजबूत और बिजनेस टिकाऊ होगा।

घरेलू शेयर बाजार के लिए 2026 अब तक दो अलग-अलग तस्वीरों वाला साल रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 12.5% टूट चुका है। लेकिन मिडकैप स्थिर और स्मॉलकैप इंडेक्स बढ़त में हैं। 31 दिसंबर, 2025 के मुकाबले मंगलवार तक बीएसई का मिडकैप इंडेक्स सिर्फ -0.1% गिरा और स्मॉलकैप इंडेक्स 4% चढ़ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तेजी सिर्फ नकदी की भरमार या जोश का नतीजा नहीं, बल्कि मजबूत कमाई की वजह से है। जनवरी-मार्च तिमाही में कई मिड और स्मॉल कंपनियों ने बड़ी कंपनियों से बेहतर ग्रोथ दिखाई।

किस श्रेणी के शेयरों ने कितना रिटर्न दिया? (इस साल अब तक, आंकड़े % में)

सेंसेक्स	निफ्टी	लार्जकैप	मिडकैप	स्मॉलकैप
-12.5	-10.5	-6.7	-0.1	+3.9

आगामी महीनों में मुनाफे की ठोस उम्मीद वाली कंपनियों के शेयरों में ही तेजी के आसार

शेयरों के प्रदर्शन पर संबंधित कंपनी की कमाई का असर

- जनवरी-मार्च में मिडकैप कंपनियों की कमाई औसतन 29% बढ़ी
- इन कंपनियों ने 22% आय वृद्धि के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया
- बीती तिमाही बड़ी (लार्जकैप) कंपनियों की कमाई औसतन 14% ही बढ़ी
- 70% स्मॉलकैप कंपनियों ने अनुमान के बराबर या उससे बेहतर नतीजे दिए

(स्रोतः मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज)

इन प्रमुख सेक्टरों ने इस साल शेयर बाजार को सपोर्ट किया

बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस (बीएफएसआई), टेक्नोलॉजी, रियल्टी, यूटिलिटीज, तेल-गैस ने मिडकैप कंपनियों की आय वृद्धि में 87% योगदान दिया।

वैश्विक तनाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका, ऐसे हालात में कमजोर कंपनियों के शेयर ऊंचे वैल्युएशन पर होल्ड करना रिस्की

आगामी महीनों में इन सेक्टरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद... ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी खर्च, घरेलू मांग और अर्थव्यवस्था में फॉर्मल सेक्टरों के उभार से उभरती कंपनियों को फायदा मिलेगा। इन सेक्टरों के शेयरों में तेजी आ सकती हैः
- इंफ्रास्ट्रक्चर
- मैन्युफैक्चरिंग
- डिफेंस
- एनर्जी ट्रांजिशन
- इंपोर्ट सब्स्टीट्यूशन
- कैपिटल एक्सपेंडिचर
- कंजम्पशन

...लेकिन ये चार चीजें बढ़ा रहीं निवेशकों का जोखिम, इन पर नजर रखना जरूरी
1. वैश्विक तनाव लंबे समय तक बने रहना
2. कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर से ऊपर रहना, इससे लागत बढ़ती जा रही है
3. विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहने से बड़ी कंपनियों के शेयरों पर दबाव
4. एक के बाद एक भू-राजनीतिक घटनाएं

अब शेयरों का चयन इन पैमानों पर हो
- कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही हो
- जिन कंपनियों पर कर्ज का बोझ कम हो
- जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत, टिकाऊ हो
- जिन कंपनियों का मैनेजमेंट भरोसेमंद हो

कमजोर कंपनियों के शेयर ऊंचे वैल्युएशन पर होल्ड करना रिस्की हो सकता है।

विस्तार में सक्षम कंपनियां चलेंगी

जनवरी-मार्च में इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की आय उम्मीद से बेहतर रही। राइट होराइजन पीएमएस के संस्थापक और फंड मैनेजर अनिल रेगो का मानना है कि आगे बाजार उन्हीं कंपनियों को अहमियत देगा, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, कारोबार बढ़ाने की क्षमता है और मुनाफे की ठोस उम्मीद है।

भास्कर नॉलेज

क्यों मजबूत दिख रहे हैं स्मॉल-मिडकैप शेयर?

निवेशकों की सोच बदल रही है। एसबीआई सिक्युरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च हेड सनी अग्रवाल के मुताबिक, बड़ी कंपनियों के शेयरों से अब 'अल्फा' यानी अतिरिक्त रिटर्न निकालना मुश्किल होता जा रहा है। निफ्टी में बैंकिंग और आईटी कंपनियों का दबदबा ज्यादा है, जिससे ग्रोथ सीमित दिख रही है। इसके मुकाबले मिड और स्मॉल कंपनियों में कई 'फ्यूचर विनर्स' मौजूद हैं, जो 15-20% से ज्यादा ग्रोथ दिखा रही हैं।

कई इंडेक्स तो युद्ध से पहले के स्तर से भी ऊपरः अमेरिका-ईरान तनाव से बाजार गिरा जरूर, लेकिन मिड और स्मॉलकैप शेयरों ने तेजी से वापसी भी की। कई इंडेक्स तो युद्ध से पहले के स्तर से भी ऊपर निकल गए। इसके दो बड़े कारण बताए जा रहे हैंः
1. गिरते बाजार में भी निवेशकों की लगातार मजबूत भागीदारी।
2. मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों की उम्मीद से भी बेहतर कमाई।

दमदार बैंकिंग • लगातार चौथे साल प्रॉफिट

सरकारी बैंकों का मुनाफा पहली बार ₹2 लाख करोड़

12 सरकारी बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ 10.6%, लोन वृद्धि 15.7% रही

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

देश के 12 सरकारी बैंकों (पीएसबी) ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड ₹1.98 लाख करोड़ मुनाफा कमाया। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह लगातार चौथा साल है जब सार्वजनिक बैंकों ने मुनाफे की राह पर कदम रखा है।

सरकारी बैंकों के फंसे कर्ज (एनपीए) भी ऐतिहासिक निम्नतम स्तर 1.93% पर आ गए हैं। यह सुधार उन दिनों की तुलना में उल्लेखनीय है जब वित्त वर्ष 2017-18 में सकल एनपीए 14.58% और शुद्ध एनपीए 7.97% के ऊंचे स्तर पर था। फंसे कर्जों ने बैंकिंग सिस्टम को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। बीते वित्त वर्ष पीएसबी का कुल कारोबार ₹283.3 लाख करोड़ हो गया, जो 2024-25 में ₹251.7 लाख करोड़ था। सरकारी बैंकों में कुल जमा राशि 10.6% बढ़कर ₹156.3 लाख करोड़ हो गई, जबकि लोन पोर्टफोलियो 15.7% बढ़कर ₹127 लाख करोड़ हो गया।

सरकारी बैंकों का मुनाफा सिर्फ 4 साल में तीन गुना

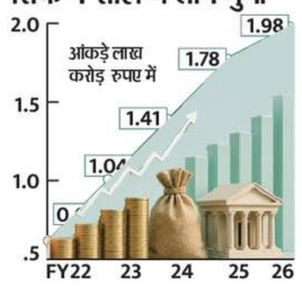

रिटेल, कृषि, छोटे उद्योगों को लोन 18% तक बढ़ा

वित्त वर्ष 2026 के दौरान लोन ग्रोथ रिटेल, कृषि और छोटे-मझोले उद्योग (एसएसएमई), तीनों ही प्रमुख क्षेत्रों में समान रूप से दर्ज की गई। रिटेल लोन में 18.1%, कृषि लोन में 15.5% और एमएसएमई लोन में 18.2% की बढ़ोतरी हुई। यह आंकड़े उद्यमिता, वित्तीय समावेश और आर्थिक विकास में सरकारी बैंकों की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हैं। वित्त वर्ष 2026 में बट्टे खाते में डाले गए खातों सहित कुल वसूली 86,971 करोड़ रही।

भास्कर नॉलेज

एआई साइबर हमला कैसे पकड़ में आया?

श्वेता कुमारी | नई दिल्ली

गूगल ने दुनिया में पहली बार एआई की मदद से तैयार किया गया साइबर हमला पकड़ा है। हैकर्स ने सॉफ्टवेयर की अज्ञात कमी ढूंढने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल किया। गूगल की 'थ्रेट इंटेलिजेंस टीम' के अनुसार, हैकर्स ने सॉफ्टवेयर की अज्ञात खामी खोजने और उसका कोड तैयार करने में एआई टूल की मदद ली। हालांकि गूगल ने समय रहते इसकी पहचान करके फिलहाल बड़े खतरे को टाल दिया है।

सॉफ्टवेयर की इस नई कमजोरी और एआई के खतरे को इन सवालों से समझें...

Q 'जीरो-डे' हमला क्या है, क्यों खतरनाक?
इसका मतलब सॉफ्टवेयर की ऐसी अज्ञात कमी है, जिसकी जानकारी कंपनी को नहीं होती। सुधार के लिए 'जीरो' दिन का समय मिलने की वजह से इसे सबसे खतरनाक माना जाता है।

Q 'एक्सप्लॉइट' क्या है, इस्तेमाल कैसे?
यह डिजिटल कोड सॉफ्टवेयर की कमजोरी का फायदा उठाकर सिस्टम में घुसता है। हैकर्स इसका इस्तेमाल डेटा चोरी या जासूसी के लिए करते हैं।

Q क्या इस हमले के पीछे कोई खास देश है?
गूगल ने चीन और उत्तर कोरिया के हैकर ग्रुप्स पर शक जताया है। ये समूह अब बड़े हमलों के लिए एआई टेक्नोलॉजी तेजी से अपना रहे हैं।

Q सुरक्षा के लिए कंपनियां क्या कर रही हैं?
एंथ्रोपिक के बाद ओपनएआई ने 'डेब्रेक' मॉडल पेश किया है। यह एआई मॉडल खास तौर पर साइबर हमले समय पर पहचानने और उन्हें रोकने के लिए ही बनाया गया है।

Q सुरक्षा के लिए क्या बदलाव करने होंगे?
कंपनियों को सॉफ्टवेयर की खामी मिलते ही 'पैच' जारी करना होगा। पैच एक डिजिटल सुरक्षा कवच है जो सॉफ्टवेयर की कमजोरियां ठीक करता है।

Q एआई से बने वायरस से आप कैसे बचें?
एआई से बने वायरस को पकड़ना अब बहुत मुश्किल होगा। अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।

Q क्या एआई से साइबर हमले और बढ़ेंगे?
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह तो बस शुरुआत है। अब एआई और हैकर्स मिलकर पहले से ज्यादा तेज और सटीक हमले करेंगे, जिनसे बचना चुनौती होगी।

ऊर्जा संकट का असर...

अमेरिका में महंगाई ने तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड

न्यूयॉर्क| अमेरिका में बीते महीने महंगाई दर बढ़कर 3.8% हो गई है। यह पिछले लगभग तीन वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी में यह दर 2.4% थी, जो मार्च में बढ़कर 3.3% और अब अप्रैल में 3.8% तक पहुंच गई है। इस उछाल का सबसे बड़ा कारण ईरान युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा संकट है।

युद्ध की वजह से 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होने से दुनिया की तेल आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे अमेरिका में तेल की कीमतों में 70% तक की वृद्धि देखी गई है।

अप्रैल में ऊर्जा की कीमतों में 3.8% की मासिक वृद्धि हुई। युद्ध शुरू होने के बाद से पेट्रोल की औसत कीमत 1.52 डॉलर बढ़कर 4.50 डॉलर प्रति गैलन हो गई है। खाने-पीने की चीजों में 0.5% और मकान किराए में 0.6% की बढ़ोतरी हुई है। हवाई किराए और कपड़ों के दाम भी बढ़े हैं। इससे अमेरिकी नागरिकों की क्रय शक्ति घट रही है।

जेगर-लेकॉल्ट्रे की एटमॉस घड़ीः यह हवा की ऊर्जा से चलती है, सिस्टम ऐसा कि 3,821 साल तक एकदम सटीक समय बताएगी

मिलान| लग्जरी कंपनी जेगर-लेकॉल्ट्रे ने मिलान डिजाइन वीक में दो नई एटमॉस घड़ियां पेश कीं। इन्हें अमर घड़ी कहा जाता है। इसे न तो बैटरी की जरूरत होती है और न ही चाबी भरनी पड़ती है। यह तकनीक 1928 में विकसित की गई थी। यह हवा के तापमान में होने वाले मामूली बदलाव से ऊर्जा लेती है। तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर इस घड़ी को लगभग 48 घंटे तक चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा दे देता है। दावा है कि यह इस सीरीज की सबसे जटिल और सुंदर घड़ी है। इसका मून फेज डिस्प्ले इतना सटीक है कि 3,821 वर्षों में सिर्फ एक दिन की चूक संभव है।

ये बेशकीमती घड़ी ब्रह्मांड की रफ्तार भी दिखाती है

यह घड़ी ब्रह्मांड की रफ्तार भी दिखाती है। इसमें एक छोटी सी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। साथ ही यह सूर्य के चक्कर भी लगाती है। इसमें चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर अपनी स्थिति बदलते हुए दिखता है।

बुलियन • अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम स्थिर

रुपए की कमजोरी से सोने में उछाल, 1.51 लाख पार

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी का असर घरेलू सराफा बाजार पर भी पड़ा। इससे 24 कैरेट सोने के दाम 1,270 रुपए बढ़कर 1,51,632 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। जेवराती (22 कैरेट) सोना भी 1,163 रुपए चढ़ा और इसकी कीमत 1,38,895 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। चांदी 8,667 रुपए महंगी होकर 2,64,867 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। विशेषज्ञों के मुताबिक रुपए डॉलर के मुकाबले 40 पैसे कमजोर होकर नए रिकॉर्ड स्तर 95.68 पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें स्थिर होने के बावजूद घरेलू बाजार में यह उछाल केवल रुपए की ऐतिहासिक कमजोरी और आयात लागत बढ़ने की वजह से देखा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स 98 का स्तर पार कर जाने से अन्य मुद्राओं पर दबाव बढ़ा है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 4,672 डॉलर प्रति औंस के स्तर के आसपास स्थिर रहा। एलकेपी सिक्युरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी एंड करेंसी) के मुताबिक निकट भविष्य में सोने के ₹1.50-1.55 लाख प्रति 10 ग्राम के दायरे रहने की उम्मीद है।

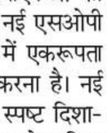

सोना अब रिकॉर्ड स्तर से 13%, चांदी 30% नीचे

इस साल 29 जनवरी को 24 कैरेट सोना 1,75,340 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर था। चांदी 3,79,988 रुपए किलो के रिकॉर्ड स्तर पर थी। फिलहाल देशभर में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर से ₹23,708 (13.5%) प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,15,121 (30.3%) प्रति किलो नीचे है।

पिन कोड की जगह स्पेस को तरजीह

दिल्लीः लग्जरी घरों के दाम 32% बढ़े

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

दक्षिण दिल्ली के लग्जरी हाउसिंग मार्केट में घरों के दाम एक साल में 32% तक बढ़ गए हैं। गोल्डन ग्रोथ फंड की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की जनवरी-मार्च तिमाही में कैटेगरी-बी की कॉलोनियों ने ए-कैटेगरी को पीछे छोड़ दिया है। कैटेगरी-बी में कीमतें 23-32% तक बढ़ीं, जबकि ए-कैटेगरी में उछाल 14-22% तक रहा। आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद रईस भारतीय और एनआरआई यहां भारी निवेश कर रहे हैं। यहां 42 कॉलोनियों के 18,500 प्लॉट्स की रिडेवलपमेंट क्षमता 6.5 लाख करोड़ रुपए की है। ए-कैटेगरी में 6,000 वर्ग फीट के फ्लोर 25 से 55 करोड़ और 2,500 वर्ग फीट के फ्लोर 14 से 25 करोड़ रुपए के हैं। कैटेगरी-बी में 3,200 वर्ग फीट के फ्लोर का दाम 12.5 से बढ़कर 16.5 करोड़ और 2,500 वर्ग फीट के फ्लोर 9 से 12.5 करोड़ रुपए के हो गए हैं। वसंत विहार, गोल्फ लिंक्स, जीके और डिफेंस कॉलोनी जैसे इलाकों में भारी डिमांड है। खरीदार अब पुराने पिन कोड के बजाय बड़े स्पेस और रिडेवलपमेंट वैल्यू को तरजीह दे रहे हैं।

प्रयास • जहां बेचना है, उत्पादन, सप्लाई भी उसी देश में होः केपीएमजी

कंज्यूमर सेक्टरः सिर्फ कीमतें नहीं, अब समय पर डिलीवरी भी बड़ी चुनौती बन रही

भास्कर न्यूज | मुंबई

पश्चिम एशिया संकट से भारतीय कंज्यूमर कंपनियां आशंकित हैं। उन्हें सिर्फ बढ़ती लागत ही नहीं, बल्कि समय पर डिलीवरी और स्टॉक बनाए रखने की भी चिंता सताने लगी है।

ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म केपीएमजी की 'कंज्यूमर एंड रिटेल सीईओ आउटलुक' रिपोर्ट के मुताबिक, 52% रिटेल और कंज्यूमर कंपनियों के सीईओ ने सप्लाई चेन को सबसे बड़ी फौरी चुनौती बताया है। यह आंकड़ा 2023 के 15% और 2024 के 30% से काफी ज्यादा है।

बढ़ते दबाव का असर रिटेल और ई-कॉमर्स सेक्टर में भी दिख सकता है। सप्लाई चेन की बाधा बढ़ने से सामान की उपलब्धता और डिलीवरी, प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में कंपनियां जहां सामान बेचना हो, उसी देश में उत्पादन और सप्लाई के प्रयास में हैं।

सप्लाई ज्यादा भरोसेमंद बनाने पर फोकस

रिपोर्ट के मुताबिक हंता वायरस, भू-राजनीतिक तनाव, मुश्किल मौसम और बढ़ती ट्रेड बाधाओं ने कंपनियों को सप्लाई और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी रणनीतियों पर नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया है। कंपनियां अब सिर्फ कम लागत वाले मॉडल पर निर्भर रहने की बजाय सप्लाई को ज्यादा भरोसेमंद बनाने पर जोर दे रही हैं।

कंज्यूमर कंपनियों की नई रणनीति में अब इन चार चीजें पर है बढ़ रहा फोकस...

1. **नियर शोरिंगः** उत्पादन या सप्लाई का काम दूर देशों की बजाय नजदीकी देशों में शिफ्ट करना, ताकि डिलीवरी तेज हो और जोखिम कम रहे।
2. **फ्रेंड शोरिंगः** सप्लाई चेन और उत्पादन धीरे-धीरे ऐसे देशों में बढ़ाना, जिनसे राजनीतिक और कारोबारी रिश्ते बेहतर और भरोसेमंद हों।
3. **लोकल-फॉर-लोकलः** जिस देश में सामान बेचना है, उसका उत्पादन और सप्लाई उसी देश में सुनिश्चित करना।
4. **एआई की मदद लेनाः** कंपनियां फोरकास्टिंग, लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सुधारने के लिए एआई में निवेश बढ़ा रही हैं।

नई एसओपी जारी...

ईपीएफओ के समान लाभ निजी ट्रस्टों में भी

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने निजी या छूट प्राप्त प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट्स के लिए नए नियमों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है। अब प्राइवेट ट्रस्टों को अपने कर्मचारियों को कम से कम ईपीएफओ के बराबर या उससे बेहतर लाभ देना होगा। नियमों का पालन न करने पर छूट का दर्जा रद्द किया जा सकता है। देशभर में 1,250 से अधिक निजी ट्रस्ट इस दायरे में आते हैं, जो 32 लाख कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करते हैं। इन ट्रस्टों के पास करीब ₹3.5 लाख करोड़ जमा हैं। ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा मंजूर नई एसओपी का उद्देश्य निजी ट्रस्टों के संचालन में एकरूपता लाना और निगरानी प्रणाली मजबूत करना है। नई एसओपी में ब्याज दरों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं। अब निजी ट्रस्ट मनमाने ढंग से अधिक ब्याज नहीं दे सकेंगे। अधिकतम सीमा ईपीएफओ की ब्याज दर से 2 पर्सेंटेज पॉइंट ऊपर तय की गई है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में पहले 30-34% ब्याज दिए जाने के मामले सामने आए थे।

बिजनेस ब्रीफ

भारत की ग्रोथ अब 6% पर आ सकती हैः मूडीज

नई दिल्ली| ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2026 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 6% कर दिया है। इसके लिए ईंधन की ऊंची कीमतें और वैश्विक अनिश्चितताओं का हवाला दिया गया है। मूडीज के मुताबिक, कच्चे तेल के महंगे आयात से लागत बढ़ सकती है।

एआई की दौड़ में पिछड़ रहा मस्क का 'ग्रोक'

न्यूयॉर्क| एक्सएआई का मॉडल ग्रोक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले पिछड़ रहा है। अप्रैल में इसके डाउनलोड घटकर 83 लाख रह गए, जबकि जनवरी में यह आंकड़ा 2 करोड़ से ऊपर था। एक सर्वे में सिर्फ 0.174% यूजर्स ने ग्रोक के लिए पेमेंट की बात कही, जबकि चैटजीपीटी के लिए यह आंकड़ा 6% से ज्यादा रहा।

इंस्टाग्राम पर अब एआई करेगा शॉपिंग, पोस्ट

न्यूयॉर्क| मेटा प्लेटफॉर्म्स जल्द इंस्टाग्राम में एआई एजेंट्स जोड़ सकती है। यह यूजर्स की तरफ से पोस्ट करने, खरीदारी करने और दूसरे डिजिटल काम संभालने में मदद करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एआई आधारित ऑटोमेशन फीचर्स पर तेजी से काम कर रही है।

कैंसर थेरेपी पर खर्च से डॉ. रेड्डीज का लाभ 86% घटा

मुंबई| जनवरी-मार्च तिमाही में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज का मुनाफा 86% घटकर ₹221 करोड़ रह गया। यह बाजार के अनुमान से कम है। कैंसर थेरेपी बिजनेस से जुड़े इम्पेयरमेंट चार्जेज का असर मुनाफे पर हुआ। हालांकि कंपनी ने कहा कि उसके मुख्य बिजनेस की ग्रोथ बनी हुई है, पर एकमुश्त खर्च ने प्रदर्शन को प्रभावित किया।

TheEconomist रोबोटैक्सी और फूड-डिलीवरी ड्रोन तेजी से सड़कों पर कब्जा कर रहे, इस ट्रेंड का विरोध बढ़ रहा

चीन में नया संघर्ष... रोबोट, ड्रोन से 2.2 करोड़ ड्राइवर खतरे में

बीजिंग| चीन एआई और ऑटोमेशन के दुष्प्रभाव से जूझ रहा है। बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का खतरा मंडरा रहा है। किंगदाओ जैसे शहर ऑटोमेशन और इंसानी संघर्ष की लैब बन गए हैं। महज एक साल पहले इस शहर में ऑटोनॉमस व्हीकल गिने-चुने थे। आज यह दुनिया के सबसे उन्नत शहरों में है। नियोलिक्स कंपनी ने यहां 1,200 मानवरहित डिलीवरी वैन उतारी है। दिसंबर तक इसे बढ़ाकर 4,000 करने का लक्ष्य है। यह शहर उस बदलाव का प्रतीक है, जहां रोबोटैक्सी और फूड-डिलीवरी ड्रोन तेजी से सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं।

गोल्डमैन सैक्स के आंकड़ों के अनुसार 2025 के अंत तक चीन की सड़कों पर 33,000 शॉर्ट-रेंज डिलीवरी वाहन थे। 2026 के अंत तक मानवरहित कैब 14,000 होने की उम्मीद है। 5 साल में, चीनी शहरों में 7 लाख रोबोटैक्सी होंगी। यह कुल राइड-हेलिंग सेवाओं का 12% होगी।

दिग्गज एप मीटुआन का अनुमान है कि वह चीन की 10% क्विक फूड डिलीवरी ड्रोन के जरिए कर सकता है। पिछले वर्ष 6 हजार करोड़ डिलीवरी हुई थीं। इससे ड्राइवरों की रोजी-रोटी छिनने लगी है। ऐसे में चीनी नेतृत्व ने रणनीति बदली है। सरकार ने मार्च में जारी पंचवर्षीय आर्थिक योजना में स्पष्ट कहा कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के जोखिम को रोकना होगा। अप्रैल में जारी एक मसौदा दस्तावेज में डेवलपर्स को सख्त हिदायत दी गई कि वे रोजगार खत्म करने के इरादे से एआई का इस्तेमाल न करें। रिसर्च फर्म टॉम ननलिस्ट के मुताबिक, चीनी एआई रेगुलेशन में रोजगार बचाने के लिए किया गया अनुरोध दुर्लभ है। इससे पहले नीतिगत स्तर पर मानव श्रम के संरक्षण का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। असली खतरा उन 2.2 करोड़ ड्राइवरों को है जो सवारियां ढोते हैं या ग्राहकों को पार्सल पहुंचाते हैं। तनाव कम करने के लिए मीटुआन जैसी कंपनियां ड्राइवरों को नई भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित कर रही हैं। शंघाई में ड्राइवरों को ड्रोन डिलीवरी संचालित करने, खाना लोड करने और कमांड सेंटर से निगरानी करने की ट्रेनिंग दी जा रही है।

वुहान में ऑटोमेशन कारों से जाम बढ़ रहा, ड्राइवर संगठित हो रहे

चीन में ऑटोमेशन की राह आसान भी नहीं है। वुहान जैसे शहरों में, जहां बायडू लगभग 1,000 रोबोटैक्सी चला रहा है, तकनीकी खामियां ट्रैफिक जाम कर रही हैं। मार्च में दर्जनों टैक्सियां अचानक सड़क पर 'फ्रीज' हो गईं, जिससे यातायात ठप हो गया। इसके बाद सरकार ने रोबोटैक्सी के नए लाइसेंस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, ड्राइवर अब संगठित होकर विरोध कर रहे हैं। 2024 में वुहान में हुए प्रदर्शनों के बाद, अधिकारियों ने बायडू को अपने रोबोटैक्सी के आंकड़े सार्वजनिक करने से मना कर दिया।

सुधार • अब संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी

सटीक आंकड़ों में देरी, जीडीपी के डेटा मई की जगह 7 जून को

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश की आर्थिक विकास दर के आंकड़े कुछ दिन की देरी से जारी होंगे। केंद्र ने सालाना और चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपीइ) के आंकड़े जारी करने की तारीख मई के आखिरी कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम डेटा ज्यादा सटीक रखने के लिए उठाया गया है।

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक, कई कंपनियों के आंकड़े समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते। मार्च से जुड़े केंद्र के खर्च, टैक्स, सब्सिडी और ब्याज भुगतान जैसे अहम वित्तीय आंकड़े भी करीब दो महीने बाद अंतिम रूप में उपलब्ध होते हैं। ऐसे में पहले जारी होने वाले जीडीपी अनुमानों में बाद में संशोधन की जरूरत पड़ सकती थी।

नया शेड्यूल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूपः केंद्र

केंद्र ने कहा कि नया शेड्यूल डेटा की गुणवत्ता, व्यापकता और मजबूती के उद्देश्य से तय किया गया है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। 2025-26 के प्रोविजनल जीडीपी और जनवरी-मार्च के आंकड़े 7 जून को जारी किए जाएंगे।

कर्म करना बहुत अच्छा है, पर यह विचारों से आता है, इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो।

– स्वामी विवेकानंद

परीक्षा की शुचिता

देश भर में हर साल लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मगर उनकी उम्मीदें तब धुंधली पड़ जाती हैं, जब परीक्षा में अनियमितता की बातें सामने आती हैं या फिर पर्चाफोड़ की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इस बार भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी-2026' में पर्चाफोड़ के गंभीर आरोप लगे हैं, जिस कारण राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने तीन मई को आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी गई है। सवाल है कि इस तरह की प्रवेश परीक्षाओं में बार-बार गड़बड़ियों के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? एनटीए का दावा है कि प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसे संबंधित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में पूरी गोपनीयता बरती जाती है और जरूरी सुरक्षा मानदंडों का भी कड़ाई से पालन किया जाता है, फिर क्या वजह है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र चुनिंदा विद्यार्थियों तक पहुंच जाता है! आखिर एनटीए और जांच एजंसियां उस सिरे को क्यों नहीं ढूंढ पा रही हैं, जिसकी वजह से इस तरह की गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है, जब एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। वर्ष 2024 में नीट की परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि उन्हें दूसरी भाषा के प्रश्नपत्र दिए गए। इसके बाद एनटीए की ओर से क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रभावित परीक्षार्थियों को दिए गए कृपांक को लेकर भी गंभीर सवाल उठे थे। इससे पहले वर्ष 2021 में भी कुछ छात्रों को गलत प्रश्नपत्र दिए जाने और कई केंद्रों पर परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतों से विवाद हुआ था। सरकार ने वर्ष 2018 में एनटीए की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करना है, जिनमें नीट, जेईई, यूजीसी और नेट भी शामिल हैं।

दरअसल, प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष बनाना एनटीए की बुनियादी प्राथमिकता है। मगर, इनमें जिस तरह से एक के बाद एक विसंगतियां सामने आ रही हैं, उससे इस एजंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नीट यूजी 2026 परीक्षा में करीब 23 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। एनटीए का दावा है कि इस परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने में पूरी गोपनीयता बरती गई और इन्हें 'जीपीएस-ट्रैकिंग' वाले वाहनों में ले जाया गया था। परीक्षा केंद्रों की निगरानी एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से एआइ-सहायता प्राप्त सीसीटीवी के माध्यम से की गई थी। सुरक्षा के इन तमाम प्रबंधों के बावजूद अगर प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही कुछ विद्यार्थियों तक पहुंच जाता है, तो यह वास्तव में बहुत ही गंभीर मसला है। जाहिर है कि परीक्षा के आयोजन से संबंधित संस्था और अन्य संगठनों की पर्चाफोड़ माफिया से मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं हो सकता। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि विद्यार्थी इन परीक्षाओं के लिए कितनी मेहनत करते हैं, महंगी कोचिंग के लिए कई परिवार तो अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, तो कोई बैंक से कर्ज लेता है। इसलिए जरूरी है कि प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

नशे के विरुद्ध

शांतिप्रिय राज्य की छवि वाले हिमाचल प्रदेश में अब युवाओं के बीच नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। नशीले पदार्थों का जाल न केवल शहरी, बल्कि ग्रामीण इलाकों तक फैल गया है। एक खास तरह का नशीला पदार्थ, जिसे स्थानीय भाषा में चिट्टा कहा जाता है, उसकी लत युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रही है। दरअसल, जम्मू और पंजाब की सीमाओं से सटे होने के कारण हिमाचल में नशीले पदार्थों की तस्करी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। जांच एजंसियों के तमाम दावों के बावजूद नशे के इस तंत्र पर रोक नहीं लग पा रही है। अब प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए सरकारी नौकरी के लिए युवाओं का 'एंटी चिट्टा टेस्ट' अनिवार्य कर दिया है। साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की भी हर वर्ष ऐसी ही जांच कराई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस कदम से युवाओं को नशे से दूर रखने में कुछ हद तक मदद मिल सकती है।

हिमाचल सरकार ने एक जून से शिक्षा संस्थानों में चिट्टा के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला भी किया गया है। मगर यह तभी सार्थक होगा, जब अभिभावकों को भी इससे जोड़ा जाएगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और घरेलू कार्यों की व्यस्तता की वजह से माता-पिता अपने बच्चों पर ज्यादा नहीं दे पाते हैं और उन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी की भी कम ही जानकारी होती है। ऐसे में किशोरों और युवाओं के साथ-साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने की जरूरत है, ताकि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख सकें और उन्हें नशे के दलदल में उतरने से रोक सकें। इसके अलावा राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान से जुड़ने वाले अधिकारियों की वार्षिक रपट में भी इस कार्य का उल्लेख करने की बात कही है। यह वास्तव में एक व्यावहारिक पहल है। इसमें दोराय नहीं कि राज्य सरकार सतही उपायों के बजाय धरातल पर काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसे राज्य में शिक्षित युवाओं को रोजगार देने की दिशा में भी व्यापक स्तर पर कदम उठाने होंगे, क्योंकि नशे का सेवन करने वालों में छात्रों और बेरोजगार युवाओं की तादाद अधिक है।

जंगलों में आग का बढ़ता जोखिम

देश भर में जंगलों में आग लगने की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन और मानवीय लापरवाही के कारण यह समस्या अब जटिल होती जा रही है।

ज्ञान चंद पाटनी

देश भर में जंगलों में आग लगना अब एक सामान्य घटना बन चुकी है। इससे न केवल प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, बल्कि वन्य जीवों, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रबंधकीय कमियों और मानवीय लापरवाही के कारण यह समस्या जटिल होती जा रही है। हालात को देखते हुए वनों को बचाने के लिए अब सजगता के साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इंडिया स्टेट आफ फारेस्ट रपट (आइएसएफआर)-2023 के अनुसार, देश में कुल वन और वृक्ष आवरण यहां के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 फीसद है। 'स्टेट आफ वाइल्ड फायर्स' की रपट से पता चलता है कि जंगलों में वर्ष 2000 से 2019 के बीच आग लगने की घटनाएं दस गुना तक बढ़ी हैं।

वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश जंगल में आग की घटनाओं के मामले में सबसे अधिक प्रभावित रहा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब भी इससे काफी प्रभावित हुए। हिमालयी क्षेत्रों में चीड़ के विशाल वन सुईनुमा सूखी पत्तियों के कारण शीघ्र ही आग पकड़ लेते हैं। ये पत्तियां सूखने के बाद बेहद ज्वलनशील हो जाती हैं। इनमें तेल की मात्रा अधिक होती है, जो आग में घी का काम करती हैं। मध्य भारत विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़ीशा और महाराष्ट्र में साल और बांस के जंगल मुख्य रूप से शुष्क मौसम (फरवरी से जून) में आग की चपेट में आ जाते हैं। यह हर वर्ष की समस्या है। यहां सबसे भीषण आग अप्रैल और मई के महीनों में लगती है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के वन भी आग से अछूते नहीं हैं। इसी तरह असम, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के वन भी संवेदनशील हैं।

इन दिनों देश भर में भीषण गर्मी और लू के कारण लोग बेहाल हैं। वहीं जंगल भी प्रभावित हुए हैं। देश के एक दर्जन राज्यों में कई जंगल आग की चपेट में हैं। उपग्रहों से मिले आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगने के मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड और तमिलनाडु से जंगलों में आग लगने की खबरें आ रही हैं। तमिलनाडु में नीलगिरि जिले तथा उससे लगे मुदुमलई, कोयंबटूर और इरोड के जंगल आग से जूझ रहे हैं। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वायुसेना की मदद की जरूरत पड़ गई। असम और मणिपुर के जंगल भी आग से धधक रहे हैं। पूर्वोत्तर के जंगलों में आग लगने की अधिक आशंका रहती है।

वर्ष 2025 की पर्यावरण लेखांकन रपट और दूसरी रपटों के अनुसार, भारत में जंगलों में आग गंभीर समस्या बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2024 से जून 2025 की अवधि के दौरान आग लगने के अनेक मामले सामने आए। सुओमी नेशनल पोलर-आर्बिटिंग पार्टनरशिप (एसएनपीपी) उपग्रह पर लगे वीआइआइआरएस सेंसर के जरिए ये आंकड़े एकत्र किए गए थे। आग लगने की घटनाओं के कारण वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, हाल के अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2024-25 के दौरान जंगलों की आग से भारत में करीब डेढ़ करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। वैश्विक स्तर पर भी

वर्ष 2024 में कनाडा और अमेरिका में लाखों वर्गकिलोमीटर में फैले जंगल राख हो गए। भारत में जंगल में आग लगने के नब्बे फीसद से ज्यादा मामले मानवजनित हैं। किसान फसल अवशेष जला कर खेत तैयार करते हैं, जिसकी चिनगारी जंगल तक पहुंच जाती है। महुआ, तेंदू पत्ता और जड़ी-बूटियों की

> वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश जंगल में आग की घटनाओं के मामले में सबसे अधिक प्रभावित रहा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब भी इससे काफी प्रभावित हुए। हिमालयी क्षेत्रों में चीड़ के विशाल वन सूखी पत्तियों के कारण शीघ्र ही आग पकड़ लेते हैं। ये पत्तियां सूखने के बाद बेहद ज्वलनशील हो जाती हैं। मध्य भारत विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़ीशा और महाराष्ट्र में साल और बांस के जंगल मुख्य रूप से शुष्क मौसम में आग की चपेट में आ जाते हैं। यह हर वर्ष की समस्या है। यहां सबसे भीषण आग अप्रैल और मई के महीनों में लगती है।

अवैध कटाई के बाद आग लगा कर साक्ष्य मिटाने की प्रवृत्ति भी आम है। पर्यटक और चरवाहे जलती माचिस की तीली, बीड़ी या सिगरेट फेंक देते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों या शिकार के लिए भी आग लगाने का प्रचलन है, जो अनियंत्रित हो जाती है। जंगलों में आग की बढ़ती घटनाएं जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ी हैं। गर्मियों का मौसम लंबा हो गया है, वर्षा अनियमित है और तापमान रेकार्ड स्तर पर पहुंच रहा है। जलवायु परिवर्तन ने शुष्क मौसम को तीन महीने लंबा कर दिया है। कम आर्द्रता, तेज हवाएं और उच्च तापमान से आग भड़कती है। चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे पेड़ों की पत्तियों से भी आग बेकाबू होती है।

जंगल की आग से जैव विविधता नष्ट होती है। हजारों पेड़-पौधे जल जाते हैं। पशु-पक्षी मारे जाते हैं। मिट्टी का कटाव बढ़ने से जलाशय दूषित होते हैं और बाढ़ का खतरा पैदा होता है। कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जो वैश्विक ताप को तेज करता है। नए वैश्विक अध्ययनों से सामने आया है कि जंगलों की आग हर साल औसतन 14.3 करोड़ टन जहरीले प्रदूषक छोड़ रही है। इससे गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की चुनौती और भी जटिल हो रही है। 'एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलाजी' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, जंगलों की आग पहले के अनुमानों से कहीं ज्यादा मात्रा में हानिकारक गैसें और कार्बनिक यौगिक वातावरण में छोड़ रही है। इस आग से निकलने वाले धुएं में सिर्फ कार्बन डाइआक्साइड ही नहीं, बल्कि कई ऐसे कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, जो ज्यादा खतरनाक हैं।

आग से पर्यावरण तो प्रभावित होता ही है, भारी आर्थिक नुकसान भी होता है। वनवासी ज्यादा प्रभावित होते हैं। धुआं फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर और हृदय रोग बढ़ाता है। आग पर काबू पाने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी भी नजर आती है, जिससे आग फैल जाती है। एक ओर वन विभाग में कर्मचारियों की कमी है, तो दूसरी ओर पुराने उपकरणों और समन्वय के अभाव की वजह से आग को नियंत्रित मुश्किल हो जाता है। बजट की कमी से अग्निशमन यंत्र, वाहन और प्रशिक्षण का कार्य प्रभावित होता है। 'फायर लाइंस' बनाने पर भी खास ध्यान नहीं दिया जा रहा। गौरतलब है कि इसे बनाने के लिए सूखी वनस्पतियां और घास जैसी सामग्री हटाई जाती है। खाइयां और रास्ते भी बनाए जाते हैं। इससे आग का फैलाव रोकने में काफी मदद मिलती है।

आग के जोखिम को बढ़ाने वाली कई गतिविधियां लोगों की रोजी-रोटी और पुरानी प्रथाओं से भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए बिना उपयुक्त विकल्पों के उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। इस पक्ष पर खास ध्यान देने की जरूरत है। जंगल की आग को प्रबंधित करने के लिए ठोस योजना जरूरी है। दूसरे देशों में जंगल की आग रोकने और बचाव के उपाय बहुआयामी हैं। वहां तकनीक, समुदाय भागीदारी और नीतिगत प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने आग की तीव्रता से निपटने के लिए नवीन रणनीतियां अपनाई हैं। भारत को भी इन देशों से सीख लेकर वनों को आग से बचाने के लिए मजबूत योजना बनानी होगी। बेहतर प्रबंधन के लिए बजट बढ़ाने के साथ कृत्रिम मेधा और ड्रोन तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। वनों से जुड़े समुदायों को साथ लेकर इस योजना पर काम करना होगा। मानदेय देकर उनका उत्साह बढ़ाया जा सकता है। इंसानी गतिविधियां और लापरवाही जंगल की आग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। इसलिए लोगों को जागरूक करने पर ध्यान देने की जरूरत है। वनों को आग से बचाना हम सभी के हित में है।

दृष्टिकोण का दायरा

शिशिर शुक्ला

जीवन सतत रूप से गतिशील है। गतिशीलता की इस यात्रा में यह भांति-भांति के रूप धारण करता है। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारे अंतर्मन और जीवन के प्रतिबिंब को निर्धारित करता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के दौरान लगभग समान परिस्थितियों का सामना करता है। ये परिस्थितियां हैं- सफलता, विफलता, सुख-दुख, आपदा संघर्ष और अवसर। मगर इन परिस्थितियों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया भिन्न होती है। यह भिन्नता दरअसल उनके दृष्टिकोण के अंतर से उत्पन्न होती है। दृष्टिकोण वह मानसिक आईना है, जिसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के माध्यम से ही हम संसार को देखते और समझते हैं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मनुष्य के जीवन का स्वरूप परिस्थितियों की अपेक्षा दृष्टिकोण से अधिक प्रभावित होता है।

दृष्टिकोण केवल विचारों का संग्रह ही नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुभवों, संस्कारों, शिक्षा और जीवन दृष्टि का समन्वित परिणाम होता है। यह वह नींव है, जिस पर हम अपने निर्णयों, कर्मों एवं भविष्य की इमारत खड़ी करते हैं। सकारात्मक, व्यापक और उदार नजरिए से युक्त व्यक्ति कठिन व विषम परिस्थितियों में भी अनुकूल अवसर तलाश लेता है। इसके विपरीत अगर दृष्टिकोण संकीर्ण, नकारात्मक और निराशावादी है, तो ऐसा व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में भी असंतोष और विफलता से ही घिरा रहता है।

एक सरल से उदाहरण की सहायता से जीवन में दृष्टिकोण की महत्ता को समझा जा सकता है। पानी से आधे भरे हुए बर्तन को दो रूप में देखा जा सकता है- सकारात्मक नजरिए से आधा भरा एवं नकारात्मक नजरिए से आधा खाली। यही अंतर जीवन के हर क्षेत्र और हर पहलू में दिखता है। दृष्टिकोण ही व्यक्ति की सफलता और विफलता का प्रमुख निर्धारक होता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति आशावादी और दृढ़ दृष्टिकोण रखता है, वह कठिनाइयों से लेशमात्र भी विचलित नहीं होता, बल्कि उन्हें सीखने तथा स्वयं को निखारने का अवसर मानकर आगे बढ़ता रहता है।

आज के समय में जीवन की गति अत्यंत द्रुत हो गई है और हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। ऐसे में दृष्टिकोण की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। आधुनिक जीवन में तनाव, असंतोष और अवसाद जैसी समस्याएं अनियंत्रित रूप से बढ़ रही हैं। इन समस्याओं का प्रमुख कारण यह है कि हम जीवन की घटनाओं को देखने का संतुलित और सकारात्मक नजरिया अपने भीतर विकसित नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में जीवन में आने वाली अधिकांश समस्याएं उतनी बड़ी और जटिल नहीं होतीं, जितना कि हम उन्हें अपने दृष्टिकोण के कारण बना लेते हैं। अगर हम उन्हें आत्मपरिष्कार और आत्मविकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें, तो वही समस्याएं हमारे व्यक्तित्व को परिमार्जित करने का माध्यम बन सकती हैं। दृष्टिकोण का संबंध केवल आशावाद से ही नहीं है, बल्कि विवेक और संतुलन भी इसे निर्धारित करने में महती भूमिका निभाते हैं।

सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं है कि हम वास्तविकता से आंखें मूंद लें। इसका अर्थ यह है कि हम परिस्थितियों को समझदारी, बुद्धिमत्ता और धैर्य की कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार करें और उनमें सुधार या उनके प्रति प्रतिक्रिया की संभावनाएं तलाशें। आज यह नितांत आवश्यक हो चला है कि हम आलोचनात्मक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करें, ताकि सत्य और भ्रम के बीच सुस्पष्ट अंतर कर सकें। बिना सोचे समझे किसी भी विचार को स्वीकार कर लेना हमारे दृष्टिकोण को संकीर्ण और असंतुलित बना सकता है।

अगर हमारा दृष्टिकोण उदार और सहानुभूतिपूर्ण है, तो हम दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत अगर हमारा दृष्टिकोण अहंकारपूर्ण और संकीर्ण है, तो वह हमारे संबंधों में दूरी और तनाव उत्पन्न कर सकता है। विविधताओं से भरे समाज में यदि लोग एक-दूसरे के प्रति सम्मान और समझ का दृष्टिकोण रखें, तो बड़े से बड़े मतभेद भी समुचित संवाद के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन अगर दृष्टिकोण कट्टरता और असहिष्णुता से भरा हो, तो वही मतभेद संघर्ष का रूप ले लेते हैं।

यह भी सच है कि दृष्टिकोण जन्मजात नहीं होता, बल्कि यह धीरे-धीरे विकसित होता है। आत्मचिंतन, अध्ययन, संवाद और अनुभव के माध्यम से व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को अधिक परिपक्व और व्यापक बना सकता है। जब हम अपने विचारों की सीमाओं को पहचानते हुए दूसरों के अनुभवों से सीखने का प्रयास करते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से विस्तार पाता है। समस्याओं के प्रति केवल आलोचनात्मक दृष्टि रखने से समाधान नहीं निकलते। इसके लिए रचनात्मक और समाधान-केंद्रित नजरिया विकसित करना होगा।

दरअसल, दृष्टिकोण मनुष्य के जीवन का वह आधार है, जो उसकी सोच, व्यवहार और उपलब्धियों को आकार देता है। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होतीं, लेकिन उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण अवश्य हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक, व्यापक और संतुलित बना लें, तो जीवन की कठिन राहें भी अपेक्षाकृत सरल हो जाती हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भीतर झांककर यह समझने का प्रयास करें कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है। अगर उसमें संकीर्णता, निराशा या पूर्वाग्रह के तत्त्व हैं, तो उन्हें बदलने का प्रयास भी हमें ही करना होगा। दृष्टिकोण का परिवर्तन ही वह कुंजी है जो व्यक्ति को सीमाओं से मुक्त कर नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। परिस्थितियां नहीं, बल्कि दृष्टिकोण ही जीवन का वास्तविक निर्माता होता है।

दुनिया मेरे आगे

> यह सच है कि दृष्टिकोण जन्मजात नहीं होता, बल्कि यह धीरे-धीरे विकसित होता है। आत्मचिंतन, अध्ययन, संवाद और अनुभव के माध्यम से व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को परिपक्व बना सकता है। जब हम दूसरों के अनुभवों से सीखने का प्रयास करते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है।

पर्यावरण की कीमत

पर्यावरण की कीमत पर विकास समृद्धि का एक ऐसा भ्रम है, जो अंततः तबाही को न्योता देता है। इस समय वनों की कटाई और प्रदूषण बड़ी चुनौतियां हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों को नष्ट करने वाला विकास दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों को ही नष्ट कर देता है। अनियंत्रित अवसंरचना विकास और औद्योगीकरण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, जिससे बाढ़, भूस्खलन, तापमान में भारी वृद्धि और जैव विविधता की हानि के साथ प्राकृतिक आपदाओं में बढोतरी होती है। इन सबके बावजूद सरकार आंखें मूंदे रहती है। हैरत है कि नागरिक समूहों और पर्यावरणविदों के भारी विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ के हसदेव-अरण्य में 4.48 लाख पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगी गई। केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लाक के प्रस्ताव पर पर्यावरण मंत्रालय की समिति विचार कर रही है। यह कोयला ब्लाक 2015 में आबंटित किया गया था। यह क्षेत्र घने जंगलों के लिए जाना जाता है, यहां तेंदुआ, भालू, हाथी समेत नौ वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं। सरकार को इन सभी पहुलओं पर विचार करना चाहिए।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

नैतिक मूल्यों का क्षरण

'उपेक्षा का दंश झेलते बुजुर्ग' (आलेख, 4 मई) पढ़ा। तेजी से बदलते आधुनिक समाज में जहां तकनीक और जीवन की भागदौड़ ने लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है, वहीं इस विकास की एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई है और वह है- बुजुर्गों की बढ़ती उपेक्षा। पहले जहां परिवारों में बुजुर्गों को सम्मान और निर्णयों में प्रमुख स्थान मिलता था। आज वही बुजुर्ग कई बार अकेलेपन और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में युवा पीढ़ी शहरों की ओर पलायन कर रही है। नतीजा यह कि संयुक्त परिवार धीरे-धीरे टूट रहे हैं। इससे माता-पिता गांवों या पुराने घरों में अकेले रह जाते हैं या फिर वृद्धाश्रमों का सहारा लेने पर मजबूर होते हैं। यह स्थिति भौतिक दूरी का ही नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी का भी संकेत देती है। बुजुर्गों की इस तरह उपेक्षा करना समाज के नैतिक मूल्यों पर सवाल खड़े करता है।

– सावित्री शाह, सिंगरौली

प्रतिशोध की परतें

लोकतंत्र में चुनाव जनमत का उत्सव माना जाता है। मगर जब चुनाव परिणाम के बाद हिंसा, प्रतिशोध और भय का वातावरण बन जाए, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक असहिष्णुता और दलगत कट्टरता समाज को विभाजित कर रही है। सत्ता परिवर्तन या चुनावी हार-जीत के बाद यदि आम नागरिक और राजनीतिक दलों के समर्थक असुरक्षित महसूस करें, तो यह लोकतंत्र की कमजोरी को दर्शाता है। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में विरोधी विचार भी उतने ही अहम हैं। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। प्रशासन और कानून व्यवस्था को निष्पक्ष होकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वह संयम, शांति और लोकतांत्रिक मर्यादा का संदेश दे।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

दोहरा रवैया

देश में बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए घर चलाना कठिन होता जा रहा है। रसोई गैस, राशन, सब्जियों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने से मध्य एवं निम्न वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं। ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों को हर चीज की रियायती सुविधा मिलने की चर्चा आमजन के मन में असमानता की भावना पैदा करती है। जनता सवाल पूछ रही है कि जब आम नागरिक बाजार दरों पर महंगा भोजन खरीदने को मजबूर है, तब जनप्रतिनिधियों को हर चीज में विशेष रियायतें क्यों मिलें? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का दायित्व जनता की समस्याओं को समझना और उनके अनुरूप नीतियां बनाना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी व्यवस्था बने, जिसमें हर नागरिक सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके।

– अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

कुपोषण दूर करने से दुनिया भर में तपेदिक के 23 लाख मामले रोके जा सकते हैं: अध्ययन

कुपोषण की समस्या का समाधान करने से दुनिया भर में तपेदिक (टीबी) के 23 लाख मामलों को रोका जा सकता है। यह संख्या 2023 में वयस्कों को हुए कुल संक्रमणों का 23.7 फीसद है। 'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' जर्नल में प्रकाशित एक 'माडलिंग' अध्ययन में यह जानकारी सामने आई। 'लंदन स्कूल आफ हाइजीन एंड ट्रापिकल मेडिसिन' के शोधकर्ताओं सहित विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि यदि कुपोषण पर ध्यान दिया जाए, तो भारत में टीबी के मामलों में सबसे बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। इसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस और पाकिस्तान का नंबर आता है। लेखकों ने लिखा, 'हमारा अनुमान है कि मध्यम से गंभीर कुपोषण को खत्म करने से वैश्विक स्तर पर टीबी के 14 लाख मामलों को टाला जा सकता है, जो 2023 में वैश्विक वयस्क मामलों का 14.6 फीसद है। वहीं, सभी प्रकार के कुपोषण को खत्म करने से 23 लाख मामले टाले जा सकते हैं, जिससे वैश्विक टीबी प्रसार में 23.7 फीसद की कमी आ सकती है।' (ए)

सोने के प्रति भारतीयों का मोह आयात की बड़ी वजह

जनसत्ता विशेष

भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और यहां प्रतिवर्ष औसतन 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। भारतीयों का सोने के प्रति मोह आभूषण से लेकर निवेश साधन तक हैं।

विश्लेषण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम एशिया में तनाव के मद्देनजर मितव्ययिता अपनाने की अपील के बीच भारत में सोने का बढ़ता आयात चर्चा का केंद्र बन गया है।

मोदी ने रविवार को कहा था कि सरकार लोगों को पश्चिम एशिया संकट के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने की कोशिश कर रही है। ईंधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, सोने की खरीद टालने तथा विदेश यात्राओं को स्थगित करने जैसे कदम उठाने की जरूरत है, ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और यहां प्रतिवर्ष औसतन 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। भारतीयों के सोने के प्रति मोह आभूषण से लेकर निवेश साधन तक हैं। यह खपत मुख्य रूप से आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, क्योंकि भारत में बहुत कम घरेलू उत्पादन होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री को लोगों से इस वर्ष सोने की खरीद टालने की अपील करनी पड़ी। आयात कम होगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव भी कम पड़ेगा। आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग द्वारा संचालित होता है। वैश्विक अनिश्चितता के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है जिससे इसकी मांग बढ़ जाती है।

भारत का सोना आयात 2025-26 में 24 फीसद से अधिक बढ़कर रिकार्ड 71.98 अरब डालर पर पहुंच गया। यह 2024-25 में 58 अरब डालर, 2023-24 में 45.54 अरब डालर, 2022-23 में 35 अरब डालर, 2021-22 में 46.14 अरब डालर, 2020-21 में 34.62 अरब डालर और 2019-20 में 28.2 अरब डालर था। मात्रा के हिसाब से आयात 2025-26 में 4.76 फीसद घटकर 721.03 टन रह गया जो 2024-25 में 757.09 टन था। यह 2023-24 में 795.2 टन, 2022-23 में 678.3 टन था।

आयात बढ़ने के कारण

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सोने के आयात में वृद्धि मुख्य रूप से कीमतों में उछाल के कारण हुई है। कीमत 2024-25 में 76,617.48 डालर प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2025-26 में 99,825.38 डालर प्रति किलोग्राम हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। अप्रैल पिछले वर्ष में यह पहली बार एक लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार गई थी।

अधिक आयात के प्रभाव

सोने के अधिक आयात से देश के व्यापार घाटे एवं विदेशी मुद्रा व्यय पर दबाव पड़ता है। 2025-26 में व्यापार घाटा बढ़कर 333.2 अरब डालर हो गया। चालू खाते का घाटा (सीएडी) भी प्रभावित हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के अनुसार, अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में सीएडी बढ़कर 13.2 अरब डालर (जीडीपी का 1.3 फीसद) हो गया। कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी नौ फीसद से अधिक है। 2025-26 में भारत का कुल आयात 775 अरब डालर रहा।

कहां से अधिक आयात

भारत के लिए सोने का सबसे बड़ा स्रोत स्विट्जरलैंड (करीब 40 फीसद) है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (16 फीसद से अधिक) और दक्षिण अफ्रीका (लगभग 10 फीसद) का स्थान है। वहीं स्विट्जरलैंड से कुल माल आयात (सोने सहित) 2025-26 के दौरान 11.36 फीसद बढ़कर 24.27 अरब डालर हो गया।

आयात कम करने के उपाय

सरकार ने सोना, चांदी और प्लेटिनम से जुड़े उत्पादों के आयात पर नियंत्रण लगाए हैं ताकि मुक्त व्यापार समझौतों के दुरुपयोग को रोका जा सके। कुछ व्यापारी शुल्क अंतर का फायदा उठाकर थाईलैंड जैसे देशों से बिना जड़े आभूषण के नाम पर आयात बढ़ा रहे थे। वर्ष 2022 में आयात शुल्क 10.75 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद किया गया। 2024-25 के बजट में इसे घटाकर छह फीसद कर दिया गया ताकि आभूषण उद्योग को बढ़ावा मिले और तस्करी कम हो। आर्थिक शोध संस्थान 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव' (जीटीआरआइ) ने सरकार से मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा करने को कहा है।

साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी

पंकज रोहिला

संसदीय समिति ने कहा कि सरकार बनाए साइबर वालंटियर वारियर प्रोग्राम।

राष्ट्रीय अपराध संबंधित रपट में सामने आई है अधिक साइबर अपराध की संख्या।

तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध की एक बड़ी वजह साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी कर्मचारियों की कमी है। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार की संसदीय समिति ने गहरी चिंता जाहिर की है और केंद्र से सिफारिश की है कि एक विशेष कार्यक्रम (साइबर वालंटियर वारियर प्रोग्राम) के तहत युवाओं को इस पहल से जोड़ा जाए ताकि देश भर में इन अपराधों से लड़ने के लिए एक विशेष कार्य बल भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।

संसदीय समिति ने अपनी रपट में साफ कहा है कि साइबर अपराध इकाइयों की तकनीकी क्षमता में व्यापक वृद्धि करने की आवश्यकता है। अनेक जिला स्तरीय साइबर सेल में कर्मचारियों की कमी है और आज भी इन सेल में पुराने उपकरणों की मदद से काम किया जा रहा है। इस वजह से साइबर अपराध के मामलों में साक्ष्य निष्कर्षण, डिजिटल फोरेंसिक और क्रास प्लेटफार्म पर काफी अधिक देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी को पूरा करने में साइबर वालंटियर वारियर प्रोग्राम बनना चाहिए, इसमें प्रशिक्षित युवाओं, साइबर सुरक्षा स्नातकों और एथिकल हैकिंग प्रतिभाओं को साइबर पुलिस इकाइयों का सहयोग करने वाले सवैतनिक, प्रमाणित योगदान के रूप में शामिल किया जाए। इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और निजी कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह सिफारिश हाल ही में महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने पेश की है।

रपट बताती है कि यदि साइबर अपराध की स्थिति देखें तो राज्यों में पुलिस ने कुल 77, 390 मामलों का निपटारा किया गया था, जबकि इन राज्यों में इन मामलों की संख्या कुल 1, 22, 498 थी।

बजट के बाद भी कम खर्च पर चिंता जताई

समिति ने साइबर सुरक्षा के लिए वर्ष 2025-26 में पर्याप्त बजट होने के बाद कम खर्च पर चिंता व्यक्त की है। समिति का कहना है कि इस वित्त वर्ष के लिए 782 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान था। इसके बावजूद साइबर अपराध का पता लगाने और निवारण प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास के लिए कोई समर्पित फंड नहीं था। महिलाओं समेत डीपफेक डिटेक्शन, एंटी स्टैकिंग टूल्स, स्वचालित खतरे- खुफिया प्रणाली, सक्रिय निगरानी प्रौद्योगिकी या कृत्रिम मेधा (एआइ) आधारित तंत्र स्थापित करने के लिए कोई भी निर्धारित आवंटन नहीं था। समिति ने भविष्य में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की है।

एनसीआरबी रपट

गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध के आंकड़ों की एक रपट जारी की है। इस रपट में 2024 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया है। रपट बताती है कि यदि साइबर अपराध की स्थिति देखें तो राज्यों में पुलिस ने कुल 77, 390 मामलों का निपटारा किया गया था, जबकि इन राज्यों में इन मामलों की संख्या कुल 1, 22, 498 थी। इस प्रकार औसतन पूरे साल में ऐसे अपराधों से संबंधित लंबित मामलों का फीसद 61.3 था। बीते सालों में साइबर अपराध के मामलों की संख्या में सभी प्रदेशों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। ये मामले वर्ष 2022 में 65, 893, वर्ष 2023 में 86,420 और 2024 में 1,01,928 थे।

डिजिटल कृषि मिशन से करोड़ों किसानों को मिली नई पहचान

सर्वेश कुमार

देश में मार्च से अब तक करीब नौ करोड़ किसान आइडी बनाई जा चुकी हैं। भविष्य में यह पहचान पत्र किसानों को उर्वरक, सबसिडी सहित तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज होगा। नई पहचान से किसानों की जमीन, फसल, मिट्टी और पशुधन का डेटा एक ही जगह सुरक्षित रहेगा।

बदलाव

किसानों की आय बढ़ाने में डिजिटल कृषि मिशन की भूमिका अहम हो गई है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का किसानों को लाभ आसानी से मिले, इसके लिए विशिष्ट डिजिटल किसान पहचान पत्र (आइडी) की अहमियत बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा, फसल सर्वेक्षण सहित सरकार की तमाम योजनाओं का किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए आधार की तर्ज पर 11 अंकों वाले विशिष्ट किसान आइडी उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं।

देश में मार्च तक अब तक करीब नौ करोड़ किसान आइडी बनाए जा चुके हैं। भविष्य में यह पहचान पत्र किसानों को उर्वरक, सबसिडी सहित तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज होगा। नई पहचान से किसानों की जमीन, फसल, मिट्टी और पशुधन का डेटा एक ही जगह सुरक्षित रहेगा। इस मिशन का उद्देश्य समय पर सटीक जानकारी प्रदान कर, उत्पादन लागत को कम करते हुए फसलों का नुकसान करना है ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। यह अभियान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्रीस्टैक परियोजना के तहत चलाया जा रहा है।

डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य मकसद खेती के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआइ) तैयार कर मिट्टी, जमीन, फसल, जानवरों के लिए किसान केंद्रित डिजिटल समाधान के लिए एक सशक्त डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। एग्रीस्टैक डीपीआइ में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन बुनियादी डेटाबेस हैं। इनमें किसानों की पहचान, भूमि रिकार्ड, आय, ऋण, बीमा, फसल समेत किसानों से संबंधित संपूर्ण ब्यौरा संरक्षित किया जाता है।

मार्च तक अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों को विशिष्ट पहचान के लिए 'किसान आइडी' मुहैया की गई है। खासतौर पर विशिष्ट किसान पहचान मिलने से खेती और किसानों को विभिन्न योजनाओं का फायदा मिलने के साथ साथ एकीकृत डेटा से कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान में भी सहूलियतें बढ़ गई हैं। इससे पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, ऋण समेत अन्य योजनाओं का लाभ सटीक, पारदर्शी और त्वरित मिल सकेगा और सभी जानकारियां गोपनीय रहेंगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, अब तक करीब 9 करोड़ किसान आइडी बन चुकी हैं जो ह्यएग्रीस्टैकरह्ल का हिस्सा हैं। आधार की तर्ज पर 11 अंकों वाले यूनिक किसान आइडी बनाकर किसानों को एक यूनिक डिजिटल पहचान दी गई है। इसमें उनकी जमीन, फसल, मिट्टी और पशुधन का डेटा एक ही जगह सुरक्षित रहेगा।

देखभाल

जयपुर में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर नवजात शिशुओं की देखभाल करतीं नर्स।

शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादा कामकाजी

जनसत्ता विशेष

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, डेयरी और पारिवारिक कार्यों में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है।

रपट

देश में शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं ज्यादा कामकाजी हैं। हालांकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की रोजगार भागीदारी अब भी काफी कम बनी हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति शहरों के मुकाबले बेहतर है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) की भारत में महिलाएं और पुरुष 2025 विषय पर रपट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की संख्या शहरों के मुकाबले 19 फीसद अधिक हैं। शहरों में एकल परिवार, सुरक्षित कार्यस्थल, बेहतर परिवहन, बच्चों की देखभाल की सुविधाएं सहित अन्य बड़ी समस्याएं हैं। रपट के श्रमिक-जनसंख्या अनुपात के अनुसार देश में 15 साल से अधिक आयु के कुल पुरुषों में 76.6 फीसद किसी न किसी रोजगार या आर्थिक गतिविधि में शामिल रहे, जबकि महिलाओं में यह अनुपात केवल 38.8 फीसद दर्ज किया गया। कुल आबादी के स्तर पर यह अनुपात 57.4 फीसद रहा। ग्रामीण भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का कार्य भागीदारी अनुपात 78.4 फीसद रहा, जबकि महिलाओं का अनुपात 44.9 फीसद दर्ज किया गया।

कुल ग्रामीण आबादी में कार्य भागीदारी 61.2 फीसद रही। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, डेयरी और पारिवारिक कार्यों में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। यह रोजगार का एक साधन है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार भागीदारी काफी कम दिखाई दी।

जलवायु जोखिमों को समझने और निपटने में मददगार बनेगा 'क्रेविस'

सुशील राघव

'क्रेविस' का उद्देश्य केवल मौसम के आंकड़े दिखाना नहीं, बल्कि भविष्य के जलवायु जोखिमों का आकलन कर सरकारों, उद्योगों और नीति निर्माताओं को बेहतर फैसले लेने में मदद करना है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

पहल

जलवायु परिवर्तन अब केवल भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल हो चुका है। देश के कई हिस्सों में बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे समय में भारत ने जलवायु जोखिमों को समझने और उनसे निपटने के लिए एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है।

ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) ने 'क्लाइमेट रेजिलिएंस एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन इंटेलिजेंस सिस्टम' यानी 'क्रेविस' मंच विकसित और जारी किया है। यह मंच जलवायु संबंधी आंकड़ों को एक ही जगह पर उपलब्ध कराने वाला एआइ-सक्षम तंत्र है। 'क्रेविस' का उद्देश्य केवल मौसम के आंकड़े दिखाना नहीं, बल्कि भविष्य के जलवायु जोखिमों का आकलन कर सरकारों, उद्योगों और नीति निर्माताओं को बेहतर फैसले लेने में मदद करना है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। बढ़ती आबादी, तेजी से शहरीकरण और कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी के कारण जलवायु जोखिमों का असर और गंभीर हो सकता है। ऐसे में 'क्रेविस' जैसी प्रणाली भविष्य की चुनौतियों को पहले से समझने और उनके अनुरूप तैयारी करने में मदद कर सकती है। यह केवल आपदा प्रबंधन का उपकरण नहीं, बल्कि आर्थिक योजना, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि नीति और शहरी विकास के लिए भी एक रणनीतिक मंच बन सकता है।

'क्रेविस' एक एकीकृत जलवायु जोखिम क्लाइमेट रिस्क बुद्धिमत्ता मंच है, जो 40 वर्षों के ऐतिहासिक जलवायु आंकड़ों को भविष्य के अनुमानों के साथ जोड़ता है। यह मंच 2030-2050 और 2051-2070 तक के जलवायु परिदृश्यों का अनुमान प्रस्तुत करता है। खास बात यह है कि यह केवल राष्ट्रीय या राज्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला और 25 गुणा 25 किलोमीटर ग्रिड स्तर तक विश्लेषण कर सकता है। इस मंच में 279 संकेतकों के आधार पर तापमान, वर्षा, नमी, सूखा, अत्यधिक गर्मी और भारी बारिश जैसी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी जिले में आने वाले वर्षों में कितने 'लू' वाले दिन बढ़ सकते हैं, कितनी भारी बारिश हो सकती है, सूखे की अवधि कितनी लंबी हो सकती है आदि के बारे में 'क्रेविस' अनुमान लगाने में सक्षम है। 'क्रेविस' विभिन्न सरकारी और वैज्ञानिक संस्थानों के आंकड़ों को एकीकृत करता है। इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकर, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली और आइआइटीएम पुणे जैसे संस्थानों के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

यह मंच कृत्रिम बौद्धिमत्ता और आंकड़ों की मदद से जलवायु के पैटर्न का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ रहा है और वहां बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, तो 'क्रेविस' इन दोनों आंकड़ों को जोड़कर भविष्य में संभावित बिजली संकट या इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव का आंकलन कर सकता है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस जिले में सूखे की संभावना अधिक होगी और वहां कौन-सी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में यह मंच यह समझने में मदद करेगा कि किन इलाकों में बाढ़ या अत्यधिक गर्मी का खतरा अधिक है, ताकि 'मास्टर प्लान' और 'इंफ्रास्ट्रक्चर' निवेश उसी हिसाब से किए जा सकें।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

विसंगती कोणाला जाणवत नाही का?

'**अदृश्य अर्थदृष्टी**' हा अग्रलेख (१२ मे) वाचला. प्रत्येक गोष्टीत लोकांच्या भावनेला, धर्मप्रेमाला, देशप्रेमाला हात घालून बेमालूमपणे स्वतःचे अपयश लपवणे, प्रसंगी स्वतःच्या अपयशाचे खापर विरोधक वा पूर्वसुरींच्या माथ्यावर फोडणे ही चलाखी मोदी कुशलतेने करतात हे मान्यच केले पाहिजे. काही मूलभूत प्रश्न पडतात :

(१) नोटाबंदीचे पुढे काय फलित निघाले? तो शब्दच मोदींनी आपल्या शब्दकोशातून काढून टाकला आणि आता त्याबद्दलची रंजक माहिती धंदेवाईक मसाला चित्रपटातून लोकांना दिली जात आहे, हे अपयश कोणाचे?

(२) आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी तळ गाठला असताना जो प्रचंड नफा सरकारने कमावला, त्याचा हिशेब कोणी द्यायचा?

(३) निवडणुकांच्या तोंडावर प्रच्छन्नपणे रेवड्या वाटण्यासाठी हजारो कोटी रुपये उधळले जातात ते कोणत्या आर्थिक शिस्तीत बसते?

(४) अर्थव्यवस्थेच्या ट्रिलियनच्या ट्रिलियन उड्डाणांची अभिमानाने जाहिरात केली गेली, मग एवढी सशक्त अर्थव्यवस्था असताना आता मायमाउलींच्या गुंजभर सोन्यावर नजर जायची वेळ का आली?

(५) काटसकरीचा उपदेश करणारे पंतप्रधान स्वतः दुसऱ्याच दिवशी आणखी एक मंदिरातील भपकेबाज कार्यक्रमात दिसले, यात विसंगती कोणाला जाणवत नाही का?

(६) परदेश प्रवास टाळण्याचे धोरण परदेशी पर्यटकांनी भारताबाबत अंगीकारले तर?

हे प्रश्न सामान्य नागरिकाला पडतात पण देशाच्या म्होरक्यांना पडत नाहीत हेच आजच्या घडीचे वास्तव आहे.

■ **डॉ. रत्नप्रभा मोरे,** ठाणे

आधी स्वतःचे आचरण तपासावे

'**अदृश्य अर्थदृष्टी**' हा अग्रलेख वाचला. काटकसरीच्या उपायांबाबत या सरकारचा इतिहास अत्यंत निराशाजनक आहे. पंतप्रधान स्वतः आपल्या डोळे दिपवणाऱ्या पोशाखांमुळे उधळपट्टीसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. एकीकडे ते नागरिकांना काटकसरीचे उपदेश करतात, तर दुसरीकडे कोणत्याही निवडणुकीशिवाय रोड शो आणि राजकीय रॅली आयोजित करण्यात मग्न असतात. आता ते पुढील आठवड्यात अनेक देशांच्या दौऱ्याची योजना आखत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांचे काटकसरीचे आवाहन कोण गांभीर्याने घेईल?

या सरकारचा १२ वर्षांचा लेखाजोखा मांडताना मन विषण्ण होते. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती तळ गाठत होत्या, तेव्हा सरकारने बेसुमार कर आकारून सामान्य माणसाला लुटले आणि तेल कंपन्यांनी अमाप नफा कमावला व बक्कळ लाभांश सरकारला दिला. आता किमती वाढल्या असताना सरकार बचतीचे सल्ले देत आहे. कोणत्याही राज्य सरकारने व्हॅट कमी केलेला नाही. परकीय पर्यटकांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी आपण काय केले? मजबूत पायाभूत सुविधांचे ढोल बडवले जात असतानाही परकीय पर्यटक भारतीय पर्यटनस्थळांकडे पाठ का फिरवत आहेत?

'मेक इन इंडिया'चा जयजयकार होतो, मग परकीय चलन का येत नाही? परकीय संस्थागत गुंतवणूकदार भारतापासून का दूर पळत आहेत? डॉलरमधील फ्युचर्स ट्रेडिंगमुळे देशाला प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले आहे. सरकारच्या सोने रोखे योजनेमुळे लाखो-कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अर्थमंत्री इंग्रजीत अस्खलित बोलतात, परंतु त्यांचा कारभार आर्थिकदृष्ट्या शून्य आहे. काटकसरीचे उपदेश करणाऱ्यांनी आधी स्वतःचे आचरण तपासणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे सारे उपदेश जनतेसाठी केवळ उपहासाचा विषय ठरतात.

■ **राम लेले,** पुणे

हे धोरणात्मक अपयश नाही काय?

'**अदृश्य अर्थदृष्टी**' हा संपादकीय लेख (१२ मे) वाचला. देशाच्या पंतप्रधानांनी इंधन बचतीसाठी जनतेला केलेले आवाहन वरवर योग्य वाटत असले तरी, त्यामागील वास्तव आश्चर्यकारक आहे. सरकारने स्वतःच्या धोरणात्मक अपयशाचेही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

(१) पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा असे सांगताना, मागील दशकभरात भारताचे ई-वाहन धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवून इंधनाला सक्षम पर्याय देण्याकडे दुर्लक्ष का झाले? आज चीनसारख्या अवाढव्य देशात ई-वाहनांच्या आक्रमक धोरणामुळे पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व खूप कमी झाले आहे.

(२) १९९१ पासून आजतागायत देशात संकटाच्या वेळी किमान सहा महिने पुरेल इतका इंधनाचा सामरिक साठा आपण का निर्माण करू शकलो नाही? या दूरदृष्टीच्या अभावावर सर्वोच्च नेतृत्वाने विचार करणे गरजेचे नाही का?

(३) सार्वजनिक वाहतुकीची उडालेली दाणादाण सरकारने पाहावी. महाराष्ट्राच्या एसटी महामंडळाचेच उदाहरण घ्या. सर्वाधिक प्रवाशांचा भार पेलणाऱ्या एसटीला ५० वर्षांत साधे 'रिअल-टाइम जीपीएस' किंवा एक व्यवस्थित मोबाइल ॲप देता आलेले नाही.

सक्षम आणि अद्ययावत पर्याय उपलब्ध करून न देता केवळ काटकसरीचे सल्ले देणे हा शाश्वत उपाय होऊ शकत नाही. हे 'नवीन भारता'चे धोरणात्मक अपयश नाही काय?

■ **आदित्य म्हस्के,** सिन्नर (नाशिक)

सरकारलाही करता येण्यासारखे काही...

सरकार आणि नागरिक दोघेही जबाबदारीने वागल्याने देश मजबूत होतो. शासनातर्फे करण्यासारख्या काही गोष्टी आहेत. सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध आणावा. भारतातील घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोने आहे. गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम अधिक प्रभावी करावी. विजेवरील वाहनांना प्रोत्साहन द्यावे. सार्वजनिक वाहतुकीत सुधारणा करावी. 'मेक इन इंडिया'सारख्या उपक्रमांतून इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री आणि संरक्षण क्षेत्रातील आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. चैनीच्या वस्तूंवर अधिक आयात शुल्क लावावे. चांगली शीतगृहे बांधल्यास अन्नधान्याची नासाडी कमी होईल. कौशल्य विकासावर भर द्यावा. भारतीय उत्पादनांसाठी अधिक व्यापार करार करावेत.

■ **राजेंद्र साळोखे,** सांगली

आजची काटकसर उद्याची संजीवनी

'**अदृश्य अर्थदृष्टी**' हा अग्रलेख वाचला. आवाहनातील प्रत्येक बाब काळजीपूर्वक अमलात आणल्यास अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. रुपयाचे झालेले अवमूल्यन सावरू शकते. त्यासाठी लोकसेवक, लोकप्रतिनिधी यांनीही मोठ्या प्रमाणात जागृती करणे आवश्यक आहे. बचतीचा फायदा हा नागरिक, समाज आणि राष्ट्र सर्वांना होऊ शकतो. आजची काटकसर उद्याची संजीवनी आहे.

■ **शांताराम मराठे,** जोगेश्वरी (मुंबई)

हे तर जखमेवरचे मीठ

इस्रायल- इराण संघर्ष २८ फेब्रुवारीला सुरू झाला. होर्मुझची खाडी बंद केली गेली. स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल, डिझेल, युरियाच्या टंचाईची टांगती तलवार डोक्यावर लटकू लागली. पण सरकार म्हणत राहिले की परिस्थिती नियंत्रणात आहे. याचे कारण सर्वांनाच माहीत होते- तोंडावर आलेल्या निवडणुका आणि त्या कशाही प्रकारे जिंकण्याची दुर्दम्य महत्त्वाकांक्षा.

या निवडणुकांच्या काळात प्रचारासाठी अनेक गाड्यांचे ताफे घेऊन, विमान प्रवास केले गेले. त्यावेळी या आर्थिक संकटाची जाणीव पंतप्रधानांना का झाली नाही? की त्यांना सत्ता कायम राखणे एवढेच स्वतःचे काम आहे, असे वाटते? निवडणुका जिंकल्यावर लगेच त्यांनी देशवासीयांना त्यागाचे आवाहन केले आणि नंतर लगेचच स्वतः ३० वाहनांच्या ताफ्यासह सोमनाथ येथे रोड शो केला. शिवाय १५ मे रोजी ते युरोपीय देशांच्या दौऱ्यावर जात आहेत. एखाद्या व्यक्तीला इतरांना उपदेश करण्याचा अधिकार तेव्हाच मिळतो जेव्हा, ती व्यक्ती स्वतः योग्य आचरण करते. मला वाटते मोदींनी आधी स्वतःची आवाहने आचरणात आणावीत आणि मगच जनतेला सांगावीत. अर्थात पेट्रोल- डिझेलचे भाव आता एवढे वाढतील की सामान्य जनतेला काटकसर करावीच लागेल, पण त्याला 'त्याग' असे गोंडस नाव तरी देऊ नये. लोकांवर सोने गहाण ठेवून कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. वर्क फ्रॉम होम दूरच, नोकऱ्याच जात आहेत. याला त्याग म्हणणे हे आधीच भरडले गेलेल्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.

■ **डॉ. मंजिरी मणेरीकर,** दादर (मुंबई)

शेतीपुढे तिहेरी संकट!

युद्ध, बदलते हवामान आणि महागाई ही आव्हाने भारतातील शेतकऱ्याला भेडसावत आहेत. खाद्य असुरक्षेचे संकट आगामी काळात गहिरे होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

विकास परसराम मेश्राम

vikasmeshram04@gmail.com

मध्य-पूर्वेतील धगधगणाऱ्या युद्धाचे चटके आता हळूहळू सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचू लागले आहेत. या संघर्षाची खरी किंमत मोजली जाते रोजच्या बाजारात, भाजीपाल्याच्या दुकानात आणि शेतकऱ्याच्या उद्ध्वस्त मनात. महागडे कच्चे तेल, गगनाला भिडलेल्या खताच्या किमती आणि शेतीचा वाढता खर्च या गोष्टी एकत्र येऊन जागतिक खाद्यमहागाईसाठी जमीन तयार करत असून हे संकट थेट माणसाच्या पोटापाण्याशी निगडित आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफएओ) आपल्या ताज्या अहवालात एक महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. जागतिक खाद्यकिंमत निर्देशांक सलग दुसऱ्या महिन्यात वाढला असून मार्च २०२६मध्ये तो १२८.५ अंकांवर पोहोचला. फेब्रुवारीच्या तुलनेत तब्बल २.४ टक्के अधिक. एक वर्षापूर्वीच्या तुलनेत हा आकडा एक टक्क्याहून अधिक आहे. मार्च २०२२च्या विक्रमी पातळीपेक्षा हे अजून सुमारे २० टक्के कमी असले तरी, पुन्हा चढ्या दिशेने सुरू झालेली वाटचाल चिंताजनक आहे. कारण बाजार एखाद्या लंबकाप्रमाणे असतो. एकदा गती पकडली की थांबणे कठीण होते. या वाढीची मुळे शोधायची तर उत्तर एकाच ठिकाणी सापडते कच्चे तेल. मध्य-पूर्वेतील संघर्षाने ऊर्जाबाजारात अस्थिरता आणली आहे. युद्धाचे ढग गडद होताच कच्चे तेल महाग होते, आणि तेल महाग झाले की एक अदृश्य लाट संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतून धावत जाते. ट्रॅक्टर चालवणे, खत, माल वाहतूक महाग होते. शेती ही एकच अशी गोष्ट आहे जिचा खर्च एकाच वेळी अनेक बाजूंनी वाढतो आणि तरीही शेतकऱ्याला मिळणारा भाव मात्र बाजाराच्या मनावर अवलंबून असतो. वाढलेल्या खर्चाचा बोजा अखेर ग्राहकाच्या थाळीवर येऊन पडतो, हे तर अगदी शालेय अर्थशास्त्राइतके साधे सत्य आहे.

या साखळीत सर्वांत आधी धक्का बसतो तो गव्हाला. मार्चमध्ये गव्हाच्या जागतिक किमती ४.३ टक्क्यांनी वाढल्या. अमेरिकेत दुष्काळाने पिकांच्या अपेक्षा धुळीस मिळवल्या, तर ऑस्ट्रेलियात महागड्या खतांमुळे शेतकरी पेरणी कमी करण्याच्या विचारात आहेत. पुढे मक्याच्या किमती ०.९ टक्क्यांनी वाढल्या कारण महागड्या तेलामुळे इथेनॉलची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे आणि ब्राझिल व अमेरिकेत हवामानाच्या अनिश्चिततेने पुरवठ्यावर दबाव आणला आहे. तांदळाच्या किमती काही प्रमाणात घसरल्या, धानाच्या किमतीत तीन टक्के घट दिसून आली, पण ही घसरण अल्पकालीन असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण परिवहन खर्च वाढल्याने निर्यातदार देशांमधील बाजारावरचा दबाव कायम आहे. खाद्यतेल महागले आहे. हा निर्देशांक गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल १३.२ टक्के अधिक आहे. पाम तेलाने तर २०२२ नंतरची सर्वोच्च पातळी गाठली. एप्रिलमध्ये हा निर्देशांक आणखी उसळून १९३.९ अंकांवर पोहोचला. जुलै २०२२ नंतरची ही सर्वात उंच पातळी आहे.

कच्च्या तेलाच्या चढत्या किमतींमुळे जैवइंधन म्हणजेच बायोफ्युएलची मागणी जगभरात वाढत आहे. सोयाबीन तेलातून इथेनॉल बनवणे परवडते, त्यामुळे सोयाबीन तेलाचे भाव उसळतात. काळ्या समुद्राच्या क्षेत्रातून होणारा पुरवठा युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विस्कळीत झाला आहे, त्यामुळे सूर्यफुलाचे तेल महाग होते. दक्षिण-पूर्व आशियात उत्पादन घटण्याच्या भीतीने पाम तेलाच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. पाम, सोया, सूर्यफूल आणि रेपसीड चारही तेले एकाच वेळी महाग झाली आहेत. आणि साखरेच्या किमतीही या वादळात सापडल्या आहेत. मार्चमध्ये साखरेचे भाव ७.२ टक्क्यांनी वाढले, कारण सर्वांत मोठा साखर उत्पादक ब्राझील आपला ऊस वाढत्या प्रमाणात इथेनॉलसाठी वापरत आहे, कारण इंधन बाजारात जैवइंधनाची मागणी उंचावली आहे. साखरेचे भाव नोव्हेंबर २०२५ नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले होते. मात्र एप्रिलमध्ये भारत, थायलंड आणि ब्राझीलमध्ये चांगल्या उत्पादनाच्या अपेक्षेने किमती ४.७ टक्क्यांनी घसरल्या. साखर निर्देशांक ९२.८ वरून ८८.५ अंकांवर आला. पण ही घसरण टिकेल का, याची हमी कुणीच देऊ शकत नाही.

एफएओचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मॅक्सिमो टोरेरो यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे 'ऊर्जासंकट आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावाचे परिणाम आता खाद्यबाजारांपर्यंत पोहोचत आहेत. महागडे इंधन आणि खते कृषीखर्च वाढवत आहेत आणि त्याचा बोजा अखेर सामान्यांवर पडत आहे.' त्यांनी पुढे इशारा दिला, हा संघर्ष लांबला तर शेतकऱ्यांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. कमी खत, कमी पेरणी आणि कमी खर्चाच्या पिकांकडे वळणे याचा फटका पुढच्या हंगामात उत्पादनाला बसेल. आणि खाद्यकिमतींचा भडका उडेल.

या संकटाचा सर्वात खोल व्रण उमटतो तो गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर. ज्या घरांमध्ये कमाईचा मोठा हिस्सा आहारावर खर्च होतो, तिथे थेट ताटातील जेवण कमी होते. श्रीमंताला महागाई 'दिसते' गरिबाला ती 'सोसावी लागते'. जागतिक खाद्यसुरक्षातज्ज्ञ सतत इशारा देत आहेत की ऊर्जासंकट, युद्ध आणि हवामान बदलाच्या आपत्ती जर याच गतीने सुरू राहिल्या, तर जगभरातील कमकुवत देशांमध्ये आणि उत्पन्नाच्या तळाशी असलेल्या कुटुंबांमध्ये खाद्यसुरक्षा आणि कुपोषणाचे संकट अधिक गडद होऊ शकते. अन्न, दूध, तेल लाखो लोकांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले आहे आणि हे केवळ आर्थिक नव्हे, तर मानवी संकट आहे.

जागतिक खाद्यसंकटाची एक बाजू बाजारात दिसते, तर दुसरी बाजू शेतीत आणि ती बाजू कितीतरी अधिक वेदनादायक आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) नुकताच 'भारतातील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या २०२४' हा अहवाल जाहीर केला. त्याने एक धक्कादायक वास्तव समोर ठेवले आहे. २०२४ या एकाच वर्षात देशात कृषी क्षेत्राशी संबंधित १०,५४६ जणांनी आपले जीवन संपवले. देशातील १,७०,७४६ आत्महत्यांत हे प्रमाण ६.२ टक्के आहे. म्हणजे रोज सरासरी २८ शेतकरी व शेतमजूर जगाचा निरोप घेत आहेत. ही संख्या २०२३ च्या तुलनेत थोडी कमी आहे तेव्हा १०,७८६ जणांनी आत्महत्या केली होती. २०२२ मध्ये हा आकडा सर्वाधिक ११,२९० इतका नोंदवला गेला होता आणि त्यानंतर तो हळूहळू घसरत आला. पण पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता, भारतात दर तासाला सुमारे एक शेतकरी आपले जीवन संपवत असल्याचे दिसते.

आत्महत्या करणाऱ्या १०,५४६ जणांपैकी तब्बल ५,९१३ (५६ टक्के) शेतमजूर होते. हे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक आहे. २०२० मध्ये हेच प्रमाण ४७.७५ टक्के होते म्हणजे चार वर्षांत ते आठ टक्क्यांनी वाढले आहे. शेतमजूर हे सहसा चर्चेत येत नाहीत. 'शेतकरी आत्महत्या' या संज्ञेत आपण बहुतांशी जमीनमालक शेतकऱ्यांचाच विचार करतो. मात्र ज्या माणसाकडे स्वतःची जमीनही नाही, जो दुसऱ्याच्या शेतात राबतो, पण ज्याची मजुरी वाढत्या महागाईपुढे तोकडी पडत आहे त्या शेतमजुराची व्यथा समाजाच्या नजरेआड राहते.

या बदलाचे एक महत्त्वाचे आर्थिक कारण आहे. गेल्या अनेक वर्षांत शेती-उत्पादनातून होणारे उत्पन्न घटत आहे आणि मजुरीवर अवलंबित्व वाढत आहे. शेतीतील नफ्याने घर चालत नाही, म्हणून कुटुंबातील सदस्य मजुरीसाठी बाहेर पडतात. पण खताच्या किमती आणि इंधनखर्च वाढल्याने शेतमालकही मजुरांना कमी दिवस काम देऊ लागतो. परिणामी, शेतमजुराच्या हातात येणारे उत्पन्न अपुरे पडते आणि कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. या कोंडीतून मार्ग दिसेनासा झाला आहे.

राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या ३,८२४ आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या. देशातील एकूण कृषी आत्महत्यांमधील तब्बल ३६.२६ टक्के हिस्सा या एका राज्यातून आला. देशातील सर्वांत प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची ही अवस्था चिंताजनक आहे.

एनसीआरबी अहवाल या आत्महत्यांची नेमकी कारणे सांगत नाही, पण एक तथ्य नोंद घेण्यासारखे आहे. २०२४मध्ये महाराष्ट्रात पूर व अतिवृष्टीमुळे किमान २० लाख ३७ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान झाले. हा आकडा देशभरात टोकाच्या हवामानामुळे बाधित एकूण ४० लाख ७२ हजार हेक्टरपैकी जवळपास निम्मा आहे. म्हणजे एकाच राज्याने देशाच्या अर्ध्या पिकनुकसानीचा बोजा उचलला आहे. पीक गेले, उत्पन्न गेले, कर्ज राहिले आणि शेतकऱ्याच्या सहनशक्तीचा बांध फुटला. महाराष्ट्राखालोखाल कर्नाटकात २,९७१, मध्य प्रदेशात ८३५, आंध्र प्रदेशात ७८०, तमिळनाडूत ५०३ आणि छत्तीसगडमध्ये ४८६ आत्महत्या नोंदल्या गेल्या. वाढीच्या दरात मात्र कर्नाटक सर्वांत पुढे आहे. तिथे गतवर्षाच्या तुलनेत २२.६१ टक्क्यांनी वाढ झाली. राजस्थानात १४ टक्के आणि मध्य प्रदेशात ७.४६ टक्के वाढ दिसून आली. आंध्र प्रदेशात मात्र आत्महत्यांमध्ये १५.६७ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली हा थोडासा दिलासा. पण एकूण चित्र गडद आहे.

या साऱ्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा एकच मार्ग आहे परवडणारी शेती. खत आणि बियाण्यांवरील अनुदान पुरेसे असणे, पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, हमीभाव लागू करणे आणि बाजारात शेतमालाचे योग्य मूल्य मिळण्याची व्यवस्था उभारणे या गोष्टी सोप्या वाटतात, पण प्रत्यक्षात अत्यंत कठीण आहेत. जागतिक स्तरावर युद्ध थांबवणे, ऊर्जाकिमती नियंत्रणात आणणे आणि हवामान बदलांवर उपाय करणे या गोष्टी एका देशाच्या आवाक्याबाहेर आहेत. पण देशांतर्गत धोरणांनी शेतकऱ्याला किमान एक आधार देता येतो की त्याने घेतलेल्या कर्जापायी कुटुंबाची उपासमार होणार नाही आणि पीक गेले तरी तो मोडणार नाही.

जगभरातील तज्ज्ञांचे एकमत आहे की कुपोषण आणि खाद्य असुरक्षेचे संकट आगामी काळात अधिक गहिरे होऊ शकते, जर ऊर्जासंकट, भू-राजकीय तणाव आणि हवामान बदलाचे दुष्परिणाम असेच सुरू राहिले. ज्या देशांमध्ये आणि घरांमध्ये लाखो लोक आधीच उपासमारीशी झुंजत आहेत, तिथे खाद्यकिमतींमधील आणखी वाढ म्हणजे जगण्याचा प्रश्न निर्माण होणे. आणि हा प्रश्न केवळ दुर्गम गावांमध्ये नाही महानगरांच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये, छोट्या शहरांतील मजूरवस्त्यांमध्येही तो तितक्याच तीव्रतेने उभा आहे. पण कोणीही लक्षात घेत नाही ही मूलभूत समस्या आहे.

कुतूहल

लीप वर्ष का येतं?

सध्या जगभर सामान्यपणे प्रचलित असलेलं 'ग्रेगोरियन' कॅलेंडर हे पृथ्वीच्या स्वतःभोवतीच्या फेऱ्या, सूर्याभोवतीच्या प्रदक्षिणा आणि त्यामुळे आपल्याला दिसणारी सूर्याची भासमान हालचाल यांच्या गणितावर आधारित आहे.

सूर्य निरीक्षकाच्या मध्यमंडलावर येण्यापासून, पृथ्वी स्वतःभोवती एक फेरी पूर्ण करून पुन्हा एकदा तो निरीक्षकाच्या मध्यमंडलावर येण्यामधल्या काळाला आपण 'सौर दिवस' म्हणतो. या काळात पृथ्वी स्वतःभोवती जवळजवळ ३६१ अंश फिरते, कारण या कालावधीत ती आपल्या सूर्याभोवतीच्या प्रदक्षिणेमध्ये सुमारे एक अंश पुढे गेलेली असते. या कालावधीचे २४ भाग करून आपण त्या प्रत्येक भागाला 'तास' या नावाने ओळखतो. ही झाली पृथ्वीची स्वतःभोवती फिरण्याची अंशिक गती!

पृथ्वी सूर्याभोवती एक प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी असे ३६५.२४२५ दिवस लागतात. आपण ३६५ दिवसांचं वर्ष मानलं तर दर वर्षी सुमारे १/४ दिवस किंवा सहा तासांचा हिशेब लागत नाही. असे सहा तास आपण दर वर्षी बाजूला टाकत गेलो, तर आपले कॅलेंडर आणि नैसर्गिक घटना यांमध्ये विसंगती निर्माण होऊन ती दर वर्षी वाढत जाईल. 'नेमेचि येतो मग पावसाळा' या न्यायाने आपण जे ऋतू अनुभवतो ते जवळजवळ कॅलेंडरच्या तारखेबरहुकूम येतात. त्याशिवाय सूर्याशी निगडित असलेल्या अवकाशीय घटना उदा. विषुवदिन, अयनदिन यांच्या तारखा दरवर्षी १/४ दिवस किंवा दर चार वर्षांनी एक दिवस मागे सरकत जातील.

विषुवदिन व अयनदिन पृथ्वीच्या सूर्याभोवतीच्या फिरण्यामुळे होणारे बदल आहेत. विषुवदिनी म्हणजे २१ मार्च आणि २३ सप्टेंबर या दोन दिवशी रात्र व दिवस समान म्हणजे १२-१२ तास असतात. अयनदिन म्हणजे वर्षातील सर्वात मोठा म्हणजे उन्हाळ्यातला २१ जून किंवा सर्वात लहान म्हणजे हिवाळ्यातला २२ डिसेंबर हे दिवस.

हिंदू पंचांग हे चंद्राधारित आहे. चंद्राची पृथ्वीभोवती फिरण्याची गती अतिशय अनियमित आहे. बारा चांद्र मासांचे वर्ष ३५४ दिवसांचं असतं. हिंदू पंचांगामध्ये हा अकरा दिवसांचा फरक भरून काढण्यासाठी दर सुमारे ३२ महिन्यांनी अधिक मासाची योजना केलेली असते.याच कारणासाठी ग्रेगोरियन कॅलेंडरमध्ये लीप वर्षाची योजना केलेली आहे. या योजनेप्रमाणे दर चार वर्षांनी म्हणजेच चारने भाग जात असलेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिना २८ ऐवजी २९ दिवसांचा असतो. मात्र १००च्या पटीत असलेल्या वर्षाला जर ४०० ने भाग जात असेल तरच ते लीप वर्ष असतं. त्यामुळे सन २००० हे लीप वर्ष होतं पण सन २१०० हे लीप वर्ष नसेल. थोडक्यात कॅलेंडर आणि नैसर्गिक घडामोडी यांचा मेळ राखण्यासाठी लीप वर्ष येतं.

सुनील सुळे
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

गदर पार्टीच्या इतिहासाचे धागेदोरे शोधून काढणारे, हाती लागलेल्या दस्तावेजांचे संकलन, जतन करणारे आणि मिळालेली माहिती पुस्तकरूपाने वाचकांपर्यंत पोहोचवणारे लेखक आणि इतिहासकार मालविंदर जीत सिंग वारैचा यांच्या निधनाने स्वातंत्र्यचळवळीचा एक चालता बोलता साक्षीदार हरपला. सिंग यांनी स्वातंत्र्यलढ्यातील पंजाबच्या योगदानाचा सखोल अभ्यास केला. ब्रिटिशांविरोधात दिल्या गेलेल्या अनेक लढ्यांना अधिकृत मान्यता मिळवून देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यासाठी आवश्यक तो न्यायालयीन लढा दिला आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले.

मालविंदर जीत सिंग वारैचा

वारैचा यांचा जन्म आता पाकिस्तानात असलेल्या गुजरानवाला येथे २१ नोव्हेंबर १९२९ रोजी झाला. पेशाने प्राध्यापक असलेल्या वारैचा यांनी गुरु नानक देव महाविद्यालयात कला शाखेत तीन दशके अध्यापन केले आणि १९८९ मध्ये ते निवृत्त झाले, मात्र दरम्यानच्या काळात इतिहासकार म्हणून त्यांची ओळख प्रस्थापित झाली होती. सेवानिवृत्तीनंतर, त्यांनी कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून एलएलबीचे शिक्षण घेतले आणि त्यांचे भाचे व ज्येष्ठ वकील आर. एस. चीमा यांच्याबरोबर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. जनहित याचिकांच्या माध्यमातून त्यांनी कुका आंदोलन, गदर पार्टी, कोमागाटा मारू हिंसाचार आणि जालियनवाला बाग हत्याकांड यांना अधिकृत मान्यता मिळवून दिली. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या ब्रिटिशांनी जप्त केलेल्या जमिनी त्यांच्या कुटुंबीयांना परत करण्यास त्यांनी सरकारला भाग पाडले.

वारैचा यांनी पाच दशकांहून अधिक काळ पंजाबच्या कानाकोपऱ्यांत प्रवास केला, वृद्ध गदरसमर्थक, स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भेटी घेतल्या, अनेक जीर्ण छायाचित्रे, पत्रे संकलित केली, त्यांचे जतन केले. नातेवाईकांच्या आठवणी आणि न्यायालयातील कागदपत्रांचे संकलन केले. क्रांतिकारकांच्या लढ्यांशी संबंधित कागदपत्रांचे भाषांतर केले. त्यांनी या विषयावर पंजाबी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये ६० हून अधिक पुस्तकांचे लेखन, अनुवाद वा संपादन केले. यात भगत सिंग यांच्यावरील अनेक पुस्तकांचा समावेश आहे.

१९६६ मध्ये ते गदर पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बाबा सोहन सिंग भाकना यांच्या संपर्कात आले आणि १९६७ मध्ये त्यांनी या क्रांतिकारकांच्या आयुष्यावर 'जीवन संग्राम' हे आपले पहिले पुस्तक प्रकाशित केले. त्यांनी भगत सिंग यांच्या आई विद्यावती आणि त्यांचे सहकारी पंडित किशोरी लाल यांची भेट घेऊन संवाद साधला होता. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी प्रभारी सरन्यायाधीश राणा भगवानदास यांनी २००६ मध्ये चंदीगड भेटीदरम्यान भगत सिंग यांच्या खटल्यासंदर्भातील उर्दू कागदपत्रांच्या प्रती पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाला सुपूर्द केल्या होत्या. वारैचा यांनी त्या कागदपत्रांचे संपादन करून अनुवाद केला. त्या माहितीवर आधारित पाच खंड त्यांनी प्रकाशित केले.

आयुष्यभर अभ्यासाला वाहून घेणाऱ्या वारैचा यांच्या इच्छेनुसार, त्यांचे पार्थिव वैद्यकीय संशोधन आणि शैक्षणिक उद्देशांसाठी एका वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्थेला दान करण्यात आले आहे. त्यांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी अनेक विद्यार्थी आणि इतिहास अभ्यासकांचा परिवार आहे.

राजवाडे विचारविश्व

धन्याचे सेवेत जीव देऊन गुन्ह्याचे क्षालन!

पानिपत युद्धाच्या द्विशताब्दी स्मृतिवर्षानिमित्ताने पंजाब विद्यापीठातर्फे प्रा. हरी राम गुप्ता यांनी लिहिलेला 'मराठाज ॲण्ड पानिपत' हा ग्रंथ प्रकाशित झाला, तर प्रा.न.र.फाटक व सेतुमाधवराव पगडी यांनी एकत्र येऊन 'पानिपतचा संग्राम' या शीर्षकाचा ग्रंथ प्रकाशित केला. या मराठी ग्रंथात पगडींनी काही अस्सल फार्सी साधने संकलित स्वरूपात मराठीत आणली, तर फाटकांनी मराठी व फार्सी साधनांची तौलनिक चिकित्सा करून ती एकाच प्रसंगाबद्दल कशी उलटसुलट मतप्रदर्शन करतात, ते सोदाहरण स्पष्ट केले होते. पुढे १९६५ साली इतिहाससंशोधक शं.ना.जोशी यांनी संपादित केलेला 'पानिपतचा रणसंग्राम' हा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला. त्यात साधनांचे संकलनही होते आणि घटनाक्रमाचे विवेचनही होते. नंतरही वेळोवेळी पानिपतवर इंग्रजी-मराठीतून तुरळक पण महत्त्वाचे ग्रंथलेखन होतच राहिले. इयान रिंगसाइड यांचा 'दि डिकेड ऑफ पानिपत' हा निवडक मराठी साधनांचा इंग्रजी अनुवाद उपलब्ध करून देणारा ग्रंथ (१९८४), उदय कुलकर्णी यांनी १४ जानेवारी १७६१ या दिवशीच्या घटनाक्रमाचा संशोधनाच्या आधारे मांडलेला लेखाजोखा : 'सॉलिस्टस ॲट पानिपत' (२०११) किंवा आभास वर्मांचा 'थर्ड बॅटल ऑफ पानिपत' हा प्रचंड तपशीलवार विवेचन सामावणारा ग्रंथ (२०१२) ही काही त्यानंतरची उदाहरणे.

पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईबद्दल ग्रंथलेखन करणाऱ्या या अभ्यासकांनी वेगवेगळी संदर्भसाधने वापरून किंवा त्यांच्या विवेचन-वर्तुळाचा परीघ लहानमोठा करून काही ठाम निष्कर्ष मांडले. साहजिकच एकमेकांच्या निष्कर्षांना छेद देणे किंवा अंशतः मान्यता देणे व अंशतः नवी मांडणी करणे असा प्रकार घडत गेला. लक्षात घेण्यासारखी बाब ही की, पानिपतच्या अपयशाचे सारे खापर राजवाडे यांनी ज्या पद्धतीने एकट्या गोविंदपंत बुंदेले यांच्या माथी फोडले होते, ती पद्धत इतर संशोधकांना व ग्रंथलेखकांना रुचली नाही, पटली नाही. तो परिस्थितीमुळे कसा गांजलेला होता, हे दाखवून देणारी काही पत्रे नंतरच्या काळात उघडकीस आली.

'राजवाडे विचारदर्शन' या मौलिक समीक्षाग्रंथामध्ये डॉ. प्र. न. जोशी यांनी त्याच्या समर्थनासाठी लिहिले, 'भाऊच्या पत्रांतील बोचक शब्दांनी सावध होऊन गोविंदपंत आपल्याकडून होता होईल ते करीत होता. त्या वेळी त्याचे वय साठीच्या वर होते. लढाईचा अनुभव कमी. पण थोडाफार वसूल पाठवून दिल्यावर अबदालीची रसद बुडवण्यासाठी त्याने प्रयत्न चालू केला. अबदालीस हे सहन झाले नाही. त्याने नव्या ताज्या दमाच्या सरदारांना गोविंदपंतावर पाठवले. गोविंदपंत कर्मठ ब्राह्मण. स्नान व संध्या करून सोवळ्याने जेवण करण्याच्या बेतात होता. इतक्यात ही धाड आली. पळापळ सुरू झाली. पळताना गोविंदपंत तीनदा घोड्यावरून पडला. तिसऱ्या खेपेस त्याचा मुलगाही जवळ नव्हता. अशा स्थितीत अफगाणांनी त्याचे शीर कापून नेले आणि भाऊच्याकडे जाणारे धान्य पठाणांस मिळाले. प्राप्त परिस्थितीत धन्यास मदत करता करताच गोविंदपंतास मरण आले.'

'रियासतकार' सरदेसाई यांनीही असेच मत मांडताना लिहिले, 'पानिपतच्या अपयशाचा बराच मोठा वाटा राजवाड्यांनी गोविंदपंताचे माथी मारला, ते बरोबर नाही. त्याने होड्या पुरवल्या असत्या, तरी अखेरचा परिणाम विशेष निराळा झाला असता, असे म्हणता येत नाही. गोविंदपंत मतलबी होता. तसा आर्थिक मतलब त्या काळी सर्व लहानमोठ्यांच्या मनात प्रामुख्याने वसत होता... तो मूळचा कारकून, हिशेबी कामाचा वाकबगार, पण पुष्कळदा शिपाईगिरीचे कामही त्यास शक्तीबाहेर पडले. यजमानांच्या आज्ञा त्याने यथाशक्ती पाळल्या. पंताने आपल्या अडचणी वरिष्ठांना वारंवार लिहून पाठवलेल्या आढळतात, त्यावरून मुद्दाम लबाडी किंवा हरामखोरी त्याने केल्याचे दिसत नाही. चहूंकडची माहिती ठेवून, सावधगिरीने वागून कोणाशीही विकोपास न जाता आपला कार्यभाग व्यवस्थित चालवावा, असा त्याचा परिपाठ उपलब्ध कागदांत व्यक्त होतो... मी चाकर बारगीर स्वामीचा आहे... आम्ही कान धरली शेळी आहो. हुकमी आहो. खावंदाची अहर्निशी सेवा एकनिष्ठपणे करावी हे जाणतो... अशी याची माया... पंताने धन्याचे सेवेत जीव देऊन गुन्ह्याचे क्षालन केले असल्यामुळे आता जास्त विवेचन करण्याची जरुरी नाही.'

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

सत्ताधीशांची ससेहोलपट

युवक, अल्पसंख्याक या मजूर पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांना ग्रीन पार्टीने आपल्याकडे ओढले, तर ज्येष्ठ, मध्यमवयीन आणि ग्रामीण या हुजूर पक्षाच्या मतदारांना 'रिफॉर्म यूके'ने...

ब्रिटनमध्ये गेली काही वर्षे एक विचित्र वास्तव सातत्याने अधोरेखित होत आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रचंड बहुमताने एखादा पक्ष निवडून येतो. संसदीय लोकशाहीत स्थैर्याचा तो पहिला टप्पाच. स्थैर्याच्या पायावर पुढे निर्णयांची, धोरणांची इमारत उभी राहील हेही अध्याहृत. पण पार्लमेंटमध्ये स्थिरस्थावर बनलेल्या सत्ताधीशांना जनतेचा कौल मानवत नसावा बहुधा. कारण कधी पक्षीय राजकारण, कधी अप्रिय निर्णय वा धोरणे यांच्या माध्यमातून आत्मघात करून घेण्याची खोड बहुतेक राजकारण्यांमध्ये दिसून येते. ब्रिटनमध्ये सन २०१९ मध्ये हुजूर (कॉन्झर्वेटिव्ह) पक्ष मोठ्या बहुमताने निवडून आला. तत्कालीन पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या हाताशी त्यांच्या आधी मोजक्याच पंतप्रधानांनी पाहिला होता, असा कौल होता. पण त्यांची उच्छृंखल वृत्ती त्यांच्या पदास अपेक्षित परिपक्वपणा दाखवू शकली नाही. याचा परिणाम नंतरच्या पंतप्रधानांवरही झाला. सत्ता हातात असूनही हुजूर पक्षाला त्या पाच वर्षांच्या काळात बोरिस जॉन्सन, लिझ ट्रस आणि ऋषी सुनाक असे तीन पंतप्रधान द्यावे लागले. त्याच्या आधीची पाच वर्षेही हाच पक्ष सत्तेत होता. त्यावेळी ब्रेग्झिटच्या मुद्द्यावर जनमत घेण्याचा आततायीपणा तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांना नडला. त्यांनी कार्यकाळाच्या मध्यावरच राजीनामा दिला, त्यानंतर थेरेसा मे पंतप्रधान बनल्या. पण पक्षांतर्गत विरोध झाल्यामुळे पुढील निवडणूक बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली लढण्याचा निर्णय झाला अन थेरेसा यांची कारकीर्दही अल्पजीवी ठरली. म्हणजे सत्तेच्या दहा वर्षांमध्ये पाच पंतप्रधान! यात स्थैर्य कुठेच आढळून येत नाही. दहा वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीत मग विक्रमी पराभव. पण त्यांनी निराश होण्याचे कारण नाही, याची काळजी त्यांचे कट्टर विरोधक ब्रिटनचे विद्यमान सत्ताधीश घेत आहेत. तेथील सध्याचे मजूर (लेबर) पक्षाचे पंतप्रधान सर कीर स्टार्मर हेही सन २०२४ मध्ये प्रचंड बहुमताने निवडून आले. तरी त्यांचा मजूर पक्ष सध्या ज्या दिशेने वाटचाल करतो आहे, ते पाहता पुढील सार्वत्रिक निवडणूक त्यांनाही जड जाईल याचे स्पष्ट संकेत मिळू लागले आहेत. इंग्लंडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच वेल्स आणि स्कॉटलंडमध्ये तेथील स्थानिक पार्लमेंटसाठी गेल्या आठवड्यात निवडणुका झाल्या. यात मजूर पक्ष आणि काही प्रमाणात हुजूर पक्ष या प्रस्थापित पक्षांचा धुव्वा उडाला. त्यांच्या तुलनेत रिफॉर्म यूके या बंदिस्त राष्ट्रवादी विचारधाटणीच्या, स्थलांतरितविरोधी पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळाले. रिफॉर्म यूके पक्षाचे नेते नायजेल फराज हे कट्टर युरोपविरोधी आणि ब्रेग्झिटवादी, तसेच उदारमतवादाची खिल्ली उडवणारे आणि ट्रम्पवादाचे निस्सीम चाहते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या पक्षाने गेल्या काही निवडणुकांमध्ये अस्तित्व दाखवायला सुरुवात केली होती. हे फराज पूर्वी युनायटेड किंग्डम इंडिपेंडंट पार्टी या पक्षात होते. आता नवीन पक्ष स्थापला असला, तरी विचार जुनेच. पण इंग्लंडमध्ये या पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जवळपास १४०० जागा जिंकून निर्विवाद बहुमत मिळवले. स्कॉटलंड आणि वेल्स येथील स्थानिक पार्लमेंट निवडणुकांमध्येही जागा जिंकल्या. जागा किती जिंकल्या यापेक्षाही जेथे वर्षानुवर्षे मजूर आणि हुजूर या दोन प्रस्थापित, पारंपरिक पक्षांची घट्ट पकड होती, अशा ठिकाणी रिफॉर्म यूके पक्षाने मारलेली मुसंडी दखलपात्र अशीच. उत्तर इंग्लंडमध्ये अनेक कौंटींमध्ये वर्षानुवर्षे मजूर पक्षाचे उमेदवार निवडून यायचे तेथे रिफॉर्म यूकेने प्रस्थापितांना धक्का दिला. लंडनसारख्या राजधानीच्या शहरात या पक्षाने हुजूर पक्षाकडून पहिला 'बरो' जिंकून घेतला. वेल्स पार्लमेंटमध्ये हा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर आला, तेथे मजूर पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला.

कीर स्टार्मर यांच्यासाठी या निवडणुका म्हणजे त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतली पहिली अग्निपरीक्षा होती. त्यात ते सपशेल नापास झाले. यावरून पक्षात त्यांच्या विरोधात मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. आपण कोणत्याही

ब्रिटनचा राजकीय पोत बदलत चालल्याचे, तेथील द्विपक्षीय मक्तेदारी संपुष्टात येऊ लागल्याचे या निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे.

परिस्थितीत राजीनामा देणार नाही, मात्र पराभवाचा नम्रपणे स्वीकार करतो असे म्हणत स्टार्मर यांनी उसने अवसान दाखवले खरे, पण त्यांच्या जवळपास प्रत्येक पूर्वसुरींनी तसे ते दाखवले होते आणि तरीही त्यांना जावे लागले. ब्रिटिश लोकशाहीमध्ये पक्षांतर्गत नेताबदलाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. यातून मोजक्यांची मनमानी आणि दंडेली चालू नये असे अपेक्षित असते. त्यामुळे तूर्त स्टार्मर यांच्या पदास धोका नाही. पण त्यांच्या पक्षाची पीछेहाट पाहता, सन २०२९ मधील निवडणूक त्यांच्या पक्षास किती आव्हानात्मक ठरेल याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. त्यांच्या सुदैवाने मजूर पक्षाचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या हुजूर पक्षाची कामगिरीही सुमार झाली.

यातून दोन्ही पक्षांनी धडा घ्यावा अशीच ही निवडणूक ठरली. तो धडा म्हणजे, पर्यायी पक्षांची वाढ. रिफॉर्म यूकेप्रमाणेच इंग्लंडमध्ये ग्रीन पार्टी या आणखी एका पक्षाने काही महत्त्वाचे विजय मिळवले. ग्रीन पार्टी हा नावाप्रमाणेच पर्यावरणवादी आणि डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेला पक्ष. या पक्षाला युवकांमधून मिळणारा पाठिंबा नोंदणीय ठरला. ग्रीन पार्टीने मजूर पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांना - युवक आणि अल्पसंख्याक - आपल्याकडे ओढले. या कलबदलाची दखल मजूर नेतृत्वाने घेतली नाही, तर आगामी काळात असे धक्के त्यांना वारंवार खावे लागतील. तिकडे हुजूर पक्षाचा पारंपरिक मतदार - ज्येष्ठ व मध्यमवयीन आणि ग्रामीण - रिफॉर्म यूके पक्षाच्या पारड्यात भरभरून मते टाकत आहे. ब्रिटनमध्ये अजून तरी स्थानिक निवडणुकांच्या निकालांचे पडसाद राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये फारसे उमटत नाहीत. पण बदलत्या काळात हे असेच राहणार याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. मतदारांचा रोष हा सत्तारूढांच्या विरोधात विशेष असतो हे आता प्रगल्भ म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थांमध्येही दिसून येऊ लागले आहे. लोकानुनयी, राष्ट्रकेंद्री, धर्म व वंशकेंद्री, 'परजीवी'विरोधी मुद्द्यांवर झटपट आणि मोठ्या संख्येने निवडून येता येते याची चटक आणि चुणूक लागलेल्या नेत्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्या आक्रमक, भयद्वेषयुक्त प्रचाराला भुलणाऱ्या मतदारांची संख्याही वाढीस लागली आहे. या रेट्यासमोर मध्यममार्गी, उदारमतवादी, सर्वसमावेशक राजकीय विचारधारा कुचकामी आणि अल्पजीवी ठरू लागल्या आहेत याची नोंद घेणे भाग पडत आहे.

ब्रिटनचा राजकीय पोत बदलत चालल्याचे, तेथील द्विपक्षीय मक्तेदारी संपुष्टात येऊ लागल्याचे या निवडणुकांनी दाखवून दिले. युरोपशी काडीमोड घेतल्यानंतर ब्रिटनमधील मतदार आणि नेतेही गोंधळल्यागत झाले आहेत. पण आता मतदारांसमोर एक-दोनपेक्षा अधिक पर्याय उपलब्ध आहेत. रिफॉर्म यूके पक्षाचे सध्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये सहाच खासदार आहेत. ही संख्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत वाढेल हे नक्की. ग्रीन पार्टीचा उदय लोकशाहीवाद्यांसाठी आश्वासक ठरतो. जर्मनी आणि फ्रान्स या इतर दोन मोठ्या युरोपीय देशांमध्येही उजव्या विचारसरणीचे पक्ष वाढत आहेत. पण त्यांची झेप अद्याप सत्तास्थानापर्यंत गेलेली नाही. तरी या दोन देशांप्रमाणेच ब्रिटनमध्येही प्रस्थापित राजकीय पक्षांमध्ये मतदारांपासून दुरावत चालल्याची भावना आहे आणि यावर उपाय काय असावा याविषयी अनभिज्ञता आहे. शंभरहून अधिक वर्षे जुना इतिहास असलेल्या या पक्षांसाठी हे अजिबातच शुभलक्षण नाही. किंबहुना, रसरशीत आणि सशक्त लोकशाही मूल्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या युरोपसाठीही अशा धोक्याच्या घंटा वारंवार वाजू लागल्या आहेत. अल्पकालीन, संकुचित फायद्यांचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षांची वाढ होत आहे, तेथे विशाल जनाधार असलेल्या पक्षांना मात्र एखाद्या निवडणुकीत अक्षरशः फेकून दिले जात आहे. मजूर पक्षाने हे अनुभवले, हुजूर पक्षानेही हे पाहिले. सत्ताधीशांची अशी ससेहोलपट वारंवार का होते आणि ती थांबवायची कशी या विवंचनेत हे दोन्ही पक्ष सापडले आहेत. कदाचित त्यांची ही अवस्था आधुनिक जागतिक व्यवस्थेत प्रतीकात्मकही आहे.

धम्मक्रांतीपुढील आव्हान

लेख

मधु कांबळे
madhukamble61@gmail.com

नुकत्याच सुरु झालेल्या जनगणनेत धर्मांतरित बौद्धांनी फक्त बौद्ध लिहावे की त्यासह पूर्वाश्रमीची अस्पृश्य जातही लिहावी यावरून चर्चा सुरु आहे. या संभ्रमावर प्रकाश टाकणारा लेख.

भारतात १ मेपासून जातीनिहाय जनगणनेला सुरुवात झाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातिव्यवस्थेने ज्यांचे माणूसपणच हिरावून घेतले होते, त्या अस्पृश्य समाजाला जातीच्या चिखलातून बाहेर काढून ज्यांना समता आणि स्वाभिमानाच्या बुद्ध धम्माच्या वाटेवर आणून सोडले, त्यांतील आरक्षणासाठी जगणाऱ्या काही लोकांनी 'जनगणनेत जात सांगा' अभियान सुरू केले आहे. धर्मांतरित बौद्धांमध्ये सध्या जनगणनेत फक्त बौद्ध लिहावे की बौद्धासह पूर्वाश्रमीची अस्पृश्य जातही लिहावी यावरून खल सुरू आहे. 'जात लिहा' असे सांगणाऱ्यांनी सध्या आघाडी घेतली आहे. त्यात उच्चशिक्षितांचा आणि उच्चभ्रूंचा भरणा अधिक आहे. आरक्षण हाच जीव की प्राण असे मानणारे जनगणनेत जाती लिहा असे सांगून तत्त्व आणि व्यवहार अशी फारकत करत आहेत. म्हणजे बौद्ध म्हणून आम्ही जगतोच आहोत, परंतु आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी प्रशासकीय बाब म्हणून अनुसूचित जातीमधील जातीचा उल्लेख करायला काय हरकत आहे, असा त्यांचा प्रश्न किंवा युक्तिवाद आहे.

विशेष म्हणजे तो करणाऱ्यांमध्ये मोठमोठी प्रशासकीय व न्यायालयीन पदे भूषविलेल्यांचा समावेश आहे, त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्याला वजन प्राप्त होते, सामान्य माणसांवर त्यांचा अधिक प्रभाव पडतो. ते सांगतात की, आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी धर्माच्या रकान्यात बौद्ध लिहा आणि अनुसूचित जातीच्या रकान्यात धर्मांतरापूर्वीची अस्पृश्य वर्गातील जात लिहा. केवळ बौद्ध लिहिल्यास अनुसूचित जातीसाठी असणारे आरक्षण धर्मांतरित बौद्धांना मिळणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे.

मुळात बौद्ध हा केवळ धर्म नाही तर जातमुक्त, विषमतामुक्त, समतेचा विचार आहे, तत्त्व आहे, धम्मात जात नाही तर मग इथे बौद्ध आणि जातीचे मिश्रण कसे केले जाते किंवा करायला सांगितले जाते? अर्थात अशा नोंदीला विरोध करणाराही एक वर्ग आहे. बाबासाहेबांनी भारतातील जातिव्यवस्था निर्मूलनासाठी बौद्ध धम्माचा स्वीकार करून समतेचा, स्वातंत्र्याचा, बंधुतेचा विचार देशासमोर ठेवला, की जेणेकरून भारतीय समाजाने जातीच्या अनैसर्गिक, अमानवी मानसिकतेतून बाहेर यावे. परंतु ज्यांनी हा विचार स्वीकारला, तेच आता जात सोडली तर, घटनात्मक भौतिक लाभ हिरावण्याची भीती दाखवून, बाबासाहेबांच्या धम्मक्रांतीने मातीत गाडलेली जातीची मढी पुन्हा उकरून उरावर घेऊन मिरविण्यासाठी आटापिटा करत आहेत.

येवला येथे १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी केलेल्या धर्मांतराच्या घोषणेनंतर ३०, ३१ मे व १ जून १९३६ रोजी मुंबईत झालेल्या अस्पृश्यांच्या विराट परिषदेत 'मुक्ती कोण पथे' या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, तुम्हाला जी जातीवाचक नावे प्राप्त झाली आहेत, त्या नावांना इतकी दुर्गंधी लागलेली आहे की, त्याचा उच्चार केला तरी स्पृश्य लोकांना मळमळते. पुढे ते म्हणतात, हिंदू हा कोणी मनुष्यप्राणी आहे, म्हणून कोणी ओळखीत नाही. महार सांगून भागणार नाही. कारण त्या नावाचा उच्चार केल्यावर कोणी जवळ येणार नाही. असल्या मधल्या स्थितीत घोटाळत राहण्यापेक्षा आज हे नाव, उद्या ते नाव, असे नामांतर करण्यापेक्षा तुम्ही धर्मांतर करून कायमचे नामांतर का करू नये, असा माझा तुम्हाला प्रश्न आहे.

बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी धम्मक्रांतीने लाखोंचे कायमचे नामांतर केले, त्याची जाणीव ठेवायला हवी असे वाटते.

जनगणनेत जातीचा उल्लेख करण्याचे समर्थन करणाऱ्यांनी सामाजिक व राजकीय आरक्षणासंबंधी घटनात्मक व कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याला घटनात्मक व कायदेशीर आधारानेच उत्तर दिले पाहिजे, तरच हा संभ्रम दूर होऊ शकतो.

त्यांचा पहिला मुद्दा आहे, केवळ बौद्ध म्हणून लिहिले आणि जातीचा उल्लेख केला नाही तर, आपण अनुसूचित जातीच्या यादीतून बाहेर जाऊ, सर्वसाधारण प्रवर्गात टाकले जाईल आणि त्यामुळे शिक्षणातील व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण हिरावून घेतले जाईल. म्हणजे हा सामाजिक आरक्षणाचा प्रश्न आहे.

हा प्रश्न खरा आहे का, याचे उत्तर नाही, असे आहे. जनगणनेत, शाळेच्या दाखल्यावर केवळ बौद्ध लिहिले तरी धर्मांतरित बौद्धांना सामाजिक आरक्षण मिळते. संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) कायदा १९९० नुसार आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळतात. अट एकच आहे, पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींमधून धर्मांतर कलेले बौद्ध आरक्षणास पात्र आहेत, त्यात काहीही चूक नाही.

यावरही असा प्रचार किंवा अपप्रचार केला जातो की, बौद्ध अथवा नवबौद्ध म्हणून राज्यात आरक्षण मिळते, परंतु केंद्रीय शिक्षण संस्था व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळत नाही. हा प्रचारही चुकीचा आहे. १९६२ पासून महाराष्ट्रात धर्मांतरित बौद्धांना आरक्षण लागू करण्यात आले. १९९० पासून घटनादुरुस्ती करून बौद्धांना केंद्रातही आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यासाठी जातीच्या दाखल्याचा नमुना क्रमांक सात भरून सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने तो सादर करावा लागतो. महाराष्ट्र शासनाने ३ सप्टेंबर २०१२ रोजी राजपत्रात वेगवेगळ्या प्रकारच्या जातीच्या दाखल्यांचे अधिकृत नमुने इंग्रजी व मराठीमध्ये प्रसिद्ध केले आहेत.

धर्मांतरित बौद्धांसाठी नमुना क्रमांक सातच्या अर्जातील शेवटचा भाग असा... बौद्ध धर्मात धर्मांतरित झालेल्या, अनुसूचित जातीचे आहेत, ज्यांना संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) कायदा अंतर्गत अनुसूचित जाती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा झाला महाराष्ट्रातील बौद्धांसाठी. इतर राज्यांमधील धर्मांतरित बौद्धांसाठी जातीचा दाखला नमुना क्रमांक १० भरून द्यावा लागतो. अशा प्रकारच्या दाखल्यांच्या आधारावर महाराष्ट्रातील बौद्ध विद्यार्थ्यांना बौद्ध म्हणूनच केंद्रीय शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश व केंद्रीय सेवेतील नोकऱ्याही मिळाल्या आहेत, त्याचेही पुरावे उपलब्ध आहेत. अशा दाखल्यांवर कोणत्या अनुसूचित जातींमधून बौद्ध धर्मात धर्मांतर केले आहे, त्या जातीचा अनुक्रमांक लिहिला जातो.

सध्या जनगणनेत केवळ बौद्ध लिहिल्यामुळे सामाजिक आरक्षण मिळणार की नाही, असा वाद सुरू आहे, तर जनगणनेशी संबंधित नोंदींचाही या वादावर पडदा टाकणारा पुरावा उपलब्ध आहे. १९९१च्या जनगणनेतील महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसंबंधी जे. के. बांठिया, (संचालक, जनगणना कार्यसंचालन, महाराष्ट्र) यांनी केलेले विश्लेषण व लिहिलेले टिपण बौद्धांना आरक्षण लागू आहे की नाही, यावर झगझगीत प्रकाश टाकणारे आहे. त्यातील संबंधित महत्त्वाचा भाग असा- संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) अधिनियम १९००च्या परिणामी ज्या अनुसूचित जातींनी आपला धर्म बौद्ध किंवा नवबौद्ध म्हणून नोंदविला आहे, तेदेखील हिंदू आणि शिखांसोबत अनुसूचित जाती म्हणून गणनेत पात्र आहेत. मात्र ज्या राज्यात ज्यांची गणना केली जात आहे, तेथील अनुसूचित जातींच्या यादीत त्यांच्या जातीच्या नावाचा समावेश असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, धर्म बौद्ध किंवा नवबौद्ध लिहिले तरी त्यांना अनुसूचित जातीचे मानले जाते, त्यासाठी जातीचा उल्लेख करण्याची गरज नाही.

आता दुसरा प्रश्न राजकीय आरक्षणाचा म्हणजे लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघाचा. केवळ बौद्ध लिहिल्यामुळे अनुसूचित जातींची लोकसंख्या कमी होते, परिणामी राजकीय राखीव जागाही कमी होतात, कारण त्याचा लोकसंख्येशी संबंध आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे बांठिया अहवालानुसार बौद्ध ही नोंद केल्यामुळे अनुसूचित जातींची संख्या कमी होणार नाही, राजकीय राखीव जागांवर त्याचा परिणाम होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.

मात्र त्याहीपेक्षा राखीव मतदारसंघ निवडणूक पद्धतीला खुद्द बाबासाहेब आंबेडकरांचाच विरोध होता, याची जातीचे घोडे दामटणाऱ्यांना कल्पना आहे काय? एकदा-दोनदा नव्हे तर, पाच वेळा बाबासाहेबांनी आणि त्यांच्या त्या वेळच्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनने पुणे करारानुसार अमलात आलेली राखीव मतदारसंघ निवडणूक पद्धत रद्द करा, अशी मागणी केली होती.

- १८ व १९ जुलै १९४२ रोजी नागपूर येथे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत राखीव मतदारसंघाची तरतूद असलेली निवडणूक पद्धती रद्द करण्याचा ठराव.
- २३ सप्टेंबर १९४४ मद्रास येथे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत असाच ठराव करण्यात आला.
- १९४६ मध्ये पुणे व इतरत्र ब्रिटिश कॅबिनेट मिशनच्या विरोधात बाबासाहेबांच्या थेट कृती आदेशानुसार झालेल्या आंदोलनात अनुसूचित जातींच्या खऱ्या प्रतिनिधींना विधानसभेत परत येण्यापासून रोखणारा पुणे करार रद्द झाला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली होती.
- १५ मार्च १९४७, रोजी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेला राज्य व अल्पसंख्याक या नावाने सादर केलेल्या निवेदनात राखीव मतदारसंघ निवडणूक पद्धत रद्द करा, असा उल्लेख आहे.
- १३ डिसेंबर १९५५ रोजी बाबासाहेबांनी पक्षाची भूमिका म्हणून लिहिलेल्या 'भाषावार प्रांतरचनेवर विचार' या पुस्तकात राखीव मतदारसंघ आणि त्यांची मूळ मागणी असलेली स्वतंत्र मतदारसंघ या दोन्ही निवडणूक पद्धती नकोत, त्याऐवजी बहुसदस्यीय निवडणूक पद्धती आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

याचा अर्थ खुद्द बाबासाहेबांचाच राजकीय राखीव जागांना विरोध होता, मग त्यांचे अनुयायी म्हणवून घेणाऱ्यांना जनगणनेत बौद्ध लिहिल्यामुळे राखीव मतदारसंघ कमी होतील, असा प्रश्न का पडला आहे.

बाबासाहेबांचा दोन कारणांमुळे राखीव मतदारसंघ निवडणूक पद्धतीला विरोध होता. १) राखीव मतदारसंघातून निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी हे समाजाचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत, तर ते ज्या पक्षातून निवडून जातात, त्याची तळी उचलून धरतात. हे प्रतिनिधी म्हणजे मुके प्राणी आणि त्यांचे पक्ष म्हणजे मालक. २) दुसरे कारण फार महत्त्वाचे आहे. आग्रा येथे १८ मार्च १९५६ रोजी धर्मांतराच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भाषणात बाबासाहेबांनी जाहीर केले की, बौद्ध झाल्याबरोबर मला तुमचे नेतृत्व करता येणार नाही आणि मला फेडरेशनमध्येही राहता येणार नाही. बौद्ध झाल्यावर राजकारण सोडणार नाही, मात्र शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या तिकिटावर उमेदवार म्हणून मी निवडणूक लढविणार नाही. मी स्वतःच्या हिमतीवर निवडणूक लढवेन. मग माझा विजय होवो अथवा पराभव होवो, त्याची मला किंचितही पर्वा नाही. 'प्रबुद्ध भारत'च्या २४ मार्च १९५६ च्या अंकात त्याचा 'भाकरीपेक्षा स्वाभिमानाला अधिक महत्त्व आहे', या मथळ्याखाली वृत्तांत प्रसिद्ध करण्यात आला. बाबासाहेबांचे विचार इतके सुस्पष्ट असताना जनगणनेत काय लिहावे असा प्रश्न पडण्याचे कारण नाही. जात कोणतीही घ्या, त्यात लाचारी, गुलामी आणि तिरस्कारच असतो. बौद्ध असण्यात स्वाभिमान, समता आणि बंधुता असते. ज्यांना बाबासाहेबांच्या शब्दांत भाकरीपेक्षा स्वाभिमान महत्त्वाचा वाटतो, त्यांनी जनगणनेत आपली नोंद फक्त आणि फक्त बौद्ध म्हणून नोंद करावी. ज्यांना स्वाभिमान नाही, त्यांना जात महात्म्याचे पारायण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

अन्वयार्थ

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काय होणार?

अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. अजितदादांच्या पश्चात अवघ्या चारच महिन्यांत पक्षात निर्माण झालेला संघर्ष लक्षात घेता राष्ट्रवादीची भविष्यातील वाटचाल खडतर असल्याचीच एकूण लक्षणे दिसू लागली आहेत. पक्षाच्या वतीने २९ एप्रिलला निवडणूक आयोगाला सादर केलेले पत्र आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्याने आता नव्याने वादाला तोंड फुटले आहे. अजित पवार यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची निवड करण्यात आली. या निवडीनंतर २६ फेब्रुवारीला पक्षाच्या वतीने निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलेल्या पत्रात राष्ट्रीय कार्यकारिणीवरील सदस्यांची यादी सादर करण्यात आली. त्यात प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, दिलीप वळसे-पाटील आदी जुन्याजाणत्या नेत्यांचा समावेश होता. अर्थात, या पत्रात अध्यक्ष सुनेत्रा पवार व खजिनदार शिवाजी गर्जे अशा दोघांचाच उल्लेख होता. प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष असले तरी त्यांच्या पदाचा उल्लेख का नाही, असा प्रश्न तेव्हाही उपस्थित झाला होता. गेल्या काही दिवसांत पक्षातील निर्णय प्रक्रियेवरून प्रफुल्ल पटेल आणि खासदार पार्थ पवार यांच्यात शीतयुद्ध सुरूच आहे. अशातच पक्षाच्या वतीने निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलेले पत्र प्रसिद्ध झाल्याने वाद आणखी विकोपास जाण्याची चिन्हे आहेत. कारण राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील या नेत्यांची नावे गायब झाली आहेत. २६ फेब्रुवारीला सादर करण्यात आलेल्या यादीत या सर्व नेत्यांची नावे होती. मग २९ एप्रिलच्या पत्रात ही नावे नसल्याने प्रफुल्ल पटेल, भुजबळ, तटकरे आदींना पक्षाच्या कार्यकारिणीतून डच्चू दिल्याचा अर्थ काढला जाऊ लागला. 'पक्षाच्या कार्यकारिणीतील नावांबाबत प्रशासकीय चूक झाली असून, ती लवकरच दुरुस्त केली जाईल' अशी सारवासारव उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांनी केली असली तरी यातून पक्षात सारे काही आलबेल नाही हा संदेश बाहेर गेलाच. सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार पार्थ पवार सरचिटणीस, तर दुसरे पुत्र जय पवार सचिव अशी पदाधिकाऱ्यांची यादी बघितल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे अजित पवारांच्या कुटुंबीयांची खासगी कंपनी झाल्याचेच शिक्कामोर्तब झाले.

अजित पवारांच्या मृत्यूनंतरचा घटनाक्रम व सुनेत्रा पवार यांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीसाठी करण्यात आलेली घाई हे लक्षात घेता पक्षाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे या द्वयीने भाजपच्या मदतीने प्रयत्न केले होते हे लपून राहिलेले नाही. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीबरोबर विलीनीकरणाची चर्चा सुरू झाल्यावर पटेल व तटकरे यांनी त्याविरोधात भूमिका घेतली होती. 'विलीनीकरण कोणाचे व कोणाबरोबर', असा प्रश्न तटकरे यांनी उपस्थित केला होता. अजित पवारांच्या पश्चात सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पक्षाची व विधिमंडळ पक्षनेतेपदाची जबाबदारी आली असली तरी पक्षाची संघटनात्मक सूत्रे पार्थ पवार यांच्याकडे गेली. पटेल, तटकरे यांचे प्राबल्य पार्थ पवार यांनी मोडून काढले. यातूनच पक्षात पार्थ पवार विरुद्ध प्रफुल्ल पटेल, अशी दरी निर्माण झाली.

अजित पवारांच्या पश्चात पक्षाचे अस्तित्वच जाणवत नाही. पक्षाचे नेते व कार्यकर्तेही सैरभैर होऊ लागले आहेत. कोणाकडे दाद मागावी हेच समजेनासे झाले आहे. सुनेत्रा पवार किंवा त्यांचे पुत्र पार्थ यांची पक्षावर वा प्रशासनावर तेवढी पकड नाही. सत्तेत असूनही राजकीयदृष्ट्या पक्षाची ताकद कमी होऊ लागली आहे. अर्थ खाते पुन्हा पक्षाला मिळेल याची खात्री नसल्याने निधीवरून आमदारांमध्ये अस्वस्थता वाढू लागली आहे. विलीनीकरणावरूनही पक्षात एकवाक्यता नाही. पक्षाची ताकद खचल्यास नेतृत्वाच्या अभावी पुन्हा राष्ट्रवादीला उभारी मिळणे कठीण. राज्याच्या सत्तेत पक्ष भागीदार असल्याने नेते व कार्यकर्ते अजून टिकून राहतील. पक्षात अशीच परिस्थिती राहिल्यास राष्ट्रवादीत मोठी फूट अटळ मानली जाते. तसेही प्रादेशिक पक्ष गिळंकृत करून आपली ताकद वाढविण्याचे भाजपचे धोरण आहेच. पश्चिम महाराष्ट्र किंवा सहकार चळवळीतील यशाने भाजपलाही राष्ट्रवादीची तेवढी उपयुक्तता राहिलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे काय होणार, असाच प्रश्न आता विचारला जात आहे.

विनेश फोगटच्या भारतीय कुस्ती महासंघाबरोबरच्या नव्या संघर्षाचे कारण काय?

विश्लेषण

ज्ञानेश भुरे
dnyanesh.bhure@expressindia.com

माजी आशियाई व राष्ट्रकुल सुवर्णपदक विजेती कुस्तीगीर विनेश फोगटच्या कुस्तीच्या मॅटवरील पुनरागमनामुळे तिच्यात आणि भारतीय कुस्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआय) यांच्यात नव्याने संघर्ष निर्माण झाला आहे.

संघर्ष नव्याने कसा सुरू झाला?

'डब्ल्यूएफआय'ने मे महिन्यात राष्ट्रीय मानांकन स्पर्धांची घोषणा केली. ऑलिम्पिक पदकाचे अर्धवट स्वप्न, आगामी राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धा डोळ्यासमोर ठेवून विनेशने या स्पर्धेत खेळण्याचा निर्णय घेतला. तब्बल २० महिन्यांनी ती मॅटवर उतरणार होती. मात्र, शेवटच्या दिवशी विनेशने समाजमाध्यमांवरून एकदाची नोंदणी झाली हे जाहीर करताना शेवटी 'डब्ल्यूएफआय'चे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याकडून अत्याचाराचा सामना कराव्या लागलेल्या सहा महिला कुस्तीगिरांपैकी मी एक होते असे वक्तव्य केले. इथे वादाची पहिली ठिणगी पडली.

'डब्ल्यूएफआय'ने अचानक धोरणात बदल केले?

विनेशच्या या वक्तव्यानंतर 'डब्ल्यूएफआय'ने एकेक तांत्रिक मुद्दे पुढे करून तिला राष्ट्रीय स्पर्धेपासून दूर ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. प्रथम त्यांनी या स्पर्धेतील मल्लांचा आशियाई स्पर्धेसाठी विचार करणार नाही असे सांगितले. आशियाई स्पर्धेच्या संघ-निवडीसाठी स्वतंत्र निकष जाहीर केले. त्यानंतर विनेशला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. आंतरराष्ट्रीय नियमावर बोट ठेवत निवृत्ती मागे घेण्याच्या निर्णयानंतर सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी पूर्ण केला नसल्याचे सांगत या स्पर्धेतील सहभागापासूनही रोखले. साहजिकच आता विनेश आशियाई क्रीडा स्पर्धेसह जागतिक आणि राष्ट्रकुल स्पर्धेतही खेळू शकणार नाही.

विनेशवर नेमके आरोप काय?

विनेशने १८ डिसेंबर २५ रोजी उत्तेजक चाचणीसाठी उपलब्ध न राहून नियमांचे उल्लंघन केले. निवृत्तीनंतरच्या पुनरागमनाची माहिती सहा महिने आधी देणे आणि चाचणीसाठी उपलब्ध राहणे अनिवार्य होते, ते पाळले नाही, असे 'डब्ल्यूएफआय'चे म्हणणे. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये विनेशमुळे भारताचे हक्काचे पदक निसटले आणि भारतीय कुस्तीच्या प्रतिमेला तडा गेला, असा आरोप महासंघाने दोन वर्षांनी केला आहे. विशेष म्हणजे तेव्हा विनेशने ५० किलो आणि ५३ किलो अशा दोन वजनी गटांतून निवड चाचणीत भाग घेतला होता. ते नियमांच्या विरुद्ध असल्याचा महासंघाचा आरोप आहे. तेव्हा चाचणीत सहभागी करून घेतले जाईल अशा लेखी आश्वासनासाठी तिने स्पर्धा थांबवून धरल्याने इतर कुस्तीपटूंची गैरसोय झाल्याचा ठपकाही तिच्यावर आहे.

'डब्ल्यूएफआय'कडून जाणूनबुजून अडवणूक?

'डब्ल्यूएफआय' विनेशला जाणुनबुजून रोखत असू शकते, कारण महासंघातील पदाधिकारी बदलले असले, तरी अजूनही माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण यांचा त्यांना छुपा पाठिंबा आहे. विनेशच्या आरोपांमुळे ब्रिजभूषण आणि महासंघाच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. त्यामुळे त्यांनी विविध नियमांचा आधार घेत विनेशच्या पुनरागमनात अडथळे आणण्यास सुरुवात केली आहे. विनेश मानांकन स्पर्धेत खेळणार हे महासंघाला कळलेच होते. मग, त्यांनी केवळ दोन दिवस आधी निलंबनाची कारवाई कशी केली?

विनेशची भूमिका काय?

'मी तेव्हाही लढत होते आणि आताही लढत राहणार' अशीच भूमिका घेणाऱ्या विनेशने महासंघाच्या कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तरदेखील दिले आहे. संयुक्त जागतिक कुस्ती महासंघ, जागतिक उत्तेजक प्रतिबंध संस्था (वाडा) यांच्या नियमाचे मी पालन केले आहे. सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा काळ लक्षात घेऊन मी जून २०२५ मध्येच या संघटनांना पुनरागमनाचे कळवले असल्याचे विनेशने त्यांच्या पत्रासह दाखवून दिले आहे. मी निवृत्त व्हावे अशीच महासंघाची इच्छा आहे. पण, मी शेवटपर्यंत लढत राहणार...कुणी सांगतो म्हणून निवृत्त होणार नाही, असे ती म्हणते.

विनेशच्या निवृत्ती प्रकरणात नेमका पेच काय?

विनेशने सुरुवातीला आपण तात्पुरता ब्रेक (सॅबॅटिकल) घेणार असे म्हटले होते. अशा वेळी खेळाडू तांत्रिकदृष्ट्या सक्रिय मानला जातो आणि त्याला सर्व नियम लागू असतात. विनेशने या सर्व नियमांपासून पळ काढला. आपल्या ठावठिकाणाबाबत माहिती देणे बंद केले. त्यामुळे तिने निवृत्ती घेतली असे मानले गेले. निवृत्त खेळाडूस नियम लागू होत नाहीत. एखाद्या खेळाडूस निवृत्ती मागे घ्यायची असेल, तर त्याला सहभागी होण्याच्या स्पर्धेपूर्वी सहा महिने आधी शिखर संघटना, 'वाडा' आणि राष्ट्रीय महासंघास त्याची कल्पना द्यावी लागते. प्रत्येक खेळाडूला पुनरागमनापूर्वी हा सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी पूर्ण करावा लागतो. विनेशच्या बाबतीत हा पेच निर्माण झाला आहे.